हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही.

27 फरवरी, 1986

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण.

विषय–सूची

वीरवार, 27 फरवरी, 1986

पृष्ठ सख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 1
नियम 45 के अधीन सदन के मेज पर रखे	
तारांकित प्रश्न का लिखित उतर	(9) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9) 21

ध्यानाकषण प्रस्ताव–	
फरीदाबाद (एन० आई० टी ०) मै –पिट/बोंर शौचालयों कं मल से भूमिगत जान के दूषित होने तथा खारा होने आदि सम्बन्धी	(9) 26
वक्तव्य–	
स्थानीय शासन राज्य मंत्री दारा उपरोक्त	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सबंधी –	(9) 26
वर्ष 1986–87 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(9) 28
बैठक का समय बढ़ाना	(9) 77
वर्ष 1986– 87 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(9) 78

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 27 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई ।

अध्यक्ष ने अध्यक्षता की । (सरदार तारा सिंह)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब क्वैशचन्ज होंगे । श्री राम बिलास शर्मा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1060

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम बिलास शर्मा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Shifting of Ambala Cantt. Bus Stand

***1095. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister for Trans.. port be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Ambala Cantt. Bus Stand from its existing site to another site; if so, the time by which the bus stand is likely to be shifted to the new site ?

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) :

Yes, Sir. The bus stand is likely to be shifted during the next financial year.

सेठ राम दास धमीजा : स्पीकर साहब, पिछले साल भी मेरे क्वैश्चन का जवान 'यैस, सर' में ही मिला था लेकिन अभी तक बस स्टैंड वहीं है । क्या मिनिस्टर साहव इसके बारे में कोई डैफिनिंट डेट बताएंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, जब जवाब 'नो, सर' में होता है सब भी धमीजा साहब औबजैक्ट करते हैं और जब जवाब यैस, सर' होता है तब भी औबजैक्ट करते हैं । स्पीकर साहब, अम्बाला कैन्टोनमैंट का बस स्टैंड जब पंजाब और हरियाणा अलग–अलग हुए थे, तब हमें मिला था । वह बहुत छोटी जगह है । जी० टी० रोड पर भी बसें स्पिल ओवर होकर खड़ी रहती हैं और एक्सीडैट्स होने का काफी डेंजर रहता है । इन बातों को मद्देनजर रखते हुए बस स्टैंड के इमीजिएटली बिहाइन्ड जो एक डिग्गी है और म्यूनिसिपैलेटी की जमीन है, उसे म्यूनिसिपैलेटी के साथ नैगोसिएशन करके 99 साल के पट्टे पर ले लिया गया है । उसका 100 रुपया साल का किराया दिया जाएगा और जो ऐग्जिस्टिंग बस–स्टैंड की जगह है उसे बस स्टैंड–शिफ्ट होने के बाद म्यूनिसिपैलेटी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा । स्पीकर साहब, उस जगह के साथ गवर्नमैंट लैंड भी है । यह सारी जगह बस–स्टैड केलिए काफी होगी । इस डिग्गी में पानी भरा रहता है । हमने 10 लाख रुपया अर्थ फिलिंग के लिए रिलीज कर दिया है लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है । पैसा पी०डब्ल्यू० डी० के पास जमा करवा दिया है । उन्होंने टैन्डर इन्वाइट कर लिए हैं ।

मुमकिन है हफ्ते दस दिन के अन्दर फिलिंग का काम शुरू हो जाएगा । फिलिंग का काम कम्पलीट होते ही बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा और मुझे उम्महद है कि मार्च 1987 से पहले यह काम कम्पलीट हो जाएगा ।

सेठ राम दास धमीजा : धन्यवाद जी ।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, हिसार से चण्डीगढ आने के लिए अम्बाला–कालका रेलवे लाईन के ऊपर पुल नहीं है । इससे बड़ी दिक्कत होती है । क्या सरकार उस पुल को बनाने की कृपा करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी नेकी राम जी अगर कहीं बस चलाने के लिए कहेंगे वह तो मैं चला दूंगा लेकिन पुल मेरे भाई अमर सिंह जी बनवाएंगे ।

श्री नेकी राम : आप ही उनसे कहें क्योंकि दिक्कत तो आपकी बसों को होती है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, जिस तरह से अम्बाला बस स्टैड ज्वायंट पंजाब के समय बना था उसी तरह से रोहतक बस स्टैंड भी ज्वायंट पंजाब के समय 'बना था । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या रोहतक बस स्टैंड को भी शिफ्ट करने की प्रपोजल है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यह सवाल रोहतक का नहीं है लेकिन जो मुझे जबानी याद है वह मैं हाउस के सामने अर्ज कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने थोड़ा लिबरल होकर यह सवाल अलाउ कर दिया है।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, रोहतक और करनाल के बस स्टैंडज शहर के बीच में आ गए हैं । रोहतक और करनाल बस स्टैडंज को बाहर शिफ्ट किया जाए उसके लिए लेड साईटिंग बोर्ड तलाश कर रहा है । शायद कहीं छांट भी ली है लेकिन अभी तक कागज मेरे पास नहीं आए हैं । कहने का मतलब यह है कि रोहतक और करनाल दोनों बस स्टैंडज के लिए जमीन की सिलैक्शन कर ली गई है और उन्हें बाहर शिफ्ट करने की योजना अन्डर कंसिडेरशन है ।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, बराडा बस स्टैंड की प्रपोजल बहुत देर से पैंडिंग हे । वहां सैक्शन्ज 4– 5 की प्रोसीडिंग्ज हो चुकी थी और सैक्शन 6 की कार्यवाही को हुए भी एक साल गुजर गया है । मैं मैली जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस वर्ष में सारी फार्मेलिटीज पूरी करके उस बस स्टैंड को बनवा देंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, सैक्शन 4 की कार्यबाही होने के बाद जव बीच में एक साल गुजर जाता है तो

सैक्शन 4 और 8 की ऐफैश कार्यवाही करनी पड़ती है । सुस्ती कहां हो गई यह मुझे मालूम नहीं । सैक्शंज 4 और 6 की कार्यवाही होने के बाद औटोमैटिंकली सैक्शंज 7, 8 और 9 लग जाने चाहिएं थे । अब तो ऐफ्रैश सैक्शन 4 और 6 लगाना पड़ेगा । मैं अपने दोस्त मुलाना साहब से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि ये भी इस बात का ध्यान रखें ताकि वह फिर से लैप्स न हो जाए ।

Removal of Electricity Meters of Tubewells

***1127 Master Shiv Parshad@ :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state : —

(a) whether the Government is aware of the fact that electric meters of Tubewells are removed by the employees of the Haryana Electricity Board in case of non-payment of bills by the farmers;

(b) whether it is also a fact that such meters are not reinstalled promptly even after the payment of all dues/charges; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative the action taken against such erring officials ?

Irrigation & Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) :

(a) & (b) In case of non-payment of bill by the tubeweil consumer on due date the power is disconnected temporarily. If payment is not received within 90 days of temporary disconnecticn, the same is permanently

disconnected and the meter and other installations are removed. After the consumer pays the outstanding amount, he may get a connection on fresh priority.

(c) Does not arise.

श्री भले राम : स्पीकर साहब, टयूब्वैल्ज के कुनैक्शन्ज को तो नौन पेमैंट की वजह से काट देते हैं लेकिन इंडस्ट्रीज का कई कई सालों का एरीयर पड़ा हुआ है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसका क्या कारण है? फिर स्पीकर साहब ऐसा है कि जब उसका कुनैक्शन कट जाता हैं तो प्री पेमैंट करने के बाद उसे दुबारा कुनैक्शन के लिए एप्लाई करना पड़ता है जिससे उसे कुनैक्शन मिलने में बहुत देर लगती है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि पेमैंन्ट होने के बाद उसे पुराना कुनैक्शन ही क्यों नहीं दे दिया जाता?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है कि नौनपेमैंट की वजह से इंडस्ट्रीज के कुनैक्शन नहीं काटे जाते और ट्यूबवैल्ज के कुनैक्शन काटे जाते हैं । बल्कि फैक्ट यह है कि टयूबवैल्ज वालों को पेमैंट करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है और इंडस्ट्रीज वालों को 30 दिन का समय दिया जाता है । इंडस्ट्रीज की तरफ केवल उन केसिज में पैसे डयू हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से स्टे हैं या लोग आर्बिटेरशन में गए हैं । ट्यूबवैल्ज के केसिज में तो हम बहुत ज्यादा लिबरल हैं । जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि बाकी

के कंज्यूमर्ज को तो हम पेमैंट करने के लिए 30 दिन का समय देते हैं लेकिन ट्यूबवैल्ज वालों को 90 दिन का समय देते हैं । फिर अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि कुनैक्शन कटने के बाद नया कुनैक्शन मिलने में टाईम लगता है । यह तो लगेगा ही क्योंकि सरकार उनको बहुत टाईम देती रही है । बार बार यह कहा गया है कि अगर फलां तारीख तक पेमैंट दे देंगे तो पुरानी प्रायरिटी पर ही कुनैक्शन दे दिया जाएगा । 1983 में इस तरह का कंसैशन दिया गया । 1984 में दिया गया । टाईम बढ़ाते बढ़ाते इस कंसैशन को 30– 9– 1985 तक ऐक्सटेंड कर दिया गया और यह अनांउसमैंट कर दी गई कि अगर ट्यूबवैल्ज वाले इस तारीख तक पे मैट कर देगे तो उन्हें दुबारा कुनैक्शन्ज दे देंगे । इसलिए मे तो यह कहूंगा कि ट्यूबवैल्ज के केसिज में सरकार बहुत लिबरल है और दू सरे केसिज में इतनी लिबरल नहीं हें ।

चौधरी हनुमान सिंह : स्पीकर साहब, जब एक टयूबवैल लगाते हें तो उसके लिए नए कुनैक्शन के लिए ऐप्लाई करना पड़ता हैं लेकिन साथ ही 20 फुट की दूरी पर अगर एक और टयूबवैल लगाया जाता है तो उसके लिए भी उतना ही खर्चा माँगते हैं जबकि वायरिंग वही काम आ जाती है और बोर्ड भी वही काम आ जाता है । क्या मिनिस्टर साहब इस बात को ठीक करने की कृपा करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, बहुत डिटेल में तो मैं इस बात को इस वक्त नहीं बता सकता ।

श्री अध्यक्ष : इनकी बात बहुत सीधी सी है । एक कैविटी अगर बैठ जाए तो दूसरी कैविटी करनी पड़ती है । इसके लिए कुनैक्शन देने के लिए प्रायरिटी पहली ही रहनी चाहिए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका मुद्दा समझ गया हूं लेकिन इस बारे में जौ रूल्ज हैं और कायदे हैं उनकी पूरी डिटेल मुझे इस वक्त याद नहीं लेकिन जितना मुझे जबानी याद है वह मैं बता देता हूं । जहां पहला टयूबवैल था अगर उसी खेत में दूसरा टयूबवैल लगाना हो तो उसके लिए शायद कायदा लिबरल है लेकिन अगर टयूबवैल उस खेत की बजाए किसी दूसरे खेत में लगाना हो तो उसके लिए शायद फ्रैश कुनैक्शन लेना पड़ता है । बाकी मैं कल पता करके हाउस में बता दूंगा कि ' ऐक्चुयली क्या इन्स्ट्रक्शन्ज हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैं पर्सनली बता सकता हूं कि पिछले साल हमें चार बार बोर करने पड़े । जहां पर बोर करते थे वहीं टयूबवैल बैठ जाता था । तो संपरेट सैपरेट जगह के बोर में पेमैंट करना बड़ा मुश्किल होता है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : ठीक है, जो जजबात आपने जाहिर किए हैं उनकी रोशनी में पता कर लेंगे कि क्या कायदे हैं । कल दें हाउस को बता दूंगा और उसके लिए जो भी रियायतें दी जा सकती हैं उन्हें देने की सरकार पूरी कौशिश करेगी ।

चौधरी दिलू राम बाजीगर : स्पीकर साहब जो कुनैक्शन बिल न देने की वजह से कटते हैं उन कुनैक्शन्ज को दुबारा लेने के लिए सिक्योरिटी भरते हैं । फिर यह फाईल एस० ई० के. लैवल तक जाती है । उस फाईल के आने जाने में कई महीने लग जाते हैं । मेरी गुजारिश है कि अगर कोई आदमी बिल अदा नहीं करता है और उसका कुनैक्शन काट दिया जाता है तो उसे री–इनस्टेट करने की पावर्ज एस०डी०ओ ० को दी जानी चाहिए न कि एस ०ई० और ऐक्सीयन को ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैंने यह बात पहले भी कही थी कि सरकार किसानों के मामले में बहुत लिबरल हे लेकिन जो लोग डिफाल्टर है अगर उन्हे बहुत ज्यादा दी जाएगी तो बाकी के लोग भी टाईम पर बिल नही भरेंगे । यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि डिफाल्टर को इतनी खुली छुट्टी दी जाए । किसानों को हम समय समय पर कनसैशन देते रहे हैं । जैसे सन 1983 में दिया, फिर 1984 में दिया और सन् 1985 में सितम्बर के महीने तक दिया कि अगर कोई पुराना केस है चाहे उसका कुनैक्शन कटे हुए दस साल हो गये हैं, अगर वह अब भी पिछला पैसा डिपौजिट कर देगा तो हम कुनैक्शन देगे ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बात का सवाल है कि एस०डी० ओ० को अख्तियार दिये जाये क्योंकि आजकल ये एस०ई० को हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नही होगा । ज्यादा से ज्यादा ऐक्सीयन के लैवल तक फाईल जाती होगी । अगर एस० ई० तक

फाईल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि ये पावर्ज डी–सैन्ट्रलाइज हों और ऐक्सीयन लैवल तक ये पावर्ज हो जायें ।

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने पहले उत्तर में बताया कि इन्डस्ट्री का ऐसा कोई कुनैक्शन नहीं है जिसने बिल न दिया हो और उसे डिसकुनेक्ट न किया हो । क्या उनके नोटिस में यह बात है कि अगर ट्यूबवैल का दो सौ रुपये का बिल टाईम पर पे न हुआ हो तो कुनैक्शन डिस–कुनेक्ट कर देते हैं और इन्डस्ट्री का डेढ़–डेढ़ लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है और उनको डिस–कुनैक्ट नहीं किया जाता है? एक बात मैं और जानना चाहता हूं । कई जगह ट्यूबवैल्ज के जहां हमने कुनैक्शन दे रखे हैं, वहां पर बिजली नहीं पहुंचती है । जैसे हमारे यहां बाल्टी फीडर है । उसकी 150 किलोमीटर लम्बी लाईन है और वह सिंगल फेस पर चलती है । क्या उन ट्मूववैल्ज के कुनैक्शंज डिस–कुनैक्ट कर देगे क्योंकि वे ट्यूववैल्ज चलते ही नहीं है?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि यह मेरे ध्यान में कैसे हो सकता है कि किन लोगों ने बिल नहीं जमा कराये । इस बात का तो वही ध्यान दिलायेंगे कि कौन ऐसे आदमी हैं जिन्होंने डेढ़ लाख रुपये का बिल जमा नही कराया और बिजली बोर्ड ने या सरकार ने उनके कुनैक्शन नहीं काटे । अगर उसने बिल नहीं जमा कराया है तो जरूर कुनैक्शन काटे जायेंगे । इस बात का वे खुद ध्यान दिलवायेंगे । अगर किसी अफसर ने यह बात छिपा रखी है उसके

खिलाफ भी कार्यवाही करेगें । जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई लम्बी लाईन है उसका बोर्ड कुनैक्शन काट दे, सरकार तो कुनैक्शन देने का प्रयत्न करती हैं, कटवाने का प्रबन्ध तो वे खुद करवायें । बोर्ड कुनैक्शन नहीं कटवाता, चाहे कोई छोटी लाईन है या लम्बी लाईन है ।

श्री निर्मल सिंह : मन्त्री महोदय ने यह बात मानी है कि जहां पर किसी की कैविटी बैठ जाती है वहां यदि बिजली वाले किसी दूसरी जगह कुनैक्शन देगें तो उसे नया कुनैक्शन मानते हैं । आगे मन्त्री जी ने फरमाया कि अगर खेत दूर हो तो कुनैक्शन नहीं देते हैं और अगर कुनैक्शन उसी खेत में लेना हौ तो दे देते हैं । स्पीकर साहब बिजली वाले पोल के भी पैसे ले रहे हैं । मैं तो यह कहूंगा कि कुनैक्शन किसी भी कीमत पर नहीं कटना चाहिए । अगर कोई आदमी समय पर बिल नहीं भरता है लेकिन उसके बाद दूसरे ही दिन बिल भर देता है तो उसे कुनैक्शन दिया जाना चाहिए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सर, जो इन्होंने पहली बात कही कि कुनैक्शन अगर दूर हो तो नहीं देते हैं । इसके बारे में अर्ज यह है कि मैंने यह कहा था कि जिस प्लाट में, ब्लाक में या चौक में वह कुनैक्शन पहले था उसमें शायद कुनैक्शन दे' देते हैं । मैंने यह भी कहा था कि जबानी मुझे याद नहीं है । फिर मैंने यह कहा था कि अगर किसी दूसरे ब्लाक में है, तो शायद कुनैक्शन न देते हों । मैंने यह भी कहा था कि पता

करेंगे और इस बारे में किसानों की मद्द करने की पूरी कोशिश करेंगे । जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है हमें लिबरल होना चाहिए और जिस दिन वह बिल भर दे उसी दिन फिर कुनैक्शन दे दें, यह तो तमाशा ही रहेगा । ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता । तीन महीने के अन्दर यदि कोई बिल नहीं भरता है तो उसका परमानेन्ट तौर पर कु नैक्शन काट दिया जाता है और उसकी लाईन उतार कर किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, है आपके द्वारा सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन्डस्ट्री वालों की तरफ तो करोड़ों रुपया बकाया हे और जमींदार की तरफ कोई पैसा बकाया नहीं है । मकहमे वाले जमींदार के ऊपर कड़ी निगाह रखे हुए हैं । स्वीकर साहब, सरकार यह चाहती है कि पैदावार बडे । ट्यूबवैल्ज का कुनैक्शन काटने का मतलब है पैदावार को नीचे लाना । जमींदार की और कोई आमदनी नहीं होती है, वह तो खेती से कमा कर पैसा देता है । अगर वह टाईम पर पेमैंट नहीं दे सकता तो फसल आने पर दे देगा । उसे मौका देना चाहिए वह देश की पैदावार को बढ़ाता है । इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए । दूसरे मै यह भी कहूंगा कि जमींदार के जिम्मे तौ पैसा ही नहीं है फिर आप उसे एक दिन की भी ढील नहीं दे रहे हो । अगर समय पर पैसे जमा नहीं करता हे तो कुनैक्शन काट देते हो । यह उसके साथ ज्यादती है । मेरा सुझाव यह है कि उसे मौका देना चाहिए । अगर वह अपनी फसल बेच कर पैसा दे

दे तो उसका कुनैक्शन नहीं कटना चाहिए । आप कहते हैं कि कुनैक्शन कटने के बाद 90 दिन के अन्दर अपील कर सकता है । 90 दिन की उसे आप पहले ही छूट दे दें ताकि वह तकलीफ का शिकार न हो ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : सरकार किसी भी सैक्शन के खिलाफ नहीं है । जो रियायतें सरकार ने ऐग्रीक्लचर सैक्टर में दे रखी है वे किसी भी सैक्टर में नहीं दे रखी हैं । क्योंकि कांग्रेस सरकार की डिकलेयर्ड पालिसी है कि ऐग्रीकल्चरिस्ट को प्रायरिटी देगें, चाहे बिजली की बात हो चाहे कोई और बात हो । मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हू कि इलैक्ट्रिसिटी इन्डस्ट्री के लिए मंहगी दी जाती है और किसानों को सस्ती दी जाती है । स्टील फर्नेसिज के लिए 95 पैसे पर–यूनिट, लार्ज इन्डस्ट्री के लिए 85 पैसे पर यूनिट, स्माल इन्डस्ट्री के लिए 60 या 70 पैसे पर यूनिट बिजली दी जाती है जबकि ऐग्रीक्लचर के लिए 15 पैंसे से लेकर 35 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है । एक यूनिट पर बिजली बोर्ड चालीस पैसे या तीस पैसे सबसेडाइज्ड कर रहा है जिससे साल में सरकार करोड़ों रुपये का घाटा उठा कर किसानों को बिजली दे रही है ।

श्री अमीर चन्द मक्कड : स्पीकर साहब में मती महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन्डस्ट्रीयलिस्टस की तरफ कितना पैसा बिजली बोर्ड का बकाया है और किसानों की तरफ कितना बकाया

है? कृपया ये आंकड़े दे दें तो सही पोजीशन का पता चल जायेगा कि किस की तरफ ज्यादा पैसा बकाया है ।

श्री अध्यक्ष : यह क्वैश्चन मेन क्वैश्चन को रिलेट नहीं करता ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि जो कुनैक्शन्ज डिस–कुनैक्ट होते हैं क्या उनमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का भी हाथ है? वे किसान को बिजली के बिल बिल्कुल गल्त देते हैं । उनको ठीक कराने के लिए वह कई–कई महीने चक्कर काटता रहता है लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता है । इस तरह से उसकी आदत हो जाती है । यह अक्सर होता है । जमींदार का जो अमाउन्ट बढ्ता रहता है उसके लिए डिस्ट्रीव्यूटर जिम्मेदार होता है । वह जमींदारों के बिल समय पर नहीं लाता है या जो मीटर रीडर्ज होते हैं वे कई कई महीने तक यूनिट दर्ज करने के लिपू नहीं जाते हैं, वहीं बैठे हुए दर्ज करते रहते हैं । इन हालात में पेमैंट मेंरू देर हं। जाती है । मैं समझता हूं कि अगर सही बिल मिलने लगें तो यह डिस–कुनैक्शन कम हों और अमाउन्ट भी डिफाल्ट में न जाये । क्या सरकार इन बातों का प्रबन्ध करेगी?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जो डिसप्युटिड बिल हैं उनके कुनैक्शन्ज डिस–कुनैक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । उसके लिए वे डिसप्यूट रेज कर

सकते हैं, अफसरों के पास जा सकते हैं । जो करन्ट बिल हैं और डिसप्यिटड नहीं है उसे वह दाखिल करता रहे तो उसका कुनैक्शन नहीं काटा जाता है । उन केसिज में कुनैक्शन काटा जाता है जो जान–बूझ कर नहीं देते हैं । जहां तक इस बात का सवाल है कि जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर्ज हैं या मीटर रीडर हैं वे ठीक तरह से काम नट्टी करते, रीडिंग ठीक नहीं करते हैं और समय पर बिल नहीं देते हैं, उसके लिए मैं यह कहूंगा कि यह ऐसा वाइड सप्रैड काम है जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है । मैं यह नहीं कहता कि सारे ही कर्मचारी ठीक काम करते हैं । इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि वे इस बारे में ऐसे बिजली बोर्ड के या सरकारी कर्मचारियों की मदद न करें जो ऐसा करते हैं और खास तौर से चौधरी अजमत खां से कहूंगा कि वे इस तरह की बातें हमारे नोटिस में लायें और ऐसे कर्मचारियों की मदद न करें जो लोगों की सेवा करने में कोताही करते हैं, जो अपनी कारगुजारी भी ठीक नहीं करते । स्पीकर साहब, अगर कोई उनकी मदद न करे, तो बिजली बोर्ड और सरकार यह बात ऐनशयोर कर सकती है कि लोगों को तकलीफ न हो ।

Labour Colonies in Industrial Towns

***1133 Ski A. C. Chaudhry :** Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state—

(a) whether it is a fact that labour colonies have been construted in different industrial towns of the State;

(b) If so, whether all the houses in such colonies have since been allotted; if not the reasons thereof; and

(c) whether there is any proposal under consideration to construct residential colony for the employees working in the industrial town of Faridabad; if so, the time by which the said colony is likely to be constructed ?

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओमप्रकाश महाजन) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहिब, मुझे भी आज धमीजा साहब की तरह से कहना पड़ेगा कि 'जी नहीं' कहने से बात नहीं बनेगी । स्पीकर साहब, वैसे तो यह क्वैश्चन कल डिटेल में डिस्कस हो चुका है लेकिन आज सवाल के जवाब में कुछ डिस्पै– रिटि है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान और इस सदन का ध्यान दिलानी चाहता हूं । महाजन साहब ने मेरे सवाल के पार्ट ''सी'' के जवाब में यह कहा है कि 'जी नहीं' । कल मुख्य मती जी ने यह कैटेगरीकली कहा था कि फरीदाबाद के लिये लेबर कालोनीज का मामला बिल्कुल विचाराधीन है । वहां पर आलरैडी लोकल बौडी ने कुछ मकान बनाये हुये हैं और कुछ नये मकान बनाने के लिये उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि अगर वर्कर्ज भी कोआप्रेटिव बेसिज पर कोई हाउसिंग सोसाइटी आदि

बना कर प्लाट्स के लिये कहेंगे तो सरकार उनकी मदद जरूर करेगी । फिर भी मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ प्लाट्स स्ट्रैटिजिक प्वायंट्स पर पड़े हुए हैं, क्या वे प्लाटस इंडस्ट्रियल वर्कर्ज को या स्लम डवैर्ल्ज को कालोनी बनाने के लिये दिये जायेंगे? इससे आपके स्लम्ज भी क्लीयर हो जायेंगे और फैक्ट्री वर्कर्ज को भी रहने के लिये जगह मिल जायेगी । '

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी ड्ह बात का उत्तर दिया था कि यह स्कीम भारत सरकार ने जब 1952 में बनायी तो उस समय हरियाणा में केवल 8 नगरों में इसके लिए प्रोवीजन था और इसमें 986 मकान बनाये गये । फरीदाबाद उसमें तब शामिल नहीं था । सरकार की तरफ से एक निर्णय लिया गया कि यह जो 986 मकान हैं और वर्कर्ज को किराये पर दिये हुए हैं उनको किरायेदार की बजाये मुस्तकिल ही मालिके बना दिया जाये । इसके लिये हम ने उनकी कीमत असैस करवा ली है । यह काम लगभग हो गया है । इस कीमत को लेकर जो लगभग अढाई करोड़ के करीब आयेगी, हम फरीदाबाद काम्पलैक्स के अन्दर फर्स्ट प्रायरिटी देकर मकान जरूर बनवा देगे ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी ने कोआप्रेटिव वर्कर्ज की हाउस बिल्डिंग सोसायटी की बात कही थी । फरीदाबाद, जो बहुत जल्दी इंडस्टेर– लाईज हुआ है,

अगर इसके वर्कर्ज कोई सोसाइटी बनाकर हमें कहेंगे तो हम उनको प्लाट्स देंगे, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में जमीन बिल्कुल खत्म हो रही है । यही नहीं, लोगों ने पलवल और उधर सोहना रोड तक जमीन खरीदनी शुरू कर दी है । क्या सरकार इस काम के लिये कुछ ऐरिया रिजर्व करने की कोशिश करेगी ताकि वहां पर वर्कर्ज के लिये कोई हाउसिंग स्कीम बनाकर उस स्कीम को वहां पर लागू किया जा सके?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने चौधरी साहब के सवाल का जवाब दिया था कि अगर कोई वहां पर सोसाइटी बनाकर कालोनी बनाना चाहे तो सरकार उसको जमीन देने की कोशिश करेगी चाहे उसके लिये सरकार को जमीन ऐक्वायर करके देनी पड़े । लोगों से नैगोशियेशन्ज करके, लोगों से बातचीत करके भी, ऐसी सोसाइटी को जमीन दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वहां पर इन गरीब लोगों के मकान बन सकें ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार को तो यह पता ही है कि स्कीम तैयार करके उसको एप्रूव होने के लिए टाईम चाहिये । इस दौरान फरीदाबाद में जगह ही नहीं रहेगी । दिल्ली वालों ने भी जितनी हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं, वह क्योंकि लोगों के प्लेस आफ वर्किंग से बहुत दूर हैं । इसलिये अलाटीज ने वह मकान बेच दिये हैं और फिर वहीं पर बैठ गये हैं । मेरा कहना यह है कि आजकल जबकि इंडस्ट्रीज के आस–पास जमीन

अवेलेबल है, सरकार उसकने मार्क करके रिजर्व कर ले ताकि वहू जमीन बाद में ऐसी सोसाइटी को दी जा सके । क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है या यह अब कोशिश करेगी ताकि वह जमीन इस काम के लिए रिजर्व रखी जा सके?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप तो काबिल लैजिस्लेटर हैं । आपको पता होगा कि लेटेस्ट लैड राक्वीजीशन–ला के मुताबिक सरकार किसी जमीनदार को इंडैफिनिट पीरियड के लिए अपनी जमीन न बेचने के लिए पाबन्द नहीं कर सकती ।

Casuality Ward in Civil Hospital, Safidon

***1103 Chaudhri Kundan Lal :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of Government to open casuality ward (Emergency Ward) in Civil Hospital, Safidon; if so, the time by which it is likely to be opened;

(b) whether X-ray plant of Civil Hospital, Safidon is functioning properly, if not, the steps being taken to set it right; and

(c) whether the facility of post-mortem was ever available in Safidon; if so, the reasons for which the said facility has now been withdrawn togetherwith the time by which the said facility is likely to be provided there again ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा राज्य मन्त्री (श्रीमती करतार देवी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । सिविल अस्पताल, सफीदों, में एक्स–रे प्लांट लगाया जा चुका है तथा भली भांति कार्य कर रहा है ।

(ग) नहीं जी, प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौधरी कुन्दन लाल : स्पीकर साहब, स्टेट हाईवे पर सफीदों का हास्पिटल मौजूद है और इधर 35 किलोमीटर पर जींद है और उधर 34–35 किलोमीटर दूर पानीपत है । इसके दरम्यान कहीं पर भी ऐमरजैंसी वार्ड की फैसिलिटीज अस्पताल में मौजूद नहीं है । अभी कोई 5– 6 महीने पहले वहां पर एक ऐक्सीडैट सफीदों के साथ ही हुआ था और उसमें तीन मौतें हुई थी । जब तक वहां पर डाक्टरों की टीम पहुंची तब तक मरीज अपने प्राण दे चुके थे दूसरा मेरा कहना यह हे कि पहले जींद स्टेट में पोस्ट मार्टम वहीं हुआ करता था । पैप्सू के समय यह वहां पर ही हुआ करता था लेकिन अब वहां पर यह फैसिलिटी मौजूद नहीं हैं । मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि चूंकि इस पोस्ट–मार्टम की वजह से दो–दो दिन तक लाशें पड़ी सडती रहती हैं, इसलिये वहां पर पोस्टमार्टम की सुविधा जरूर होनी चाहिए ।

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि आस–पास कोई ऐमरजैंसी

सर्विस नहीं हैं, मैं यह बताना चाहती हूं कि इस समय सफीदों हास्पिटल केवल 25 बैडज का अस्पताल है और वहां पर केवल 2 डाक्टर्ज की पोस्ट्स सैंक्शन्ड हैं फिर भी हम इस बात के लिए विचार कर रहे हैं कि वहां पर पोस्ट–मार्टम की सुविधा दी जाये । अगर हम इसे अभी कर देगें तो वहां पर जो डाक्टर्ज पोस्ट–मार्टम करेंगे उनको शहादत के लिये भी जाना पड़ेगा तो पीछे से सारा काम सकर किया करेगा । सफीदों थाने के 1980 से लेकर 1985 तक केवल 160 पोस्ट–मार्टम जींद में हुए हैं । यहां पर 15, 16, 18 तथा 19 ऐक्सीडैंट्स हर साल होते रहते हैं । अगले वर्ष सफीदों में हम कम्युनिटी हैल्थ सेंटर बनाने जा रहे है । जब वहां पर ज्यादा डाक्टर्ज हो जाएंगे तो हैम वहां पर पोस्ट–मार्टम की सुविधा प्रदान करने के लिए बिचार कर सकते हैं ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय?, बात ऐसे है कि कुन्दन लाल जी की बात में बहुत वजन है । उन्होंने ठीक बात कही हें और सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि हर सब–डिवीजनल हेडक्वार्टर पर यह सुविधा होनी चाहिए । क्योंकि सफीदों के किसी आदमी का अगर ऐक्सीडैंट हो जाए और उसका पोस्ट–मार्टम जींद में करवाया जाए, ऐसा करने में काफी परेशानी होती हे । हम कोशिश करेंगे कि अगले साल में अगर नहीं हो सका तो उस से अगले साल यानी दो सालों में हर सब–डिवीजनल हैडक्वार्टजबर पोस्ट–मार्टम का इन्तजाम हो जाये । मैं इस बात के लिए सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ज्यादा नहीं

तो आधे सब–डिवीजन्ज में अगले एक साल में यह काम कम्पलीट कर दिया जायेगा ।

चौधरी कुन्दन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि करीब एक साल पहले जब मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे तो इन्होंने 30 बैडज का अस्पताल मंजूर किया था । यह वायदा वो पब्लिक को देकर आये थे । मुझे उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री जी के पास समय होगा तब इस 30 बैड के अस्पताल का उद्घाटन होगा और यह अस्पताल चालू होगा । मैं मंत्री महोदया से यह भी निवेदन करूंगा कि इसके साथ ही वहां पर पोस्ट–मार्टम की फैसिलिटी देने की जल्दी कोशिश करें ।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसका जवाब दे चुकी हूं । 30 बैडज का तो वहां पर अस्पताल हो गया है लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर कम्युनिटी हैल्थ सैंटर भी तैयार हो गया है । इस से वहां पर और भी ज्यादा पौसिलिटी हो गयी है । जैसे कि मुख्य मंत्री जी ने फरमाया है, हम वहां पर उससे भी ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करने जा रहें हैं ।

10.00 बजे

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, रादौर और लाडवा के अन्दर जो ऐक्सरे प्लांट्स है वे पिछले दो साल से चूंकि काम नहीं कर रहे हैं इस कारण लोगों को काफी दिक्कत है । क्या मन्त्री

महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इन ऐक्सरे प्लाँटस को कब तक चालू करवा दिया जाएगा?

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, मेरे पास जो इस समय रिपोर्ट है उसमें तो बताया गया है कि लाडवा और रादौर में जो ऐक्सरे प्लांट्स हैं वे ठीक काम कर रहे हैं । सीकर साहब, ऐक्सरे प्लांट्स ठीक करने का यह प्रोसीजर है कि कन्सर्ड मैडीकल औफीसर टैलीग्राफीकली सूचना देता है कि फलां ऐक्सरे प्लाँट खराब है । स्पीकर साहब, ऐक्सरे प्लांट को ठीक कराने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है । जिस कम्पनी से हम ऐक्सरे प्लाँट खरीदते हैं उन की यह कन्डीशन होती है कि उसको वही ठीक करेंगे । जैसे ही हमारेरू पास सूचना आती है हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराते हैं । जो पुराने एक्सरे प्लांट्स हैं वे बाहर की कम्पनियों से खरीदे हुए हैं इसलिए उनको ठीक कराने में देर लग जाती है क्योंकि उनको बाहर से आना पड़ता है । अब हम ने हरियाणा की कम्पनियों से ही खरीदने शुरू कर दिए हैं इससे देर होने कीं कम सम्भावना रहती है ।

Bus Stand at Barwala and Uklana

***1120. Chaudhri hider Singh Nain :** Will the Minister for Transport be phased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Stands at Barwala and Uklana in District Hissar; and

(b) if so, the time by which the construction of the above said Bus Stands is likely to be started/completed

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) Yes, Sir

(b) Construction work of Bus Stands at Barwala and Uklana is likely to be started during the next financial year.

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : स्पीकर साहब, कर्नल साहब ने अपना उत्तर 'हां' में दिया है और इसके साथ ही लिखा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क अगले फाईनैशियल ईयर में शुरू हो जाएगा, इन् दोनों बातों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । स्पीकर साहब, उकलाना और बरवाला दोनों जगहें चण्डीगढ से हिसार जाते हुए सडक पर पड़ती हैं और दोनों बड़े कस्बे हैं । यहां पर काफी बसें आती हें । मैं प्रार्थना करता हूं कि उकलाना को छः वेज का बस स्टैंड और बरवाला को तीन बेज का बस स्टैण्ड बनाया जाए ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नही कि दोनों जगह बक्त इम्पौटैंट हैं । नैन साहब ने यह बिल्कूल ठीक बात कही है । इस वक्त योजना यह – है कि बरवाला में तकरीबन साढे चार एकड़ जमीन ऐक्वायर हो चुकी है और वहां पर तीन बेज बस स्टैण्ड बनाने की योजना तैयार है । मुख्य मन्त्री जी ने उसका फाउण्डेशन स्टोन भी रख दिया है और इसके लिए फण्डज अलोट होकर नैक्सट ईयर काम कम्पलीट हो

जाएगा । उकलाना में ' भी तकरीबन साढ़े चार एकड़ जमीन 2. 75 लाख की ऐक्वायर की है और उसके लिए भी तकरीबन 785 लाख रुपया अलौट कर दिया है । कितने बेज का बस स्टैण्ड कहां पर बनाया जाए । इस बारे में ट्रांसपोर्ट बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि जहां पर डिपो हैडक्वाटर्ज और बडे बड़े बस स्टैण्ड हैं । वहां पर बारह बेज का बस स्टैण्ड बनाया जाएगा । जो सब डिपो है वहां पर नौ बेज का बस स्टैण्ड, जहां छोटे डिपो हैं वहा पर छः बेज का बस स्टैण्ड और जहा सब डिपो या छोटे डिपो नहीं हैं वहा पर तीन बेल का बस स्टैण्ड बनाया जाएगा । इस पौलिसी के तहत उकलाना और बरवाला में तीन वेज के बस स्टैण्ड मन्जूर हुए हैं । ' स्पीकर साहब, इस वक्त बस स्टैण्ड बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है । छरू वेज का बस स्टैण्ड बनाने पर कम से कम पच्चीस लाख रुपया खर्च होता हे । तीन बेज के बस– स्टैण्ड पर आठ दस लाख रुपया खर्च आता है । नैन साहब ने जो प्रोबलम रखी है उस पर विचार किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट बोर्ड की मीटिंग में यह बात रखेंगे ।

श्री ए ० सी० चौधरी : मन्त्री जी ने अभी बताया हे कि बारह बेज, नौ बेज और छः बेज के बस स्टैन्डज बनाने का क्राईटेरिया डिपो और सब–डिपो होता है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डिपो या सब–डिपो खोलने का क्राईटेरिया क्या है? क्या इसका क्राईटेरिया ट्रैफिक और आबादी है? अगर बसिज और

आबादी ही काई– टेरिया है तो क्या फरीदाबाद का बस स्टैण्ड जो छरू बेज का रखा गया है वह – नाकाफी नहीं है?

कर्नल राव राम सिंह : सीकर साहब, मेन क्राईटेरिया तो ट्रैफिक का है लेकिन यह औबवियस बात है कि पापुलेशन उसके साथ जुड़ जाती है । जहां पापुलेशन ज्यादा होगी वहां ट्रैफिक ज्यादा होगा लेकिन मेन क्राईटेरिया ट्रैफिक है । ट्रैफिक जनरेशन का सर्वे कराकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट यह फैसला करता है कि कहां पर सब–डिपो होना चाहिए और कहां पर डिपो हैडक्वार्टर होना चाहिए । स्पीकर साहब, डिपो हेडक्वार्टर का जहां तक ताल्लुक है, हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐक्सैप्ट अम्बाला, में एक डिपो हेडक्वार्टर होता है । जहां तक सब–डिपो का ताल्लुक है, जहा ट्रैफिक जस्टीफाई करता है वहां सब–डिपो बनाया जाता है । आमतौर पर यह ध्यान रखा जाता है कि जहां से चालीस पचास बसिज जनरेट हो वहां पर सब–डिपो बनाया जोता है ताकि वे बसिज वहां ठहर सकें और ट्रैफिक को पिक अप करने की कलियत हो । जहां तक फरीदाबाद का तालुक है, स्पीकर साहब, फरीदाबाद और बल्लभगढ तकरीबन एक ज्वाएंट शहर हो गया हए । बल्लभगढ में डिपौ हैडक्वार्टर है और बस स्टैण्ड बनाया जा रहा है । बल्लभगढू में 18 बेज का बस स्टैण्ड बनाया जाएगा इसलिए फरीदाबाद में कोई बड़ा बस स्टैण्ड बनाने की गुंजाइश नहीं है । वहां का ट्रैफिक एन० आई० टी० से मेनली जनरेट होता है और ज्यादातर दिल्ली आफिस जाने वालों का ट्रैफिक होता हें । इसके लिए तकरीबन चार या साढे चार

एकड़ जमीन हमने ले ली हे और वहां पर बस स्टैण्ड बनाया जाएगा । अगर वहां पर बड़े बस स्टैण्ड की जरूरत होगी तो ऐग्जामिन करबाकर फिर विचार कर लिया जाएगा ।

चौधरी साहब सिंह सैनी : मन्त्री जी ने बताया है कि तीन बेज, छः बेज और नौ बेज बस स्टैण्ड बनाने का क्राईटेरिया ट्रैफिक है । स्पीकर साहब, पिपली का जो बस स्टैण्ड बनाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे पता लगा है कि वह तीन वेज का बनाने जा रहे हैं । स्पीकर साहब, पिपली से तीन चार स्टेट्स, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यू० पी०, की बसिज गुजरती हैं । क्या मन्त्री महोदय इस बस स्टैन्ड को तीन बेज का बनाने की बजाए– छः बेज का बस स्टैण्ड बनाने पर विचार करेंगे? स्पीकर साहब, दूसरा मेरा प्वांयट यह है कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक डिपो हैडक्बार्टर होता है । कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, धार्मिक स्थान है और ऐतिहासिक जगह है । क्या मन्त्री महोदय वहां पर एक डिपो बनाने के बारे में विचार करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, हेंने यह तो नहीं कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक डिपो हैडक्वार्टर होता है. मैंने यह कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिपो हेडक्वार्टर है । स्पीकर साहब, सब को पता है किं कैथल में डिपो हैडक्वार्टर है । कैथल से कुरूक्षेत्र डिपो हैडक्वार्टर शिफ्ट करने में कई

डिफिकल्टीज हैं । अगर कुरूक्षेत्र में डिपो हैडक्वार्टर बन सकता है तो इस बात को ऐग्जामिन कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : पिपली की इम्पौरटैसं बहुत भारी है ।

कर्नल राय राम सिंह : जहां तक पिपली का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिपली बहुत इम्पौरटैंट जगह है । इन्टरसैक्शर है, ट्रैफिक के लिहाज से बहुत इम्पौरटैट जगह है । इसलिए वहां पर तीन बेज का बस स्टैण्ड मन्जूर हुआ है लेकिन इसका जो डिजाइन बनाया गया है वह इस किस्म का बनाया गया है कि वह कभी भी छः बेज के बस स्टैण्ड में कन्वर्ट किया जा सकता Depending upon the availability of funds and the generation of traffic, the 3 bays bus stand can be converted into 6 bays bus stand at any time.

मास्टर राम सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से एक बात जानना चाहता हूं । मेरे रादौर हल्का में जो बस स्टैण्ड बन रहा है, उस बारे में मुझे पता चला है कि वहां पर टायलैट की सुविधा नहीं दी गई है जिससे स्त्रियों को काफी असुविधा होगी मर्द तो कहीं दूर भी जा सकते हैं । क्या वे बताएंगे कि यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां 'ए' कैटेगरी का बस स्टैण्ड बनाया जाता एं वहां पर नक्शे में टायलैट का प्रोवीजन होता है क्योंकि वहां पानी का अच्छा प्रबन्ध होता है । लेकिन जहां पर पानी का आसानी से बन्दोबस्त नहीं होता वहां

पर टायलैट का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है । क्योंकि पानी के बिना वहां पर काफी गन्दगी फैल सकती है । इंडीपैनडैन्टली वाटर सप्लाई का किसी जगह पर इंतजाम करना काफी कौस्टली पड़ता है । रादौर के बारे में मुझे याद नहीं । फिर भी हम इसको ऐग्जामिन करवा लेंगे । जो कुछ सम्भव होगा किया जाएगा । वहां बस स्टैण्ड सड़क के दोनों ओर बन रहा है जिसका पीछे मुख्य मन्त्री महोदय. ने उदघाटन भी किया था । अगर वहां पर कहीं से आसानी के साथ पानी का प्रबन्ध हो सकेगा तो वहां टायलैट का प्रबन्ध भी कर दिया जाएगा ।

सेठ राम दास धमीजा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि अम्बाला के अन्दर जो बस स्टैण्ड बन रहा है वह कितने बेज का है?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, 18 बेज का बस स्टैण्ड अम्बाला में बन रहा है ।

चौधरी लीला कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के के अन्दर बहुत सारे लोकल बस स्टौप्स के बारे में लिख कर दिया था क्योंकि यात्रियों को इनके न होने से काफी असुविधा होती थी । क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि डिफरैन्ट डिफरैन्ट जगहों पर जहां बड़ी बड़ी रोडज हैं वहां पर बस स्टौप्स बनाने का सरकार का कोई विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, बस क्यू शैलटर्ज सड़कों पर बनाये. जाते हैं । पहले ये कौरूगेटिड आयरन शीटस के बनाये अते थे 'लेकिन वे बहुत ही भद्दे लगते थे । अब ट्रांसपोर्ट बोर्ड के फैसले के अनुसार इस तरह की शीटस के शैलटर्ज बनाने बन्द कर दिये हैं) जैसा कि आप लोगों ने चण्डीगढ के अन्दर सड़कों के किनारे छोटे–छोटे बस क्यू शैलटर्ज पक्के बने हुए देखे होंगे उसी तरह के बस क्यु शैलटर्क हम बना रहे हैं और हमने हरेक जिला में हरेक डिपोज को 20 –20 बस स्टौपस बनाने के लिये फंडज अलौट कर दिये हैं । इस एक बस क्यू शैलटर पर लगभग 20 हजार रुपया कौस्ट आएगी । आनरेबल मैम्बर श्री लीला कृष्ण जी ने कोई खास जगह का नाम नहीं बताया कि वे किस जगह पर बस क्यू शैलटर बनवाना चाहते हैं । अगर वे स्पैसिफिक जगह बता देंगे तो हम बहां पर बनवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1081

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम बिलास शर्मा सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1128

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, मास्टर शिव प्रशाद सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Construction of Fly-over on Railway Tracks in Faridabad

***1134 Shri A. C. Chaudhary :** Will the Minister for

Public Works (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Fly-overs in Railway Tracks in Faridabad and Ballabgarh to remove traffic congestion; if so, the points on which such Fly—overs are likely to be constructed?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) : Yes. The proposed points on which such Fly-overs are likely to be constructed are given at Annexure 'B'. However, the final location will depend on the concurrence of the Railway authorities and the National Capital Region authority and construction will depend upon availability of resources.

ANNEXURE 'B'

Fly-over on Railway Tracks in Faridabad likely to be Constructed

(i) Construction of road over bridge at Old Faridabad crossing Delhi-Agra railway line.

(ii) Construction of road over bridge at Ballabgarh on BallabgarhPali-Sohna road crossing Delhi-Agra railway line.

(iii) Construction of road over bridge at Faridabad near Badkhal on Faridabad-Gurgaon road crossing Delhi-Agra railway line.

(iv) Construction of road over bridge at Faridabad near Bata Chowk crossing Delhi—Agra railway line.

(v) Construction of ,road bridge at Faridabad near Mujesar crossing Delhi-Agra railway line.

श्री ए ० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में यह कहा है कि फरीदाबाद में जो पांच फलाई–ओवर्ज बनने हैं उनकी फाईनल लोकेशन रेलवे अथौरिटीज की कंकरेन्स पर डिपैन्ड करती है । मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे अथौरिटीज से कुछ पुलों की कंकरेन्स राज्य सरकार को मिल चुकी है और वे कौन–कौन से पुल हें?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि अभी तक रेलवे अथौरिटीज, भारत सरकार 'की ओर से फरीदाबाद में, किसी भी फलाई–ओवर के बारे में स्वीकृति नहीं मिली है ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, पुलों की प्रोबलमज को देखते हुत सैन्टर से मेरी बातचीत हुई है और मुझे यह बताया गया है कि रेलवे अथौरिटीज ने दो पुलों की मन्जूरी राज्य सरकार को दे दी है । यह दो पुल बल्लबगढ़–पाली–सोहना रोड व दूसरा बडखल–फरीदावाद–गुडगांव रोड पर हैं । अगर सरकार तक इनकी मन्जूरी नहीं पहुंची तो क्या सरकार दोबारा रेलवे अशौरिटीज से कंकरेन्स लेने के लिए लिखेगी या सैन्टर से बात करेगी? साथ ही क्या राज्य सरकार आगामी बजट में इन पुलों के निर्माण के लिए कोई फन्डज का प्रोवीजन करेगी ।

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय भिवानी, करनाल और कुरुक्षेत्र के रेलवे फलाई–आाएवरज अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं । इन पर लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च आएगा और 1987 में ये पुल बनकर तैयार हो जाएंगे । इसके इलावा 18 फलाई. ओवरज के बारे में भी भारत सरकार को हमने लिखा है कि इनके बारे में वे बताएं कि इन पुत्रों के निर्माण के लिए क्या–क्या सहायता दी जानी संभव है । जो पांच फलाई–ओवर्ज फरीदाबाद में बनने हैं उनके बारे में ज्वायंट सर्वे हो रहा हैं । हमने दोबारा भी रेलवे अथौरिटीज को लिखा है कि आप हमें बताएं कि आपकी मिनिमम रिकवायरमैन्ट क्या हे और इन पर कितना ऐस्टीमेटिड खर्चा होगा । मेरे विचार के अनुसार इन ब्रिजिज पर साढ़े 12 करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसमें से फिफटी परसैन्ट, मतलब सवा 6 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और सवा 6 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना होगा । जहां तक इन दो ब्रिजिज का सम्बन्ध है जिस बारे में चौधरी साहब बता रहे हैं उनकी मन्जूरी अभी तक नहीं आई है ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वे 18 फलाई–ओवरज कौन–कौन से हैं जो राज्य सरकार ने सैन्टर को रिकमैन्ड किए हैं?

Shri Amar Singh : Speaker, Sir, I have already told that construction work on three fly-over bridges i.e. at karnal, Kurukshetra and Bhiwani is going on. The names of other such bridges which have been recommended, are as under :

1. Construction of Road over bridge in replacement of level crossing No. 51 on Panipat-Gohana Road at Panipat.

2. Construction of Road over bridge at Sonepat in replacement of level crossing No. 26 on Delhi-Ambala Line.

3. Construction of Road over bridge on Delhi-Hissar Sulemanki Road N. H. No. 10 crossing Hissar-Sadalpur Railway Line in lieu of existing crossing No. B. 11 Gate No. 21 in Hissar near Dabra Chowk.

4. Construction of Road over bridge at on Panipat-Assandh Road crossing on Delhi-Ambala Railway Line.

5. Construction of an over bridge on Old DHS (N.H. No. 10) Delhi-Jakhal Line at Rohtak near Bangar Cinema in lieu of existing level crossing No.63.

6. Construction of Road over bridge in replacement of level crossing No.B 89 at K.M.137/4-5, on Hissar-Rewari Railway Line section Delhi Hissar Sulemanki Road (N.H.No. 10) at Hissar.

7. Construction of Road over bridge at Dabwali on N.H. No. 10 crossing Bhatinda-Bikaner Railway Line.

8. Construction of Road over bridge at Old Faridabad crossing Delhi-Agra Railway Line.

9. Construction of Road over bridge at Ballabgarh on Pali-Sohna road crossing Delhi-Agra Railway Line.

10. Construction of Road over bridge at Kaithal on

AmbalaHissar road crossing Narwana Line.

11. Construction of Road over bridge at Faridabad near Bakhal in Faridabad-Gurgaon road crossing Delhi-Agra Rly. Line.

12. Construction of Road over bridge at Faridabad near Bata ChowK crossing Delhi-Agra Railway Line.

13. Construction of Road over bridge at Faridabad near Mujesar crossing Delhi-Agra Railway Line.

14, Construction of Railway bridge at Rewari on Rewari-Jhajjar Road.

15. Construction of Road over bridge on Dadri Road crossing Rewari-Bhatinda Railway Line,

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : स्पीकर साहब, आपकी नर्म दिली का फायदा उठा कर मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं । वैसे यह सवाल रेलवे लाइन के बारे में तो नहीं है लेकिन पुलों के बारे में जरूर है । स्पीकर साहब, एक अति लोक महत्व का रास्ता है जो बल्लभगढ़ू और फरीदाबाद को धनकौर और बुलन्द शहर से जोड़ता है । इस रास्ते से करीब सौ–डेढ़–सौ किलोमीटर इलाका जुड़ता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अति महत्व के पुल को प्राथमिकता के आधार पर बनाने की सरकार की कोई प्रपोजल है, अगर है तो इसे कब तक बना दिया जाएगा? यह पुल मज–हाली के पास बनना है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री यू० पी० ने इस बारे में लिखा है और इस पुल के बनाने पर पांच करोड़ रुपया खर्च आएगा । हमने इस बारे में लिख कर भेजा है 'कि यू० पी० गर्वनमैंट इस पुल पर सारा पैसा खर्च करे क्योंकि उनके एरिया को इस पुल से ज्यादा सर्विस मिलेगी । उनका जवाब अभी नहीं आया है । अगर वे आधा–आधा पैसा लगाकर भी बनाने को राजी हो गए तो हम इस पुल को बनाने के लिए तैयार हैं ।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया । इस समय नेता अदन भी हाजिर हैं, सड़कों के मिनिस्टर साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी हाजिर हैं । सिरसा, हिसार, भिवानी, जीन्द और कुरुक्षेत्र तथा अम्बाला यानी करीब आधा हरियाणा जो है इसको पुलों की बड़ी तकलीफ है । हिसार से चलते हैं तो हिसार–बरवाला के रास्ते में रेलवे लाईन है, बरवाला–उकलाना रेलवे लाइन है, कैथल में रेलवे लाइन है । उससे आगे अम्बाला–डेरा बसी और चण्डीगढ के बीच में रेलवे लाइन है । लेकिन अम्बाला में एक ओवर ब्रिज है मैं सदन के नेता से जानना चाहता हूं कि क्या दूसरा ओवर ब्रिज अम्बाला– कालका रेलवे लाइन पर बनाने की कृपा करेंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर सहाब, एक पुल तो अम्बाला में पहले ही बना हुआ है । दूसरे पुल की अम्बाला में अभी कोई जरूरत नहीं हे क्योंकि मैंबर साहब ने अम्बाला कालका वाला

फाटक कभी भी बन्द नहीं देखा होगा, वह हमेशा खु ला रहता है । अम्बाला–कालका लाइन पर एक दो गाड़ियां ही जातीं है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी के प्रयास से और यूनियन ट्रांसपोर्ट मन्त्री के भरसक यत्न से हमारे यहां तीन पुलों पर काम चल रहा है । मैं यह समझता हूं कि फलाई ओवर ब्रिज की मंजूरी साल या दो साल में मुश्किल से एक आध स्टेट को मिलती हे लेकिन हमारे यहां करनाल, कुरुक्षेत्र और भिवानी में ऐसे पुलों पर काम चल रहा है । इसके अलावा 5 और पुलों की अन्डरटेकिंग भी हरियाणा सरकार ने दी है । जो पौसीबल हो सकेगा करेंगें क्योंकि यह फंडज की अवेलेविलिटी पर डिपैंड करता है । 5 पुल हम आगे जरूर बनाएंगे । यह ठीक हे कि इन पुलों के न होने की बजह से ट्रक और वसें काफी देर तक रेलवे फाटकों के दोनों ओर खड़ी रहती हैं जिसकी वजह से डेली लाखों रुपए का पैट्रोल और डीजल का खर्चा ज्यादा पडता है । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अम्बाला में दूसरा ब्रिज बनाने पर विचार करेंगे । हरियाणा सरकार की इच्छा है कि रेलवे क्रौसिंग पर पुल बने लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत हे । फिर भी जहां तक पौसीवल होगा हम कोशिश करेंगे । कैथल वाला पुल बहुत जरूरी है और वह हमारी प्रायरिटी लिस्ट पर है और उसके लिए हमने अंडरटेकिंग भी दे रखी है ।

श्री अध्यक्ष : करनाल और कुरुक्षेत्र के पुलों का काम इन हेड है क्या इनको कम्पलीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट भी फिक्स की गई हे?

श्री अमर सिंह : हम चाहेंगे कि बे दोनों पुल मार्च या अप्रैल 1987 में कम्पलीट हो जाए ।

श्री कंबल सिंह : स्पीकर साहब, अभी मन्डी जी ने कहा कि पांच पुलों को अगले साल शायद टेक–अप करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि हिसार–राजगढ़ लाइन पर डाबडा चौक हाइली कंजस्टिड है, क्या वहां पर पुल बनाने के लिए प्राथमिकता देंगे?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, जैसे मैंने अभी निवेदन किया था कि हिसार में डाबडा चौक पर पुल की नसैसिटी है और इसकी अंडरटेकिंग हमने भेजी हुई है । जब भी रेलवे अथौरिटीज अपने प्रोग्राम में इसको शामिल कर लेंगी और हमें अपनी रिक्वायरमैंट बताएंगी तो हम इस पुल को बनाने के लिए तैयार हैं ।

श्री ए ० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, इन पांच पुलों में से दो पुलों का मैंने जिक्र किया था । मैं सरकार से एक बात जानना चाहता हूं कि खुश किस्मती से फरीदाबाद के पांच पुलों का एरिया नेशनल कैपिटल रीजन में कवर होता है । मैंने इनको एक चिट्ठी भी लिखी थी कि फलां तारीख को नेशनल कैपिटल रीजन कमिशन की मीटिंग हो रही है अगर आप उनके प्लान में ये

पुल डलवा दें तो बगैर पैसे दिए ये पुल बन सकते हैं । क्या उस कमिशन को इस बारे में कुछ लिखा गया है?

श्री अमर सिंह : एन०सी०आर० को हरियाणा सरकार ने दिसम्बर, 1 985 में लिखा था । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि ये पुल उनके प्लान में शामिल हो जाएं । इससे हमें फंडज मिररने में आसानी हो जाएगी और पुल बनाने में भी आसानी हो जाएगी ।

चौधरी फूल चन्द : अभी मन्त्री जी ने राज्य में ओवर ब्रीज बनाने की चर्चा की । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या कहीं पर अंडर ब्रिज बनाने की भी प्रपोजल है? अगर है तो क्या अम्बाला रेलवे स्टेशन से कोर्टस का जो दो मील का डिसटैस है, वहां पर अंडर ब्रिज बनाने का विचार है?

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, अंडर ब्रिज बनाने की अभी कोई स्कीम नहीं है । अगर आनरेबल मैंबर लिख कर देंगे तो उसको ऐग्जामिन करवा लेंगे । इस काम के लिए हमारे पास अब तक 18 करोड़ रुपया सैवन्थ प्लान में है । सारे हरियाणा में ब्रिज बनाने के लिए लगभग 44 करोड़ रुपए की जरूरत है अगर इतना पैसा हमें आज मिल जाए तो मैं समझता हूं कि हम सैवन्थ प्लान में हरियाणा की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन. की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Rural Dispensary Hassangarh in district Hissar

***1121. Chaudhri Inder Singh Nain :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert Rural Dispensary of village Hassangarh in District Hissar into a Primary Health Centre; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialise ?

Minister of State for Health & Ayurveda (Shrimati Kartar Devi) :

(a) Yes.

(b) Has been converted into a Primary Health Centre on 28.1.1986.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Road in Sonepat

209. Shri Devi Dass : Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) the total kilometres of roads constructed in each constituency of District Sonepat/Sonepat Circle during the period from January, 1984 to date together with the names of roads constructed alongwith the names of villages between which the said roads have been constructed ; and

(b) whether the Government has received any

complaint about the use of substandard material or theft of material at the time of the construction of the said roads ; if so, the names of the employees, if any, found guilty therefor and the action taken against them ?

Public Works Minister (Shri Amar Singh) :

(a) There are six Assembly Constituencies in the jurisdiction of Distt. Sonepat and 22.78 Kms. of roads have been constructed in the Assembly Constituencies of this District since 1.1.1984 to date. The details of these roads are given at Annexure 'A'.

(b) No complaint regarding use of substandard material or theft of material at the time of construction of said roads has been received.

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of Assembly Constituency		Name of roads	Total length sanctioned	Length constructed from 1.1.84 to date		Name of villages between which the said road has been constructed	Remarks
1	2		3	4	5		6	7
I.	Baroda	1.	Constn. of-jagsi Chhatehra	4.60	3.60			

			road.					
				4.60	3.60			
II.	Gohana	1	Constn. of road from Khanpur Kalan to Bajana Kalan.	8.35	3.00			
		2	Constn. of Rithal School Approach road	1.75	1.75			
			Total :	10.10	4.75			
III.	Kailana	1.	Constn. of Rajpur to Bhogipur via Rajlu-Garhi-	3.25	0.35			
		2.	Constn. of Moi to Baba Jinda road	0.20	0.20			
		3.	Constn. of Mimarpur to Jamuna-Ghat road	1.10	0.30			
		4.	Constn. of Ganaur to Bari	2.80	2.04			

		5.	Constn, of Dabarpur Mahara to Sitawali	1.20	0.05	1	Dabarpur	
						2	Sitawali	
		6.	Constn. of Bega to Ghasoli road	2.94	2.10			
		7.	Constn. of Bighan School app. road	0.71	0.60			
		8.	Constn. of Lalheri to RajluGarhi	1.32	1.10			
			Total :	13.52	6.74		2 Nos villages.	
IV.	Sonepat		NIL-					
V.	Rohat	1	Constn. of Matindu to Gurukul Matindu	2.70	2.00			
		2	Constn. of Sonepat Mehalna road	1.20	1.20		Tihar Bagru	

			to Tihar Bagru road					
		3	Constn. of Thana Kalan to Thana Khurd	1.77	0.20	1	Thana Kalan	
						2	Thana Khurd	
			Total :	5.67	3.40		3 Nos Villages.	
VI.	Rai.	1.	Constn. of G. T. road to Rasoi App. road	0.30	0.30	1.	Rasoi	
		2.	Constn. of Nathu- pur Saboli to Narela Border Road	2.40	0.40			
		3.	Constn. of G.T. road to Shahpur Turk	1.58	0.58	1	Shahpur Turk	
						2	Badh Khalsa	
		4.	Constn. of	2.40	0.50	2.	Nangal Kalan.	

			Badkhalsa to Nangal Kalan					
		5.	Constn. of Jakholi to Jhundpur	2.01	2.01	1	Jakholi.	
						2	Jhundpur.	
		6.	Constn. of Nandna- pur to Nai Basodi.	4.33	0.50		-	
			Total :	13.02	4.29		6 Nos. Villages	
			Grand Total ;	46.91	22.78		11 Nos. villages	

Disbursement of Pay through Treasury

210. Shri Devi Dass Will the Minister of State for Education

be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to disburse the pay of the. Lecturers and other staff of the recognised private colleges in the State through Government Treasury ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : नहीं । लेकिन यह निर्णय लिया गया है कि गैर–सरकारी महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा अन्य अमले को वेतन बैको के माध्यम से दिया

जाएगा जैसा कि 20—2—1988 को सरकार ने सदन में घोषणा की थी ।

Demarcation of Plots in Sector-15, Sonepat

211. Shri Devi Dass : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total area of land allocated for sector 15 in Sonepat togetherwith the number of plots demarcated therein along-with their size ;

(b) the criterion, if any, laid down Par the allotment of plots referred to in part (a) above togetherwith the rate thereof, category-wise ;

(c) the time by which the construction work in the said sector is likely to be started/completed ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to carve out more sectors, in addition to sectors, 14 and 15, in Sonepat ; if so, the number thereof togetherwith their site and the time by which the said proposal is likely to materialise ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) सैक्टर— 15 सोनीपत के लिए 113.90 हैक्टेयर भूमि आंवटित की गई है और निम्न प्लाट इसमें काटे गरा हैं :—

प्लाट का साईज	प्लाटों की संख्या
1 कनाल	164
14 भरला	370
10 मरला	502
6 मरला	438
2 मरला	80
	1558

(बी) अलाटमैंन्ट लाटरी द्वारा की गई है । उपरोक्त वर्णित प्लाटों के श्रेणी अनुसार रेट निम्न प्रकार से हैं :–

2 कनाल	232.80 रु० प्रति वर्ग मीटर
1 कनाल	213.40 रु० प्रति वर्ग मीटर
14 मरला	194.00 रु० प्रति वर्ग मीटर
10 मस्सा	194.00 रु० प्रति वर्ग

	मीटर
8 मरला	174.82 रु० प्रति वर्ग मीटर
2 मरला	155.22 रु० प्रति वर्ग मीटर

(सी) विकास कार्य शुरू कर दिया गया है और प्लाटों का कब्जा दो वर्ष के बाद दिए जाने की सम्भावना है ।

(डी) निकट भविष्य में सोनीपत में अन्य रिहायशी सैक् र काटने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Construction of 100 bed Hospital at Sonepat

212. Shri Devi Dass : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) the date by which the construction of **100** beds new hospital at Sonepat was likely to be constructed and the estimated expenditure thereof togetherwith the expenditure so far incurred on its construction; and

(b) the number of quarters so far constructed out of those proposed to be constructed, for the doctors and other staff of the said hospital togetherwith the time by which the remaining quarters, category-wise, are likely to be constructed ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी)

:

(क) नए 100 बिस्तर अस्पताल, सोनीपत का निर्माण कार्य दिनांक 31–3– 1987 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । निर्माण की अनुमानित लागत 211–52 लाख रुपए हैं । दिनांक 31– 12–85 तक 157– 74 लाख रुपए खर्च हो चुके हें ।

(ख) अभी तक अमले के लिए कोई मकान नहीं बनाये गये हैं । अमले के लिए निम्नलिखित मकान बनाये जाने प्रस्तावित हैं :–

क्र० संख्या	कैटेगरी का नाम	निवास गृहों की संख्या
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
2	एच० सी० एम० एस० वर्ग –1	2
3.	एच० सी० एम० एस० वर्ग–2	10
4.	हाऊस सर्जन	2
5.	तृतीय श्रेणी	24
6.	चतुर्थ श्रेणी	24
7.	नर्सिज होस्टल (12 नसों के	1

	लिए)	

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

फरीदाबाद (एन ० आई० टी ०) में पिट/बोर शौचालयों के मल से भूमिगत जल के दूषित होने तथा खारा होने आदि सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री ए० सी० चौधरी, एम० एल ० ए०, की ओर से फरीदाबाद (एन० आई० टी०)ए में पिट/बोर लैवाटरीज के कारण नाइट सोआयल कन्टैमीनेटिंग दि सब–सोआयल वाटर एंड वाटर गैटिंग ब्रेकिश ऐटसैट्रा के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस मिला है । मैं इसे ऐडमिट करता हूं । श्री ए0 सी० चौधरी अपना नोटिस पढ़ दें । अगर मैली जी इसका आज ही स्टेटमैंट देना चाहें तो दे दें ।

Shri A.C. Chaudhry : Sir I want to draw the attention of the August House towards a matter of urgent public importance that the drinking water supplied to Faridabad (N.I.T.) is arranged through 30 tubewells of different capacities, there being no ether source of water supply. At the time of inhibition of Faridabad (N.I.T.) (at the time of settlement of refugees migrating from Pakistan) pit/bore lavatories were provided with each and every house of the area, resulting thereby night soil contaminating the sub soil water. The water is going brakish and the situation has arisen that it has crossed 'permissible limits', and is even at the verge of crossing 'tolerance limits', which is danger signal. If this situation aggravates even by 10 to 15% this will be

dangerous to public health to the extent that it will spread contagious diseases, which may even cost valuable lives. This above contention is endorsed from the results of laboratory tests of these- brakish waters which has clearly declared it as sub standard to the tune of 'not worth human consumption'.

In the above circumstances of serious nature, I would like that the. Government may make a statement on this issue of urgent public importance on the floor of the House.

वक्तव्य–

स्थानीय शासन राज्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षक प्रस्ताव संबंधी

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री औम प्रकाश महाजन) : स्पीकर साहब, एन० आई०टी० फरीदाबाद की वर्तमान जनसंख्या लगभग दो लाख है । फरीदाबाद में पीने के पानी की कमी के कारण फरीदाबाद के लोगों के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है जिसका कि एन० आई० टी० फरीदाबाद के माननीय विधान सभा सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया है । यह मामला पिछले दो दिनों में भी दो तारांकित विधान सभा प्रश्नों द्वारा उठाया गया था । सरकार इस मामले में पूर्णतया जागरूक है और इस समस्या को हल करने के लिये पग उठा रही है । वर्ष 1947 में देश के विभाजन के समय जो शरणार्थी पश्चिमी पाकिस्तान से आये थे, उनके पुनर्वास के लिये यह नया कस्बा विकसित किया था । यह

सत्य है कि लोगों की सुविधा के लिये शरणार्थी कैम्पों के आस–पास गढ्ढे वाले शौचालय उपलब्ध करवाये गये थे । साधारणतयरू गड्ढे वाले शौचालयों की गहराई 8 से 10 फुट है । कीटाणु केवल 25 फुट की दूरी तक फरीदाबाद में प्रचलित एल्वियल स्टरैटा के जरिये जा सकता है । एन० आई० टी० फरीदाबाद क्षेत्र में जो 32 नलकूप खोदे गये हैं वे 150 से 200 फुट गहरे हैं और पानी मीठा है और यह दूषित नहीं है । यदि अधिक नलक्ऊप खोदे गये तो पानी खारा हो जायेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है । भूमि के स्टरैटा में नमक होने के कारण पानी खारा हो जाता है और यह भूमि के अन्दर की सतह में गन्दगी के कारण नहीं होता । यदि गढ्ढे के शौचालयों की 50 फुट दूरी के अन्दर नलकूप स्थित हों तो गन्दगी से पानी दूषित हो जाता है । नलकूपों के पानी का समय–समय पर परीक्षण किया जाता है और अब तक कोई ऐसी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और यह स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है ।

एन ० आई० टी ० फरीदाबाद में वर्ष 1947 से लोग रह रहे हैं । पिछले 40 वर्षो से इस क्षेत्र में पानी से उत्पन्न कोई किसी माहमारी के रोग की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे कि नलकूप का पानी गन्दगी से दूषित हुआ हो जैसे कि माननीय सदस्य ने दोष लगाया है । यह ठीक है कि खारा पानी पीने के लिये अच्छा नहीं होता है और सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र

में अच्छे पीने के पानी कभई योजनायें बनाई हैं । मीठे पानी की सतह अनुपलब्धि, अनियमित विजली की पूर्ति, धन राशि की कमी और विकास चार्जिज फरीदाबाद एन० आई० टी० के लोगों कीं न देने की इच्छा इत्यादि विभिन्न जल वितरण योजनाओं को कार्यान्वित न करने के यह कुछेक कारण हैं । धन राशि की अपर्याप्ता भूमिगत अच्छे पानी की पर्याप्त माता में अनुपलब्धि के विभिन्न कारणों से एन० आई० टी ० क्षेत्र में लोगों की मांग को पूरा करने के लिये जल वितरण योजना को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है । लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन द्वारा अपनाई गई जल वितरण योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिये सरकार घोर प्रयत्नशील है ।

श्री ए० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि सरकार ने यह कह दिया है कि वहां पर पानी कन्टैमनेटिड नहीं है । मैं रिपोर्टी की डिटेल में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इस वक्त तक जितनी भी रिपोर्टें सरकार के पास आई हैं उन में किसी न किसी स्टेज पर कई सालों से यह जिक्र आता रहा है कि फरीदाबाद में पानी वर्थ कंजम्पशन नहीं है । सरकार यह भी नहीं मानती है कि वहां पर पानी बैकिश हो रहा है । सरकार कन्टैमिनेशन की डिग्री को भी डिसप्यूट कर रही है । लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन हालात में फरीदाबाद की जनता को पीने के

पानी का आल्टरनेटिव इन्तजाम करने के बारे में सोच रही है और अगर सोच रही है तो उसे कब तक पूरा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी स्टेटमैंट में यह कह दिया है कि वहां पर कीटाणुओं की वजह से पानी में इस प्रकार की कोई गन्दगी नहीं है । हमारे पास वहां से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । सारे फरीदाबाद कम्पलैक्स से ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है कि वहां पर पीने का. पानी अच्छा नहीं है । जहां तक खारे पानी की बात है वहां पर 31 नलकूप हैं उनको रैनीवैल करने के लिए सरकार 'हुडडा' के साथ मिल कर योजना बना रही है जिस पर लगभग 12 करोड़ कुछ लाख रुपये खर्च होंगे । मैं अपने माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें अपना जो सहयोग दे सकते हैं वह दें । यह पापुलर सरकार है और जनहित में चाहे. किसी भी प्रकार का काम हो उसे फर्स्ट प्रायर्टी देगी ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होने वहां पर पीने के पानी के लिए आल्टरनेट सजैस्ट किया है और यह कहा है कि नलकूपों को रैनीवैल करने के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे । मैं यह जानना चाहूंगा कि आज कल चूंकि हुडको और वर्ल्ड बैंक पानी के लिए और सिवरेज के लिए लोन देते हैं इसलिए आप अपने तौर पर अपनी तरफ से इस बारे में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल, टैक्नीकल ऐप्रूवल और सैनेटरी

बोर्ड की एप्रूवल दे दें ताकि उन से लोन ले करके इस काम को पूरा करवाया जा सके और हालात खराब न हों ।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल, टैक्नीकल ऐप्रूवल और सैनेटरी बोर्ड की ऐंप्रूवल के बारे में बात कही है । हम इस बारे में जल्दी कार्यवाही करेंगे लेकिन हुडको ओर वर्ल्ड बैंक ने जो लोन देना हे वह हमारे अधिकार में नहीं है । हम आपका यह मसला एक महीने में हल कर देंगे ।

वर्ष 1986– 87 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1986–87 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्कशन होगी ।

पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाइम बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी । आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों । डिस्कशन के बाद डिमाडज हाउस की वोट के लिए पुट की जायेंगी ।

That a sum not exceeding Rs. 85,82,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. I-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 20,65,84,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 2-General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 51,3623,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 10,22,14,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exeeeding Rs. 5,52,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 28,76,62,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the cour e of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 37,41,78,000 for revenue expenditure and Rs. 37,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in

the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 33,03,32,000 for revenue expenditure and Rs. 32,15,85,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum not exeeding Rs. 1,55,84,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 93,86,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 6,08,36,000 for revenue expenditure and Rs. 27,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 9,79,32,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 26,30,81,000 for revenue expenditure and Rs. 2,17,45,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 2,54,27,000 for revenue expenditure and Rs. 1,70,70,26,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 14-Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 90,81,84,000 for revenue expenditure and Rs. 1,45,67,47,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation

That a sum not exceeding Rs. 10,40,73,000 for revenue expenditure and Rs. 3,54,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 45,71,33,000 for revenue expenditure and Rs. 3,95,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 14,50,39,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs.2,31,76,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges, under Demand No. 19– Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 20,14,75,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 32,81,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 7,43.05,000 for revenue expenditure and Rs. 4,92,70,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 22-Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 92,45,50,000 for revenue expenditure and Rs. 12,48,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 97,23,000 for revenue expenditure and Rs. 1,05.00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 1,66,97,48,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under r Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.

श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, मैं डिमांड ने 8, 9, 10, 12, 15 और 24 पर बोलना चाहूंगा । परसों सदन में जो बजट पेश हुआ था उसी संदर्भ में आज ये डिमांडज हाउस से पास करवाई जा रही हैं । सरकार ने कहा है कि अगले साल 100 स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा । यह एक अच्छी बात है । स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं । मेरी कांस्टिचुऐंसी के अन्दर भी लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके स्कूलों की बिल्डिगें बनाई हैं । यदि सरकार इन स्क्लों को अपग्रेड करती है तो बच्चों को पढ्ने के लिए गांवों से दूर नहीं जाना पड़ेगा । मेरे अपने गांव जागसी में भी लड़कियों का स्कूल मिडिल से हाई स्कूल अपग्रेड होना है । इसी प्रकार से ज्वारा मिडिल स्कूल को हाई स्कूल अपग्रेड होना है । गर्वनमैंट मिडल स्कूल मदीना भी हाई स्कूल अपग्रेड होना है । वहां पर लोगों ने दो लाख रुपये इकट्ठे करके स्कूल की बिल्डिग को भी बना दिया है । रिण्डाना गांव के मिडल

स्क्ल को भी हाई स्कूल अपग्रेड किया जाना है । रिण्डाना गांव के अन्दर शिक्षा मैली जी गए थे । यह स्कूल पिछले साल के बजट में जो स्कूल अपग्रेड होने थे उनमें अपग्रेड होना था लेकिन अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है । मुझे पता चला है कि पिछले साल के कोटे से 4 स्कूल अभी अपग्रेड होने बाकी हैं और इन स्कूलों को अपग्रेड करने की फाईल चली हुई है । इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि रिण्डाना गांव के मिडल स्कूल को पिछले साल के कोटे से ही हाई स्कुल में अपग्रेड कर दिया जाये । इसी प्रकार से मेरी प्रार्थना है कि डुराना प्राईमरी स्कूल. को मिडल स्कूल अपग्रेड किया जाये । छपरा गांव में जो प्राईमरी स्कूल है उसको सीधा हाई स्कूल अपग्रेड किया जाना है । इसलिए इस स्कूल को भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दिया जाये । इसी प्रकार से कोहला गांव में जो प्राईमरी स्कूल हैं उसको मिडल– स्कूल में अपग्रेड किया जाना है । गोहाना के. न्दर भी जो बच्चों का प्राईमरी स्कूल हैं उसको मिडल स्कूल में अपग्रेड किया जाये । इन सब –स्कूलों के बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना हैं कि इनको अपग्रेड कर दिया जाये ताकि जो लोगों ने पैसे लगा कर बिल्डिंगज बनाई हैं वे बेकार न पड़ी रहें । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदसीन हुए ।)

यदि इन स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया जायेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी । डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं सड्कों की बात करूंगा । यह बात ठीक है कि हमारे यहां पर सड़कों की

हालत बहुत अच्छी है लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जो सड्कों से जोड़े नहीं गए हैं । सरकार की यह पालिसी भी हैं कि जो परचेज सेन्टर हैं उनको पक्की सड्कों से जोड़ा जायेगा ताकि परचेज सैन्टरों के अन्दर किसानों को अपना अनाज लाने में कोई दिक्कत न हो । कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब गोहाना में गए थे । उस समय उन्होंने कहा था कि 2–3 सालों में सभी परचेज सेन्टरों तक पक्की सड़कें पहुंचा दी जाएंगी । लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । मेरे हल्के में बिचपडी से जुटाना की सड़क का ऐस्टीमेट मन्जूर हो चुका हैलेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है । इसी प्रकार से गयाना से बिचपडी, सतसाढ से मुण्डलाना (मण्डी), कोहला से बरोडा (परचेज सेन्टर) महमूदपुर से बिचपडी की सड़कें बनाई जानी हैं । इसी प्रकार से सरफाबाद से जागसी तक की सड़क को पक्का किया जाना है जबकि वहां पर मिट्टी पड़ने का काम भी पूरा हो चुका हैं । यदि यह सड़क बन जाती है तो इससे दो जिले की सीमाएं आपस में मिल सकती है । इस बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह जो 5 किलोमीटर का टुकड़ा है इसको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाये । इसी प्रकार से गंगाना से सरफाबाद की दो किलोमीटर की सड़क को भी पक्का किया जाना जरूरी है । इस्के साथ साथ घडवाल से रिण्डाना तक की सड़क भी पक्की की जानी है जो कि पहले–ही मन्जूर हो चुकी है । इसी प्रकार से छपरा से बनवासा रोड़ ओर छतैरा से मातण्ड तक की सड़क भी बनायी जानी है । पीछे जब मुख्यमंत्री जी उस

इलाके में गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो सड़कें पक्की की जानी हैं उनको जल्दी से जल्दी पक्का कर दिया जायगा । इसलिए मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि जो सड़कें वहां पक्की की जानी हैं उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाये ताकि लोगों को आराम हो सके । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे इलाके में काफी बाढ आती है । यह ठीक बात है कि सरकार वहां पर लोगों की हर साल मदद करती है । लेकिन इसके बावजूद भी जो छोटी–छोटी ड्रेनें या माईनर्ज हैं उन पर पुल बनने रह जाते हैं जिनसे लोगों को बारिश के दिनों में बड़ी भारी दिक्कत उठानी पड़ती है । यदि इन जगहों पर पुल बना दिए जात् तो सरकार को ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेगे और लोगों को सुविधा भी अधिक हो सकेगी । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध हे कि ऐसी जगहों को प्रैफरैंस देकर काम करना चाहिए । मेरी आई०पी०एम० साहब से प्रार्थना है कि खन्दरोई से वजीरपुर, वजीरपुर से बिचपडी तक की जो माईनर ऐक्सटैण्ड की जानी है वह जल्दी से जल्दी ऐक्सटैण्ड की जाये । मुझे इस बारे में पता चला है कि वहां पर सैक्शन 4 और 8 के नोटिस जारी न होने की वजह से यह केस फाईनल नहीं हो पाया है जबकि लोगों की तरफ से उस माईनर को हर साल ऐक्सटैण्ड करने की मांग आती है । जहां तक यह माईनर ऐक्सटैण्ड होनी है वहां पर अब भी पानी खड़ा है । खासकर निजामपुर गांव में पानी खड़ा है । इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी माईनरों को या ड्रेनों को प्रेफरैस देकर बनाया जाये ताकि लोग अपनी जमीन के अन्दर बिजाई कर

सकें । इन ड्रेनों की खुदाई न होने की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पडता है । इसी प्रकार से कहलपा ड्रेन की खुदाई होनी जरूरी है । इस ड्रेन की खुदाई के लिए सैक्शन 4 और 6 के नोटिस जारी भी हो चुके हैए और दूसरे सारे कागजात तैयार पड़े हैं । इस बारे मेरी प्रार्थना है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 हजार की आबादी पर एक पी०एच ०सी ० खोला जायेगा । लोगों को पी०एच०सी ० की काफी जरूरत है खासकर उन जगहों पर जहां अधिक बीमारी फैलती है । मेरे हल्के के अन्दर जागसी–मंगाना, सिवाना और मदीना की आबादी 30 हजार से. अधिक है । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जागसी या गंगाना के अन्दर, जहां भी सरकार उचित समझे, ऐक पी०एच०सी ० खोली जाए ताकि वहां की जनता को इसका लाभ हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं पशु हस्पतालों का जिक्र करना चाहता हूं । बाढ़ के दिनों में बहुत अधिक बीमारी पशुओं में फैल जाती है । हुस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से आदमियों के लिए हस्पताल खोले हुए हें उसी प्रकाररू से पशुओं के लिए भी हस्पताल आदि बनावे जायें । मेरी कांस्टिचुऐंसी के लोगों ने चन्दे इक्ट्ठे करके कई जगहों पर पशुओं के हस्पताल खुलवाने के लिए बिल्डिंगें आदि भी बना दी हैं ।

भावड, छतेरा, नूरण खेड़ा और रिण्डाना में पशु हस्पताल बनाये जाने बहुत जरूरी हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं टूरिज्म की बात कहना चाहूंगा । ट्रिज्म का एकाध कम्पलैक्स ही घाटे में है बाकी सारे फायदे में चल रहे हैं । इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गोहाना शहर के अन्दर भी एक टूरिज्म कम्पलैक्स बनाया जाये । वहां पर इस समय टूरिजम का कोई कम्पलैक्स नहीं है । गोहाना से रोहतक, दिल्ली, नारनौल, चण्डीगढ, रिवाडी, जीन्द, भिवानी और हिसार आदि के लिए बसें चलती हैं वैसे भी गोहाना इन जगहों पर जाने वाली बसों के बीच में पड़ता है । जब पीछे मुख्य मन्त्री जी गोहाना गए थे उस समय उन्होंने वायदा किया था कि वहां पर टूरिज्म का एक कम्पलैक्स चालू कर दिया जायेगा । अब मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर ड्रेन के आस पास जो झील है उस जगह पर या और कोई अच्छी सी साईट देख कर एक टूरिज्म कम्पलैक्स जल्दी से जल्दी चालू किया जाये ताकि वहां के आसपास के लोग इस टूरिज्म कम्पलैक्स का आनन्द ले सकें ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले साल सरकार ने मेरे हल्के में गंगाना गांव के प्राईमरी स्कूल को मिडल स्कूल में अपग्रेड किया था । जब कोई नया स्कूल अपग्रेड करना होता है तो वहां दो पोस्टें एस०एस० मास्टर की और साईंस मास्टर की सैंक्शन करनी होती हैं । वहां पर ये दोनों पोस्टें अभी तक भरी नहीं गई हैं । इसके साथ ही साथ प्राईमरी स्कूल के टीचर्ज भी वहां पर

नहीं हैं । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर एस०एम० मास्टर और लार्ड्स मास्टर जल्दी से जल्दी भेजे जाए । इसके अलावा प्राईमरी तक का जो स्टाफ नहीं है वह भी जल्दी से जल्दी भेजा जाये ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान न हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कल भी जिक्र किया था कि गोहाना में मंडी बनाई जाए । मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि बिजली के कुनैक्शंज अवेलेबल बिजली को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और डोमैस्टिक यूज के लिए हर जगह जल्दी से जल्दी दिए जाएं । अध्यक्ष. महोदय, गोहाना में एक 132 के०वी० सब सैन्टर बन रहा है । उसमें पता नहीं सामान की कमी है या किसी दूसरी चीज की कमी है । उसमें काफी समय से वह प्रोग्रेस नहीं हो रही है जो होनी चाहिए । मैं चाहूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि वहां जो बिजली की कमी है वह पूरी हो । वहां अपस पास इस तरह का कोई सब सैंटर नहीं है । उसके बनने से हमारा काम चल जाएगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं सोशल वैल्फेयर के बारे में अर्ज करूंगा । यह बात ठीक है कि सरकार बीकर सैकशंज के लिए और गरीव आदमियों के लिए काफी पैसा खर्च करती है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । उन्हें घर बनाने के लिए 2 हजार रुपये की ग्रान्ट दी जाती है । यह बहुत कम है । आज कल तो 2 हजार रुपये से केवल 4–5 हजार ईटें आती हैं । यह

दो हजार रुपये की राशि आज से 8–10 साल पहले फिक्स की गई थी । इस अर्से में काफी प्राईसिज इन्कीज हो गई हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस राशि को बढ़ा कर कम से कम 5 हजार कर दिया जाए । इसी तरह की दूसरी स्कीमों को भी दुबारा कसीडर किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हम लोगों को दे सकें । इन शब्दों के साथ मैं इन डिमांडज का समर्थन करता हूं ।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, समय देने के लिए धन्यवाद । 1986–87 की जो डिमांडज सदन में पेश हुई हें क् भी इन डिमांडज के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा । मैं डिमांड नं० 8, 10, 11, 12, 14, 15, 10, 23, 24 और 25 के ऊपर चर्चा करूंगा । सबसे पहले डिमांड नं ० 8 है जो बिल्डिग्ज एंड रोडज के बारे में है । उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कुरूक्षेत्र जिले से सम्बन्ध रखते हैं । आपने देखा होगा कि बहुत सारी सडकें बन चुकी हैं, काफी गांव कुनैक्ट हो चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सडकें हैं जो कम्पलीट होने को रहती हैं । डबल लिंक बनाने से बहुत सारा डिसटैंस कम हो जाता है और बहुत सारे लोगों को सुविधा मिल सकती है । मेरे हलके में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनकी सूची मैंने मती महोदय को दी हुई है । कुछ सड़कों के तो चीफ इंजीनियर के औफिस में ऐस्टिमेटस भी आए हुए हैं । तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी क्लीयर करके सड़कों पर काम शुरू किया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हलके में मुडाखेडा के पास एक काज वे बनना है । उससे बहुत सारे गांव जुड़ते हैं । यह ज्योतिसर के पास है और इससे सरदार प्यारा सिंह जी के हलके के गांव भी जुड़ेने । मुख्य मन्त्री जी ने एक सभा में कहा था कि हम इसे मंजूर करेंगे लेकिन वह अभी तक वैसे का वैसा पड़ा है । उसका 9– 10 लाख रुपये का ऐस्टिमेट है । मैं प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी क्लीयर हो ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिल सके । इसी प्रकार का एक काज वे सिरसला से कसेरला रोड पर बनना है । सड़क वहां बनी हुई है लेकिन बरसात के दिनों में पानी की वजह से लोग आ जा नहीं सकते । उस पर केवल 50–60 हजार रुपये का खर्चा आएगा । उस पर भी काम जल्दी ही शुरू करवाया जाए ताकि लाँगों को उससे सुविधा मिले ।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड न० 10 मैडिकल एंड पब्लिक हैल्थ की है । लाडवा हस्पताल का जिक्र प्रश्न के दौरान आया था । वह हस्पताल बहुत छोटा है । बिल्डिंग भी पुरानी है । वहां के लोग जगह देने के लिए तैयार हैं । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है हाउस में कि हम जल्दी ही उसे बडा हस्पताल बनाएंगे । 30 बिस्तरों के हस्पताल की लोगों की मांग है । मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको जल्दी कलीयर किया जाए क्योंकि उस एरिया में इसकी बहुत जरूरत है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको पता है रादौर में पी०एच०सी० है । बबैन में बनने वाली है । काम शुरु नहीं हुआ है । उधर कुरूक्षेत्र है । बीच के

लोगों को असुविधा होती है । इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब मथाना गांव पीपली और लाडवा के बीच में पड़ता है । उसमें भी मैडिकल फैसिलिटीज नहीं हैं । मैंने कुरूक्षेत्र के सी०एम०ओ ० से अनुरोध किया था कि वहां एक पी०एच०सी ० बनाया जाए । पीपली में एक छोटा सा हस्पताल है । वहां एक डाक्टर है जो ना काफी है । इसलिए वहां भी पी० एच० सी० बनाया जाए । जो हमारा लोक नारायाण जयप्रकाश हस्पताल है वह 100 बैडज का है लेकिन वहां ऐक्सपर्टस सर्विसिज पूरी तरह अवेलेबल नहीं हैं । मैंने मती महोदया से कई बार प्रार्थना की है कि वहां पूरा स्टाफ दिया जाए ताकि लोगों को दिक्कत न आए । कई पेशैन्टस जब वहां सीरियस नेचर के जाते हैं तो उन्हें चंडीगढ़ या रोहतक के लिए रैफर कर दिया जाता है । जो फैसिलिटीज वहां मिलनी चाहिए वे वहां उपलब्ध नहीं हो रही हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि उस कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए । इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब वहां डाक्टर्ज के लिए रैजिडैन्सीज नहीं हैं । परिणाम–स्वरूप डाक्टर्ज को बाहर रहना पड़ता है । ऐमरजैसी के वक्त बड़ी मुश्किल हो जाती है । मुख्य मंत्री जी वहां गए थे और विश्वास दिलाया था कि उन्हें जल्दी बनवाएंगे । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि इन क्वार्टर्ज को जल्दी बनवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके एरिया में पानी कुछ ऊंचा है लेकिन थानेसर, रादौर और शाहबाद के क्षेत्रों में पानी का लेवल नीचे चला गया है और सारे गांव प्रौब्लम विलेजिज बन गए हैं । नलके वहां कामयाब नहीं हें । टयूबवैल्ज ' को बिजली कम मिलती है । पीने के पानी की बड़ी असुविधा है । अब सरकार ने कुछ और वाटर सप्लाई स्कीम्ज चालू करनी हें । मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के की कुछ स्कीम्ज जो इंजीनीयर इन चीफ के दफतर में आई हुई हैं उन्हें क्लीयर किया जांए ताकि वहां के लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिल सके । वे स्कीम्ज बीडमथाना और बहलोलपुर आदि गांव के लिए हैं । कुछ स्कींम्ज वहां अधूरी भी पड़ी हैं । कडामी वाटर सप्लाई स्कीम 4–5 गांवों के लिए है लेकिन मुनियरपुर और गादली गांव इससे जुड़ने कौ रह गए हैं । इन गांवों को भी इस स्कीम के साथ जोड़ा जाए ताकि इन गावों के लोगों को भी पानी की सुविधा मिल सके । डिप्टी स्पीकर साहब लेटैस्ट सर्वे के मुताबिक वहां अब हर गांव प्रौब्लम विलेज बन गया है । पहले' सर्वे में ये प्रौब्बम विलेजिज नहीं थे । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमारे सभी गावों में पानी का प्रबन्ध किया जाए । कुरूक्षेत्र शहर में 1 2– 13 नलकूप लगे हैं लेकिन उन्हें फीडर से बिजली की डायरैक्ट सप्लाई नहीं है । बिजली कम मिलने से वहां पानी की बड़ी असुविधा होती है । अब मुझे पता लगा है कि 8 टयूबवैल्ल को शायद डायरैक्ट फीडर से बिजली देने की मंजूरी हो चुकी है लेकिन 4 टयूबवैल्ज और बाकी रह जाते हें । उनको भी जल्दी से जल्दी डायरैक्ट फीडर से जोड़ा जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, 11 नं० डिमांड अर्बन डिवैलपमैंट के बारे में है । हूड्डा ने वहुत अच्छा काम किया है । शहरों में काफी विकास हो रहा है । महकमा आर सरकार इसके लिये बधाई की पाल हैं लेकिन जिन किसानों की जमीन ऐक्वायर की जाती है उनको पेमैंट टाईम पर नहीं मिलती है । रतगल व देवीदासपुरा मेरे हलके में पीपलों के पास पड़ते हैं । इनकी जमीन ऐक्वायर की गई थी लेकिन कम्पनसेशन कम दिया गया । उन्होंने कोर्ट में दावा किया । हाई कोर्ट तक वे आप । हाई कोर्ट ने उनका कम्पनसेशन एक साल पहले बढ़ा दिया था लेकिन अभी तक उन्हें उसकी पेमैंट नहीं मिली है । वे लोग दूसरी जगह जमीनें खरीदना चाहते हैं लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वे खरीद नहीं सकते । इसलिए मैरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी उनको पेमैंट करवायी जाए । कई लाख की पेमैंट रूकी हुई है लेकिन महकमा किस्तों में पेमैंट कर रहा है । कभी पचास हजार रुपया दे देते हैं और कभी साठ हजार रुपया दे देते हैं । यह बहुत ही अन्याय की बात है । सरकार से प्रार्थना है कि वह इस तरफ ध्यान दे ।

11.00 बजे

इससे नैक्सट डिमान्ड 12 नम्बर है जो लेबरपून्ड ऐम्पलाएमैंट के बारे में है । इस बारे में मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र में कोई इन्डस्ट्री नहीं है जिसकी बजह से वहां पर ऐम्पलाएमैंट के ऐवेन्यूज भी नहीं हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर पब्लिक सैक्टर में कोई इन्डस्ट्री लगायी जाये ताकि

लोगों को रोजगार मिल सके । कुरूक्षेत्र में 500–600 एकड़ जमीन इन्डस्ट्रीज के लिए ऐक्वायर हो गई है लेकिन अभी तक वहां पर न कोई प्राइवेट सैक्टर में और न ही पब्लिक सैक्टर में इन्डस्ट्री लगी है । पता नहीं प्लाटस मंहगे होने की बजह से या किसी और कारण से लोग नहीं आ रहे हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि पब्लिक सैक्टर में जरूर इन्डस्ट्री लगायी जाये ताकि उस इलाके के लोगों को रोजगार मिलने में सहूलियत मिले ।

डिमान्ड नम्बर 14 फूड एन्ड सप्लाईज के बारे में है । यह डिपार्टमैंट काफी अच्छा काम कर रहा है लेकिन इस विभाग के बारे में फाइनैन्स मिनिस्टिर साहब से मेरी दरखास्त है कि लाडवा के कमीशन एजेन्टों की मांग है कि उनकी पेमेंट वहीं से होनी चाहिए क्योंकि उनकी पेमेंट कुरूक्षेत्र से होती है । उन्हें चौक लेने के लिए कुरूक्षेत्र आना पड़ता है जिसके कारण वहां के व्यापारियों को दिक्कत होती है । लाडवा में सत–ट्रेजरी है । इसलिए उनको वहीं से पेमेंट की जा सकती है । कोई ऐसा तरीका निकाला जाये, जिस तरह से शाहबाद और यमुनानगर गे पेमेंट होती है, उसी तरीके से यहां के व्यापारियों को सुविधा हो जाये । हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर गुप्ता जी भी वहां गये थे । व्यापारियों ने इनसे यह मांग की थी कि उन्हें यह फैसिलिटी दी जाये । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दे कर उन्हें यह फैसिलिटी दी जाये । डिमान्ड नम्बर 15 इरीगेशन के बारे में है । नहरों के बारे में मैं इरीगेशन तथा फाइनैन्स मिनिस्टर साहेबान का बहुत

धन्यवादी हूं कि वे लाडवा और नलवी की बहुत अच्छी स्कीमें बजट में लाए हें । मेरे इलाके में बिजली की बहुत कमी थी जिस के कारण सिंचाई नहीं हो सकती थी और पैदावार में भी कमी आ रही थी । बिजली की जहां पर कमी है उस कमी को भी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है । लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहौ लाडवा में सब–स्टेशन है, उसका ट्रांसफार्मर इतना छोटा है कि कैथल तक बिजली पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है । इसलिए वह ट्रांसफार्मर चेंज होने वाला है ताकि बबैन में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है वह अच्छी तरह से इलाके को फीड कर सके । इसी तरह से कुरुक्षेत्र में भी 132 के० वी० का सब–स्टेशन मंजूर हुआ है । वहां पर उस के लिए जगह ऐक्वायर हो चुकी है । इस 'लिए उसे जल्दी से बनाया जाए । वहां पर 220 के० वी ० का जो पावर स्टेशन है वह बी ० एम० बी० के कडोल में है । उन का ही वहां पर स्टाफ है । वहां पर जो बिजली दी जाती हैं वह जोन वाइज दी जाती है । जब हमारे डिस्ट्रिक्ट को बिजली मिलने का नम्बर आता है तो वे एकदम से कट लगा देते हैं चाहे वह बिजली डौमेस्टिक हो या ऐग्रीकल्चर के लिए हो । मेरी इस बारे में गुजारिश है कि वहां पर बी ० एम ० बी ० के स्टाफ की बजाए अपना स्टाफ लगाया जाए या पीपली में जो सब–स्टेशन है उसे डिवैल्प किया जाये । मैं ड्रेनज के विषय में भी अर्ज करना चाहता हूं । हमारे यहां एक प्रताप– गढ़ गांव है । वहां पर बरसात के दिनों में पानी रूक जाता है । इस लिए वहां पर ड्रेन बननी है ।

उस ड्रेन का दो लाख रुपए का ऐस्टीमेट बन कर आया है । इसलिए यह ड्रेन जल्दी से जल्दी बनायी जाये ।

डिमान्ड नम्बर 18 इन्डस्ट्री के बारे में है । मैंने इन्डस्ट्री के बारे में पहलें भी कहा है कि हमारे यहां कोई भी बड़ी इन्डस्ट्री न प्राइवेट सैक्टर में है और न ही पब्लिक सैक्टर में है । कुछ छोटी इण्डस्ट्रीज रूरल सैक्टर में लगी हैं लेकिन चूंकि उन्हें बिजली की कोई सुविधा नही है इस लिए वह ठीक प्रकार नहीं चल पा रही हैं । डिप्टी स्पीकर साहब हमारे जिले को छोड़ कर अमृतसर से ले कर दिल्ली तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ऐसा नहीं है जहां पर इन्डस्ट्री न हो लेकिन कुरुक्षेत्र जिला ऐसा है जहां न प्राइवेट सैक्टर में कोई इंडस्ट्री है और न पव्लिक सैक्टर में है । वहां पर इन्डस्ट्री लगाई जाए ताकि लोगों को रोजगार दे सकें और वहां की इकोनोमी डिवैल्प हो सके । इस लिए मेरी फिर से प्रार्थना है कि वहां पर पब्लिक सैक्टर में इन्डस्ट्री की तजवीज की जाये ।

डिमान्ड नम्बर 23 ट्रांसपोर्ट के बारे में है । मैंने सरकार से पहले भी अनुरोध किया था कि कुरु क्षेत्र में बस डिपो बनाया जाए । उस का केस अन्डर कंसिडेरशन है । जैसा कि मिनिस्टर साहब ने क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से बस डिपो बन सकता है । हम ने कभी नहीं कहा कि किसी को शिफ्ट किया जाए । कैथल के बारे में हम ने कभी नहीं कहा कि उसे डिपो न रखा जाए । कुरुक्षेत्र में जिला हैडक्वार्टर होने के नाते, यूनिवर्सिटी

और एतिहासिक नगर होने के नाते बस डिपो बनाना बड़ा जरुरी है । वहां पर बाहर के यात्री भी आते हैं लेकिन केवल सब–डिपो होने के नाते वहां केवल 52 बसें हैं । वहां कि बसें भी अच्छी नहीं हैं । ये थोड़ी बसें हैं और ज्यादा भेजी जायें । कई बार यह भी कहा जाता है कि वहां पर जो डिपो बनेगा वह चल नहीं सकेगा । ऐसी बात नहीं है । उसके साथ शाहबाद और पेहवा को लगाया जा सकता हे या चाहे रादौर को सब–डिपो बना दिया जाए । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कुरुक्षेत्र को डिपो बनाया जाये । दूसरे हमारे शहर में बस स्टैन्ड बनना है । वहां पर नगर–पालिका और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का जमीन के बारे में झगड़ा है । वह जमीन एक महकमे से दूसरे महकमें को जानी है वह जमीन ट्रांसफर कराके वहां पर बस स्टैन्ड बनाया जाये । पीपली के बस स्टैन्ड को भी जल्दी ऐक्सटैन्ड किया जाये क्योंकि यहां आश्वासन भी दिया गया है कि उसे ऐक्सटैन्ड करेंगे ।

डिमान्ड नम्बर 24 टूरिज्म के बारे में है । मैं सरकार का बहुत ही धन्य– वादी हूं कि सरकार ने टूरिज्म के बारे में कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है । वहां पर काफी डिवैल्पमैंट की है । अभी कुछ दिन पहले सैंटर के मिनिस्टर श्री एच० के ० एल ० भक्त ने कृष्णधाम यात्री निवास का शिलान्यास किया था । 35 लाख रुपये से यह वाली निवास बनेगा । इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर एक यात्रिका की भी मंजूरी दे दी है ।

वह भी वहां बनेगी । इसके लिए मैं सरकार का बहुत ही धन्यवादी हूं ।

डिमान्ड नं ० 25 लोन ऐन्ड ऐडबान्सिज के बारे में है । सरकार की तरफ से तो लोन बडे. लिबरल तरीके से दिए जाते हैं । डी० आर ० डी० और दूसरी एजेन्सियां भी लोन देती हैं लेकिन मैंने पहले गवर्नर एड्रैस पर भी कहा था कि उन्हें बैकों से लोन लेने में बड़ी भारी दिक्कत आती है । इसलिए क् सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी एजेन्सी सरकार की हो जिसके थ्रू उन्हें लोन मिले क्योंकि बैंकों में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । सरकार की एजेन्सी के शू ही यह पैसा दिया जाये । बैंक वाले इतने नखरे करते हैं कि लोन लेने वाला आदमी दु:खी हो कर लोन लेना छोड़ ही देता है । इसलिए सरकारद्वारा कोई ऐसी एजेन्सी कायम. की जानी चाहिए जो इस बात कौ अमलीजामा पहना सके । इन शब्दों के साथ जो डिमान्डज हाउस के सामने रखी गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन की तरफ सरकार ध्यान देगी ।

श्री गिरी राज किशोर (हसनपुर–अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे टाईम दिया । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ डिमान्डज रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि उनकी ओर सरकार विशेष ध्यान देने का कष्ट करेगी और उन्हें अमलीजामा पहनायेगी । होडल

महाविद्यालय. की बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हालत में है इसलिए उस बिल्डिंग को दुबारा से बनवाया जाये । दूसरे वहां पर जगह भी बहुत कम है इसलिए वहां के लिए और जगह एक्वायर करने की भी आवश्यकता है । वहां से कागज ही नहीं चलते हैं जिसके कारण से देरी हो जाती है । वहां परजगह की इन्सपैक्शन हो चुकी है परन्तु ऐसा लगता है कि उसके पश्चात उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस पर आगामी कार्र– वाई की जाए । इसी प्रकार से बडौली गांब की स्कूल की बिल्डिंग भी बड़ी ही खस्ता हालत में है उसे भी बनवाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो । हसनपुर गर्ल्ज स्कूल में भी बहुत थोड़े कमरे हैं और बच्चे अधिक हें जिसके कारण बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम दो तीन कमरे और बनवाये जायें ताकि वहां पर बच्चों को कोई परेशानी न हो । हसनपुर में जमुना पुल की –भी अवश्यकता है । वहां पर जमुना पर पुल न बनने से लोगों को दिक्कत है । वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है । इसलिए जमुना पर अवश्य पुल बनाया जाना चाहिए । फिलहाल ड्रमों द्वारा कच्चा पुल बनवाया जाये ताकि लोगों को आने जाने में कुछ राहत मिले । खाम्भी गांव से जमुना पुल रहीमपुर तक रोड़ बनवायी जाये ताकि जो जमुना पर पुल बना है उसका फायदा होडल के इलाके के लोगों को हो सके । रायदासका से बमाडियाका तक सड़क की मंजूरी हो चुकी है । कई साल पहले तीन लाख साठ हजार रुपया जमा हो चुका है

लेकिन पता नहीं वहां पर किस वजह से काम शुरू नहीं किया गया है । मेहरबानी करके उस सड़क को बनवाया जाये ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके । इसके अलावा, रायदासका से बाता तक भी सड़क बनायी जाये । वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है इसलिए वहां पर सड़क का बनाया जाना बहुत ही आबश्यक है । भीडूकी से पेंच (यू० पी०) के लिए भी सड़क बनायी जाये ताकि वहां के लोग भी आ जा सकें । उन्हें भी काफी दिक्कत है । भीडूकी से बासवां गांव के लिए भी सड़क बनाई जानी बाहिर । दोनों गांव आस पास ही हैं । इनको काफी दूर के' रास्ते से आना पड़ता है । इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए केवल आधा किलोमीटर सड़क बनेगी । ऐसा करने से वहां के लोगों को बड़ा फायदा होगा । गढ़ी पट्टी होडल से लालपुर तक भी सड़क मिलाई जाये । वहां भी सड़क की बहुत ही सख्त जरूरत है । वहां बरसात में बहुत कीचड़ हो जाता है जिस की वजह से आना जाना भी बन्द हो जाता है । वहां पर गढ़ी पट्टी होडल से लालपुरा तक सडक बनायी जाये । इसके अलावा हसनपुर व होडल म्युनिस्पिल कमेटियों के लिये हरियाणा में सबसे कम पैसा दिया गया है । यह तो मैं नहीं कह सकता कि इसेका कारण क्ऊबा है लेकिन मैं इतना अवश्य कडु सकता हूं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा खस्ता हालत इन दोनों म्युनिस्पिल कमेटियों की है । इस दफा हसनपुर और होडल के लिये सी० एम० साहब, भी– काफी– पैसा वहां पर डिक्लेयर करके आये थे लेकिन वह पैसा भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है । मेहरबानी करके मुख्य मंत्री जी वहां पर उस पैसे

को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि वहां के लोगों की कुछ कंडीशन सुधर सके । गढ़ी पट्टी होडल में पानी खारी है । वहां पर अभी तक वाटर सप्लाई का कौई इन्तजाम नहीं है । मैंने देखा है यह इलाका किसी भी स्कीम में शामिल नहीं है । इसलिये मेहरबानी करके गढ़ी पट्टी होडल को भी वाटर सप्लाई स्कीम में शामिल किया जाये । हसनपुर क्षेत्र में आज भी कुछ खादर के गांव हैं । उन गांवों के लिये वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं बनाई गयी है । मैंने पद पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से इस बारे में बातचीत की तो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने यह बताया है कि वहां पर पानी मीठा है । यह बात तो सही है कि वहां पर पानी मीठा है लेकिन वहां पर पानी स्थल बहुत नीचा पड़ता है । वहां पर पानी इतना नीचा है कि पानी को खींचने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है । इसलिये मेरी आपसे यह अर्ज है कि खादर के इलाके में –भी वाटर सप्लाई की स्कीम को लागू किया जाये । होडल और हसनपुर में किसानों के लिये भी सिंचाई का कोई साधन नहों है । वहां पर हरक आगरा कैनाल जरुर गुजरती है लेकिन उससे हमें टाईम पर पानी नहीं मिलता । जब हमें पानी की जरूरत नहीं होती तो हमारे खेतों को पानी देकर बरबाद करती है । वहां पर जिन इलाकों में खारी पानी है, खास कर उन इलाकों में एम० आई० टी० सी० के टयूबवैल्ज लगवाये जायें या जो भी कोई दूसरे साधन हो सकें तो उनसे वहां पर पानी की सुविधा प्रदान की जाये । एस० वाई० एल० नहर को भी वहां तक पहुंचाया जाये ताकि वहाँ के पिछड़े हुए किसान भी हरियाणा के दूसरे किसानों के साथ मिलकर चल

सकें । एक बात और मैं कहना चाहता है कि हसनपुर में बस अड्डा नहीं है । वहां पर लोग धूप में और बरसात में खुले में खड़े रहते हैं । उनके लिये कोई सहारा नहीं है । वहां पर सवारियां बड़ी परेशान होती हैं । इसलिये वहां मैं एक बस–अडडा बनाने की मांग करता है । डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोएलने के लिये टाईम दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं ।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं केवल 2–3 डिमांड्ज पर ही बोलूगा । सबसे पहले मैं डिमांड नं० 24 जो टूरिजम की है, उसके ऊपर बोलना चाहूंगा । हमारे हरियाणा में टूरिस्ट काम्पलैक्सिज की एक बहुत बड़ी शृंखला बनी हुई है हमारा फतेहाबाद नैशनल हाई–वे नं० 10 पर है । वहां से मेन रोड भी निकलती है । कैथल से अम्बाला होते हुए वह सड़क चंडीगढ़ पहुंचती है । वह एक केन्द्र बिन्दु है लेकिन वहां पर आज तक भी कोई टूरिस्ट काम्पलैक्स नहीं बनाया गया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि फतेहाबाद में एक टूरिस्ट काम्पलैक्स जरूर बनाया जाए । इससे वहां के शहर की खूबसूरती बढ़ेगी और सरकार को आमदनी भी होगी इमके साथ ही वहां की जनता को भी सुविधा होगी ।

इसके बाद मैं डिमांड नं० 15 पर कुछ बोलूंगा । इरीगेशन के मसले के बारे में मैं विनती करूंगा कि फतेहाबाद में हमारी लाईफ लाईन फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी है जो भाखडा से

निकलती है । हमारी कौशिशों के बावजूद भी आज तक वह ठीक नहीं की जा सकी । इस डिखिब्यूटरी पर कई फाल्ज हैं । अगर उन फाल्क को पक्का करके खत्म कर दिया जाए तो इससे इसका बैड ऊंचा हो जाएगा जिससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई ठीक प्रकार से हो सकेगी । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए और उन फाल्ज को, जो इसमें हैं, खत्म किया जाए । इसके अतिरिक्त एक और स्कीम सरकार के विचाराधीन है कि सिरसा मेजर बडौपल के प्यायंट से एक नहर निकाली जानी है जो सीधी फतेहावाद के साथ जाकर मिलेगी । एक तो इससे अधिक भूमि की सिंचाई होगी और दूसरे जो हमारे वाटर वर्क्स सूखे पड़े हैं और जिनमें पानी की कमी रहती है, इस नई स्कीम से हुमारे वाटर वर्क्स को भी पानी मिल सकेगा और इनमें पानी की कमी नहीं रहेगी । शहर के लिए इससे सुविधा हो जायेगी । इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस स्कीम को जो हमारे यहां से केवल 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक भी ऐक्सटैडं कर दिया जाएगा । एक और स्कीम है न्यू घागड माईनर । वह भी कई साल से पैंडिग पड़ी हुई है । इस माईनर से जो सिरसा मेजर बडौपल के प्वायंट से निकलनी है, हजारों एकड़ भूमि की आबपाशी हो सकेगी और इसके बनने से किसान आपको दुआएं देंगे । इस बारे में मैंने पीछे भी अर्ज किया था कि वहां पर फतेहाबाद में ट्रांसफार्मर्ज की बहुत कमी है । इसके अलावा, वहां पर छोटे–छोटे सामान की भी कमी है । हालाँकि हरियाणा सरकार इस बारे में काफी हिम्मत कर रही है लेकिन इरीगेशन फैसिलिटीज

बढ़ाने में और लोगों को पावर देने में ट्रांसफार्मर्ज की कमी पेश आ रही है । सरकार ने लोगों को पावर देने के लिए थर्मल प्लांट्स इम्प्रूव किये हैं और न जाने कितने ही सबनटेशन बनाए हैं लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वैस्ट अपनी सरकार से है । मैं सुरजेवाला साहब, जो हमारे आई० पी० एम० भी हैं से प्रार्थना करूंगा कि फतेहाबाद में कम से कम 30 ट्रांसफार्मर्ज और दूसरे जिस भी सामान की कमी है, बह वहां पर मुहैया किया जाए ताकि किसानों को कुछ सहारा मिल सके और लोगों का भला हो सके । फतेहाबाद में ट्यूबवैल्ज का नम्बर बहुत अधिक है । इसके अतिरिक्त मैं एक और अर्ज डिमांड नं० 3 जो होम के बारे में है, करना चाहूंगा । मैंने कल एक काल अटैशन मोशन भी दिया था लेकिन किसी वजह से वह मंजूर नहीं हो सका । कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि तीन उग्रवादी पकड़े गए । यह हिम्मत हमारी पुलिस की है । उनसे कई और चीजें निकली हैं और पता लगा है कि हरियाणा में घुसने के लिए और भी कई तैयार बैठे हैं । इसलिए मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि सरकार को ऐसे कर्मचारियों को उत्साहित करना चाहिए जिन्होंने यह हिम्मत का काम किया है । इन तीन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए जिन अफसरों और कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई है, उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनको मैडल देकर उत्साहित किया जाना चाहिए । इसके अलावा, मेरा कहना यह भी है कि इस डिमांड में पुलिस के लिए जो भी सरकार देना चाहती है और जो भी कमियां महसूस करती है, चाहे वे उनके लिए मकानों की है या उनके लिए

जीपों की है, उनको पूरा करके सरकार द्वारा उनकी हिम्मत को बढ़ाया जाए । मैं यह आशा करूंगा कि हमारे लिए और बी० आई० पीज० के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है उसकी ओर सरकार ज्यादा ध्यान देकर निगरानी करेंगी । वैसे तो मुख्य मन्त्री महोदय अब भी बहुत अधिक इस तरफ ध्यान दे रहे हैं लेंकिन मेरी प्रार्थना है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए जिससे कि कोई अनहोनी घटना न घट जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मांग नम्बर 18 के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा उद्योगों के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है लेकिन मेरे हल्के फतेहाबाद में उद्योग की कमी है । मेरे इलाके में कौटन और धान काफी मिकदार में होता हे । वहां पर कौटन इतना अधिक हे कि सिरसा के बाद फतेहाबाद का दूसरा नम्बर आता है । वहां पर दो फैक्टरी लगाने की काफी गुंजाईश है । एक तो वहां पर कौटन मिल लगाई जा सकती है और दूसरे राइस शैलर की काफी गुंजाइस हए । मेरा प्रार्थना है कि इन दोनों में से एक पर अवश्य ध्यान दिया जाए । इससे वहां के किसान सुखी होंगें और फतेहाबाद की तरक्की होगी ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं समाज कल्याण और पुनर्वास के बारे में कहना चाहता हूं । यह बात ठीक है कि इसके लिए बहुत अनुदान दिया जा रहा है । गरीबों, विधवाओं, अंगहीनों और डैस्टीच्यूट्स की काफी मदद की जा रही है लेकिन मदद देने

क्य जो तरीका है वह इतना डिफिकल्ट है कि लोग काफी परेशान हो जाते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास मिसालें है कि लोगों को फार्म्ज मिलने में सालों लग जाते है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अंगहीनों, विधवाओं और डैस्टीच्यूट्स को पहले तो फार्म्ज ही नहीं मिलेंगे और अगर दौड़ धूप करके फार्म्ज मिल भी गए तो कई लोगों के दस्तखत कराने में उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । दस्तखत होने के बाद वे कागज डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं । वहां से उन पर एतराज लगकर आ जाता है । इन लोगों को फिर दौड़ना पड़ता है । वे औबजैक्शंज दूर कराने के बाद फार्म्ज फिर दुबारा जाते हैं । उसके बाद वे फार्म्ज हरियाणा सौशल वैलफेयर डिपार्टमैंट में जाते हैं । कई बार यहां पर उन पर औबजैक्शन लग जाता है । इस तरह से सालों साल खराब हो जाते हैं । मेरा कहना यह है कि इन विधवाओं, अंगहीनों और डैस्टीच्यूटस तथा बूढ़ों की मदद करने का कोई मुख्तिसर तरीका अपनाया जाए ताकि उनको यह राशि जल्दी मिल सके । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर पैन्शन मन्जूर भी हो जाती है तो 'उनको राशि पहुंचने में सालों लग जाते हैं । कभी तीन महीने की पैन्शन छः महीने में पहुंचती है । इससे उनको बडी परेशानी होती है । इसलिए प्रोसीजर को ब्रीफ किया जाए ताकि उनको जो मदद दी जानी है वह जल्दी मिल सके । (घंटी) । अच्छा जी । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

मास्टर राम सिंह (रादौर–अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डिमान्डज पर बोलने का समय दिया । मैं सब से पहले डिमान्ड नम्बर 9 जो ऐजुकेशन की है उस पर बोलूंगा । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त हर क्षेत्र में हर लिहाज से तरक्की कर रहा है और वह ऐजूकेशन में तरक्की कर रहा है लेकिन बहुत सी जगह प्राईमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है । आज स्कूलों के अन्दर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है । देखने में आया है कि कई स्कूलों में बच्चे तो दो सौ या अढ़ाई सौ हैं और अध्यापक एक या दो ही हैं । मेरी प्रार्थना है कि बच्चों के मुताबिक अध्यापक बढ़ाए जाएं । दूसरी बात यह है कि वहुत सीरू' जगह जहां प्राईमरी स्कूल्ज हैं वहां पर बिल्डिंग उपलब्ध नहीं होती । स्कूलों के लिए बिल्डिग उपलब्ध कराई जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में चौबीस जगह प्राईमरी स्कूल खुले हुए हैं लेकिन इन जगहों पर औबेल्डिंग उपलब्ध न होने के कारण बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं और इस कारण से अध्यापक परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हें । कभी बारिश हो जाती हे और कभी धूप पड़ती हे । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस डिमान्ड में जो पैसा रखा गया है उसका ज्यादा इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में किया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगली डिमान्ड नम्बर दस है जो पब्लिक हैल्थ के बारे में है । मेरे एरिया के अन्दर और खासतौर पर खादर के एरिया के अन्दर पीने का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत

खराब है और वह इतना खराब है कि भगवानपुर गांव में इस पानी से कई बार मौतें हो चुकी हैं । मैंने इस बारे में लिखकर भी दिया था कि वहां पर वाटर वर्क्त बनाया जाए । वहां पर भगवानगढ, भगवानपुर रपडी और रतनगढ गावों का एक कलस्टर है इसलिए वहां पर वाटरवर्क्स का प्रबन्ध किया जाए ताकि वहा के लोगों का जीवन बसर हो सके । हमारी स्टेट में पब्लिक हैल्थ का काम काफी मिकदार में हुआ है और हो रहा है लेकिन मेरे हल्के रादौर में इस डिपार्टमैंट का काम बहुत कम हुआ है । मैंने लिखकर दिया था कि सुलतानपुर, लखमडी और पोटली में पानी का इन्तजाम किया जाए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है । यहां पर वाटर बर्क्स की बहुत जरूरत है और जितनी जल्दी यह वहां पर लग जाएगा उतने ही वहां के लोग धन्यवादी होंगे ।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 13 सोशल वैलफेयर की है । इसमें बूढ़े आदमियों, अपगों तथा विधवाओं को पैन्शन दी जाती है । डिप्टी स्पीकर साहब, जिन लोगों को पैन्शन मिलती है उनको समय पर नहीं मिलती । कई बार देखने में आया है कि पैन्शन मांगते–माँगते लोगों की मौत हो जाती है । बाद में पता लगता है कि कई साल तक पैन्शन नहीं मिली । मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि बुजुर्ग लोगों को जब भी सहायता की जरूरत हो तो फौरन ही उसका इन्तजाम किया जाए ताकि उनको सरकार द्वारा दी गई सहायता का उचित लाभ मिल सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ट्रांस्पोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे हल्के में ऐसी सडकें हैं जहां एक–एक सड़क पर बारह–तेरह गांव आते हैं लेकिन बस सर्विस नहीं है । वहां पर बस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है । सड़क तथा पुल बिल्कुल कम्पलीट हैं लेकिन बस नहीं है। मैंने जी० एम० कैथल को लिखकर दे रखा है लेकिन उन्होंने अब तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है । डिप्टी स्पीकर साहब, मुसतफाबाद, बडतौला, मुबाखेडी, रामनगर, बलोलपुर और लाडवा इन सड्कों पर कोई बस नहीं चलाई गई है । ये सड़क कम्पलीट हैं । मेरी प्रार्थना है कि यहां पर बस चलाई जानी चाहिए जिससे कि इन सड्कों के पास जो रहने वाले हैं उनको लाभ हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे हल्के के अन्दर बहुत से गांव ऐसे हैं जहां सब सैन्टर्ज की बिल्डिंग नहीं है । जो सब सैन्टर्ज चल रहे हैं. वे प्राईवेट घरों में चल रहे हैं । सैन्टर की बिल्डिंग न होने के कारण ए० एन० एम० वहां नहीं ठहरती । वह अपने घर चली जाती है । इस कारण वह गांव के मरीजों की रात को देखभाल नहीं कर सकती और उसका लाभ गांव के लोगों को पूरा नहीं मिलता । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मेरे हल्के में हैल्थ सब–सैन्टर्ज की बिल्डिग्ज बनाई जाएं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री ए० सी ० चौधरी (फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं डिमांड नम्बर 8 पर बोलूं गा । मेरे हल्के फरीदाबाद टाऊनशिप के साथ 30 देहात लगते हैं और वे इस तरह की लोकेशन में हैं जहां आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है । कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं और सड़कें न होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत है । आज भी वे सडकें फंडज या दूसरी वजुहात की वजह से रुकी हुई हैं । खास– तौर पर जो गांव जैसा कि नगला गुजरा वगैरह–वगैरह शहर के साथ लगते हैं और जो छोटे–छोटे देहात हैं जिनका शहर के साथ रोजमर्रा का वास्ता रहता है, इन गांवों की सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और इन गांवों को बड़ी सड़कों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि देहात. के लोगों को आने जाने में असुविधा न हो ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 9 के बारे में जोकि शिक्षा से सम्बन्धित है अपने विचार रखना चाहूंगा । शिक्षा का विस्तार देश के लिए बड़ा आवश्यक है और खासतौर से उन इंडस्ट्रीयल टाऊनशिपस में जहां पर कि झुग्गी झोपड़ियों की बरसात है । वहां रहने वाले लोग वैसे ही आम सुविधाओं से वंचित रहते हैं लेकिन इसके साथ ही वहां पर शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि शिक्षा के लिए प्रदेश में जो पैसा एलोकेट किया गया है उसमें से फरीदाबाद टाऊनशिप की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के

बच्चों के लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया जाए । साथ–साथ कुछ और बस्तियां हैं–जैसे कि जवाहर बस्ती, बबुआ व पंजाबी कालोनीज आदि जिनकी आबादी 40 हजार से 60 हजार तक की ईय वहां पर भी सरकारी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है । मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि इन इलाकों को भी शिक्षा के लिए कंसिडर किया जाए । इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहूंगा कि शहरों के साथ–साथ देहातों में भी जहां पर स्कूलों की हालत खस्ता है, वहां पर शिक्षा का खूब विस्तार होना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, देहातों में तो पहले ही बच्चे अशिक्षित होते हैं और अगर वहां पर स्कूलों का प्रबन्ध न किया गया, शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध न किया जाएगा तो बच्चों का रुझान शिक्षा की तरफ से हट जाएगा जिससे कि भारत का भविष्य अन्धकार में पड़ जाएगा । इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है कि कम से कम मेरे हल्के के अन्दर जो देहात शहरों से दूर–दूर हैं और जहां पर शिक्षा की सहूलियतें उपलब्ध नहीं हैं वहां शिक्षा के लिए हर प्रकार की सहूलियतें मुहैया की जाएं । सिटी में जो स्कूल है उसको 10+2 में तबदील कर दिया जाए । लडकियों के स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जाए । इसके साथ–साथ मैं यह भी कहूंगा कि स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत बहुत ही खस्ता है । बैठने को जगह नहीं है । स्कूलों में अलग–अलग हैडज के लिए फण्डज तो अवेलेबल हैं लेकिन उन फण्डज को रिलीज करने में बहुत सारी अडचने हैँ और कोई मास्टर या हैडमास्टर इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले पाते क्योंकि वे समझते हैं कि अगर उन्होंने फण्डज को कहीं खर्च जिया तो

उनके खिलाफ ऐक्शन होगा । अतरू सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हो सके और हमारे बच्चे अच्छी व सही शिक्षा पा सकें ।

इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माँग नम्बर 10 जोकि मैडिकल व पब्लिक हैल्थ से सम्बन्धित है, पर अपने विचार रखूंगा । जिला फरीदाबाद में बड़ी देर से एकमात्र सिविल हस्पताल बादशाह खां के नाम से चला आ रहा है और 1948 से लेकर, जब से वह बना था, उसमें कोई भी बढ़ौतरी नहीं की गई है । दिनों दिन उस हस्पताल की हालत और खस्ता होती जा रही है और इस हालत का एहसास करते हुए सरकार ने 1980–8 1 में हस्पताल की एक नई बिल्डिंग का फाऊंडेशन स्टोन रखा था लेकिन आज तक वह फाऊंडेशन स्टोन वहीं का वहीं है और कुछ नहीं है । तो मैं सरकार से यह आग्रह करुंगा कि उस हस्पताल को प्रायरिटी दी जाए क्योंकि सारे जिला में केवल वही एक हस्पताल होने के कारण वहां बहुत रश रहता है । इससे पहले वहां पर सिविल डिसपैसरी थी लेकिन जब से ऐम्पलाईज इंशोरेस स्कीम लागू हुई है तब से वह डिसपैंसरी बन्द कर दी गई कुए और वे लोग जो इस स्कीम के अन्डर कवर्ड नहीं हैं उनकी हालत खराब है और वे लोग प्राईवेट डाक्टरों के रहमो कर्म पर ही रहते हैं । अगर एक आदमी एक महीने के लिए बीमार पड़ जाता है तो उसकी फैमिली महीना भर के लिए बैकवर्ड हो जाती है ।

इससे आगे अब मैं डिमांड नम्बर 11 व 12 जोकि अर्बन डिवैल्पमैंट और लेबर एंड इंम्पलायमैंट के बारे में है, पर अपने विचार व्यक्त करूंगा । मेरा हल्का इंड स्ट्रीयल टाऊनशिप है और अर्बन डिवैल्पमेंट के मामले में वह काफी पिछड़ा हुआ है । अर्बन डिवैल्पमैंट का मतलब हुड्डा नहीं होना चाहिए उसमें लोकल बाडीज भी शामिल होनी चाहिए और इसमें सलम क्लीयरैन्स के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है । 35 हजार के लगभग मेरे हल्के में झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं । आप अन्दा जा लगा सकते हैं कि 35 हजार झुग्गी झोपडियो वाले लोगों के लिए लोकल बाडीज का कोई भी साधन समर्थ नहीं होगा । इस आग्रह के साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि अर्बन डिवैल्पमेंट में रखा हुआ पैसा किसी भी हा लत में हरियाणा की सभी 82 म्युनिसिपल कमेटियों को कवर नहीं कर सकेगा । फरीदाबाद जो कम्पलैक्स है, यहां पर लोगों की मुश्किलातों को देखते हूए मैं यह कहूंगा कि वहां बहुत पैसे की आवश्यकता है । फरीदाबाद में पौल्यूशन बहुत है । इंडस्ट्रीज की वजह से एयर पौल्यूशन है । इसके लिए ठीक इन्तजाम होना चाहिए और इस काम को सही करने के लिए करोड़ों रुपये की आवश्यकता होगी । लेबर के लिए हाउसिंग स्कीम के लिए करोड़ों रु एवा चाहिए । इसके इलावा यदि स्लम एरियाज को क्लीयर करना हो तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी । फरीदाबाद टाउनी शप का सीवरेज सिस्टम जो है उसकी मियाद खत्म हो चुकी है । उसको रेनोवेट करने के लिए करोड़ों तो क्या अरबों रुपए की आवश्यकता हीगी और ऐसा करना

सरकार के सामर्थ्य में नहीं होगा क्योंकि एक शहर को डवैल्प करके बाकी जगहों को इग्नौर नहीं किया जा सकता । ऐसा करना सरकार के बस का रोग नहीं होगा । तो मैं सरकार से आग्रह करूं गा कि जिस तरीके से, दिल्ली डिवैल्पमैंट अथारिटी, यू ० पी ० में गाजियाबाद डिवैल्पमैंट अथारिटी बनी हुई है उसी तरह से फरीदाबाद कम्पलैस के अन्दर जो तीन शहर फरीदाबाद टाऊनशिप । बल्लभगढ और नेवला महाराजपुर हैं तथा उसके साथ लगते हुए देहात हैं, उनकी डिवैल्पमैंट के लिए एक कंपैक्ट डिवैल्पमैंट अथारिटीज बना दी जाए जिसका नाम फरीदाबाद डिवैल्पमैंट अथारिटी रख दिया जाए और उसकी डिसपोजल पर गाजियाबाद के पैटर्न पर अगर पैसा दे दिया जाए तो मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हू कि न सिर्फ यह एक बेहतरीन तजुर्बा होगा बल्कि हरियाणा को एक नई दिशा दे गा । डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी मानते हैं कि गांव देश की आत्मा और शहर देश का शरीर हैं और शहरों की खूबसूरती से देश की खूबसूरती बढ्ती है । डिप्टी स्पीकर साहब, फरीदाबाद टाउनशिप एक इंडस्ट्रीयल टाउन है । वहां पर मजदूर दूर दूर से आकर रहते हैं और वे ज्यादा किराया भी नहीं दे पाते जिनके कारण' से वहां पर स्लम्ज बढ्ती जा रही है । इस बात को मदेनजर रखते हुए वहां पर एक कम्पैक्ट अथारिटी चाहिये । मैंने पहले कहा कि वहां हुड्डा भी मौजूद है, कम्पलैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन भी है, जिला ऐडमिनिस्ट्रेशन भी है लेकिन उन सब की नाक के नीचे सरकार की कानूनी खामियों की वजह से स्लम्ज बढ़ते जा रहे हैं । तो मेरा आग्रह है

कि इस तरह के काम को सबसे पहले प्रायरिटी दी जाए ताकि लोग गन्दगी के कारण बीमारियों के शिकार न हो सकें ।

अब मैं डिमांड नम्बर 13, जोकि सोशल वैलफेयर विभाग व रिहैवलीटेशन से सम्बन्धित है, पर बोलूंगा । मेरे हल्का में भी दो विडोज होम हैं । बदकिस्मती की बात हे कि सन 1948 में जिन लोगों ने प्राण की आहुति दी उनकी विधवाओं और बच्चों के लिए विडो होमज बने हुए हैं लेकिन उन विडो होमज की आज तक सेन्टर गवर्नमैंट से स्टेट गवर्नमैंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकी जिसके कारण आज वे विडोज होम स्लम्क से भी बदतर हो रहे हैं । उनमें कोई सिविक अमैनीटीज नहीं दी जा रही हैं जबकि इसके लिए सन 1960 से लगातार आग्रह किया जा रहा हे । तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विडो होमज को इमीजीऐटली ट्रांसफर करके लोकल बाडीज को दे दिया जगर और जिन विडो होमज की अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है उनको डायरेक्ट लोकल बाडीज को देकर के सरकार वहां पर दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराके स्वयं इस काम से विमुक्त हो जाए । इसके इलावा एक और बात मैं कहूंगा कि जो ओल्ड ऐज पैन्शन मिलती है वह इनसफीशीऐन्ट है और जिस तरीके से वह देरी से मिल रही है उसकी ओर सरकार ध्यान दे क्योंकि गरीब आदमी आंखें बिछाये हर बार अपने पैसों की इन्तजार में रहते हैं । इसके लिए सरकार कोई ऐसी नियमित नीति अपनाये ताकि पैन्शनर्ज को वहां के लोकल पोस्ट आफिस द्वारा या डी ० सी साहब के द्वारा या फिर

स्टेट बैंक द्वारा ही भुगतान हो जाया करे जिससे किसी भी गरीब ओल्ड विडोज को इसके लिए बार बार न भागना पड़े । यह पैन्शन हर महीने की 7 या 10 तारीख को मिल जानी चाहिये और साथ साथ इसकी राशि में कुछ बढ़ोतरी भी होनी चाहिए । एक ओर मांग फ्रीडम फाईटर्ज की भी थी कि सरकार की तरफ से उन्हें फ्री बस पास दिया जाए । मैं आग्रह करूंगा कि इसका भी प्रावधान जल्द किया जाए ताकि उन को फायदा हो सके ।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 14 जोकि फूड एण्ड सिविल सप्लाई से सम्बन्धित है, पर अपने विचार रखूंगा । मैं मजदूरों के लिये यह मांग करूंगा कि उन्हें सबसिडाईजड राशन दिया जाप । जो राशन कार्ड आज बने हुए है उन पर फी व्यक्ति एक कार्ड पर चार सौ ग्राम चीनी मिलती है । इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए । जितने भी राशन कार्डज हैं उन्हे नार्मज के अनुसार राशन दिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । कार्डज ज्यादा हैं ऐलोकेशन कम है । लगभग चार सौ ग्राम की बजाए तीन सौ या साढ़े तीन सौ ग्राम चीनी एक आदमी को दी जाती हे । इस तरह की कटौती तो पब्लिक के साथ एक तरह का मजाक ही है । इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने राशन कार्डज हों उनको सैट किए गए नामर्ज के अनुसार ही राशन दिया जाए । किसी प्रकार की कटौती न की जाए । अगली आइटम डिमांड नं० 15 हे, जो इरीगेशन की है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कई बार इसी फोरम से सरकार से आग्रह किया था कि कोटबन्ध मेरे हलके से

बाहर पहाड़ की तरफ है । जब भी बारिश आती है तो पहाड़ का ओवर फलोड पानी जल्दी छोड़ दिया जाता है ताकि बन्ध टूटे नहीं । वह सारा पानी जतोपुर और बीजोपुर गांवों को समैश कर देता है और फसलों को भी तबाह कर देती है । हर बार सरकार ने वायदा किया है कि इस पानी को नाला खो. कर आगे डिस्पोज आफ करेंगे लेकिन अभी टक वह नहीं हुआ । ऊपर सरकार से तो स्कीम बन कर आ चुकी है लेकिन उसकी इम्पलीमैंटेशन नहीं हुई । मैं आशा करता हूं कि इस बारिश से पहले पहले सरकार इस बारे में गौर करेगी । इसके अलावा, इंडस्ट्रीज की हालत फरीदाबाद में बहुत खस्ता है । आज जिन लोगों ने इंडस्ट्री पर पैसा लगाया है वे बैकों को इन्टैरस्ट की इंस्टालमैंट भी नहीं दे सकते । अन–एम्पलायमैंट बड़े जोर पर है क्योंकि बिजली नहीं है । हमारा सरकर से नम्र आग्रह है कि सरकार जो भी काम कर रही है उस पर मैं डि प्यूट नहीं करता, अच्छे तरीके से इसकी देखभाल कर ली जाए लेकिन इसका हल यहां के साधन नहीं होंगे । उसके लिए एटोमिक पावर ही एक माल हल है । जब एटोमिक पावर का ग्रिड आपके राजस्थान में जयपुर तक पहुंच चुका है इसलिये अगर सरकार थोड़ा सा भी प्रयत्न करे तो यह हरियाणा की तरक्की को चार चान्द लगाएगा । इसलिये सरकार इस बारे में भी विचार करे कि इसे कैसे किया जा सकता है ।

डिमांड नं० 18 एनीमल हसबैंडरीं की है । उसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि किसान के पास जमीन के बाद

अगर कोई धन है तो वह पशु धन है । उसके लिए मेरे 30 देहात बड़ी औड लोकेशन पर हैं, शहर से तीस किलोमीटर दूर हैं और वहां कोई भी अच्छे डग की एनीमल डिसपैंसरी या हस्पताल नहीं है मैंने जमीन का भी रैजोल्यूशन भिजवा दिया है खास कर जतोपुर और फतेहपुर सजा का भी । मैं आग्रह करूंगा कि इसे भी तेजी से –लागू किया जाए और वहां के लोगों को राहत दी जाए ।

डिमांड नं ० 19 फिशरीज की है, बड़ी अच्छी वाह– है । लेकिन मैं सरकार का ध्यानाकर्षण करूंगा कि वह फिशरीज को प्रोत्साहन तो दे रही है लेकिन फिशरीज के लिए जब लोग ट्युबवैल्ज का कनैकशन मांगते हैं तो उसके लिए सबसिडी डिनाई की जाती है । डिप्टी स्पीकर साहब, एक गरीब जो फिशरीज का काम करेगा तो उसे ट्यूबवैल पर सबसिडी उसी तरह से दी जाए जैसे देहात में दूसरे ट्यूबवैल्ज को दी जाती है । यह उसका हक बनता है इसीलिये इस पर सरकार गौर करे । इसके साथ ही जहाँ कैनाल का पानी है वहाँ फिशरी के लिए पानी का कनैकशन तक अलाउ नहीं किया जाता । तो मैं आग्रह करूंगा, फिशरीज को प्रोत्साहन देने के लिए तेजी से ये बातें लागू की जाएं । डिमांड नं 20 फारेस्ट की है । इस बारे में मैं एक ही आग्रह करूंगा कि इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स से पोल्यूशन जोरों पर है और पोल्यूशन को नयूट्रेलाइज करंने के लिए दरख्त ही एक माल साधन हैं । इसलिये फरीदाबाद कम्पलैक्स में और फरीदाबाद जिले में तो खास

तौर पर सरकार अपने तौर पर दरख्त लगवाए, लोकल बौडी पर यह काम न छोड़े । भले ही उनसे साथ साथ कोआर्डिनेशन करवा ले लेकिन इसकी बहुत जरूरत है ।

डिमांड नं० 21 कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट की है । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बना कर मेवों की दुर्दशा सुधारने के लिए बहुत बेहतरीन कदम लिए हैं लेकिन इस स्कीम को केवल मेवात के एरिया तक, जिला गुड़गांव तक सीमित रखा गया है जबकि मेव गांव और भी हैं जोकि आज फरीदाबाद जिले का हिस्सा है जैसे जतोपुर, विजोपुर, लदियापुर, फतेहपुर सजा, गादल पुर और खडौली । इन गांवों में भी वह स्कीम लागु कर दी जाए क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेव गांव हैं इनके अलावा और कोई पापुलेशन वहां नहीं है ।

डिमांड नं 9 22 कोआप्रेशन की हए । मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हाउसिंग स्कीम के लिए कोआप्रेटिव बेसिज पर बहुत सारी स्कीमें हैं । लीडर आफ दि हाउस की इस बारे में अश्योरैंस भी है कि आप कोआप्रेटिव बनाए, हम यह काम करवा देगे । इस काम के लिए मैं चाहता हूं कि कोआप्रेशन डिपार्टमैंट पूरी तरह से हमारी हैल्प के लिए आए । वह कोआप्रेटिव सोसाइटीज की फौरमेशन में और आफिशियल पेपर फिल करने में मदद दे । मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फरीदाबाद जिले के जो स्लमज हैं वह कोआप्रेशन डिपार्टमैंट के सहयोग से बहुत जल्द सुधारे जा सकते हैं और वहां एक नई दिशा दी जा सकती है ।

डिमाँड नं ० 23 ट्रांसपोर्ट की है । मैं हैरान हूं कि हर जगह 12, 18 और 20 बेज का बस अड्डा बनता है लेकिन फरीदाबाद टाउनशिप से हर पाँच मिनट के बाद एक बस चलती है और मेरा ख्याल है कि 500 बसें रोज चलती होंगी, वहां पर भी अच्छा बस अड्डा बनाया जाए । इसके अलावा मेरी माँग है फरीदाबाद में यू ०पी ०, राजस्थान और पंजाब से आए लाखों मजदूर मुरहतलिफ फैक्ट्रियों में काम करते हैं लेकिन उनके लिए बस रुट के हिसाब. से कनबेएंस का कोई साधन मुहैया नहीं किया गया है । मेरी रिकवैस्ट है कि यहू सुबिधा भी वहाँ दी जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, साढ़े तीन साल से मैं माँग कर रहा हूं कि वहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए बसें चलाई जाएं लेकिन अब तक उस पर कोई असर नहीं हुआ है । एक बार बस चलाई थी तो वह वाया सोनीपत चलाई थी जिसमें आम हालत से तीन घंटे ज्यादा लगते थे और साथ ही 10– 11 रुपए किराया भी फालतू था । तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जहाँ आपने ट्राँसपोर्ट को एक नई दिशा दी है वहाँ फरीदाबाद हल्के की भी इन जरूरी डिमाँडज पर ध्यान देकर इनको लागू करें । फरीदाबाद, बल्लभगढ, सैक्टर्ज और सिटी ये चार ऐसे कम्पोनैटंस हैं जो बेसिकली एक हैं लेकिन इनका डिस्टैस इतना ज्यादा है कि आम आदमी के बस की बात नही हए कि वह रिक्शा रेहडे पर चल सके । तो मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगा कि फरीदाबाद, बल्लभगढ, सिटी और सैक्टर्ज के लिए भी एक इन्टर्नल बस सर्विस चला दी जाए ताकि लोगों का दुख सुख में आना जाना हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सभी डिमांडज का समर्थन करता हूं ।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं डिमांड नं० 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 17 और 23 पर बोलूंगा । डिमांड नं ० 2 जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है । मैंने पहले भी सप्लीमैंटरी डिमांडज पर बोलते हुए जिक्र किया था कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला सब से जरूरी बात है । जो लोग सर्विस में हैं जैसे अफसर हैं, क्लर्क हैं, पुलिस अफसर हैं और छोटी पोस्टों पर काम करते हैं । वे सब इस में आ जाते हैं । जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी के साथ जुडा हुआ है । इसके काम को आसान करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए । आज के वक्त में जहां कम्पयूटर का जमाना है तो हर महकमे को कम्पयुटर की हैल्प लेनी चाहिए इस से लोगों का काम आसान हो जाएगा । आज क्या होता है कि एक आदमी कोई दर्खास्त देता है तो तीन दिन तक तो उसकी पड़ताल ही नहीं होती । वह एलीकेशन दस जगहों पर घूमती है । क्यों नहीं एक जगह पर ही उसका फैसला हो जाए । जब तक ऐडमिनिस्टेरशन में लोगों की सर्विस करने की भावना नहीं आएगी उस वक्त तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगाय मैंने पीछे कहा था कि रैवेन्यू डिपार्टमैंट में आनरेरी तहसील– दारों का प्रावधान किया जाए । लोग उसके पास जाएं और अपनी रजिस्ट्री करवा कर आ जाएं ।

यह बड़ा सिम्पल काम है । गवर्नमैंट की हिदायत है कि रैवेन्यू डिपार्टमैंट के थ्रू रैड क्रास की टिकटें नहीं काटी जाएगी लेकिन फिर भी काटी जा रही हैं । इसी तरह से होम डिपार्टमैंट की शत है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण महकमा है । थानों में जो सिपाही और थाने– दार हैं और फील्ड में काम करने वाले इन्सपैक्टर्ज हैं उन के पास बहुत ज्यादा काम–होता हे । उनको सुबह से शाम तक डियूटी देनी पड़ती है । इनके काम करने की परम्परा बहुत पुरानी है जोकि अंग्रेजों के टाईम से चली आ रही है । पुलिस के प्रति लोगों की और लोगों के प्रति पुलिस की एक दोस्त की तरह भावना होनी चाहिए । इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के सौ–सौ रुपए बढ़ाए गए हैं मैडिकल अलाउंस के नाम पर उसी ढंग से गवर्नमैंट पुलिसमैन को भी ज्यादा से ज्यादा तनखाह दे' । इसके लिए गवर्नमैंट को चाहे कितने भी टैक्स क्यों न लगाने पड़े लेकिन जो लोग थानों में लगे हुए हैं उनको अच्छी तनखाह दी जाए । इसके अलावा जो लड़के आज बेरोजगार हें । उनमें से कई ग्रेजुएट लड़के पुलिस में भर्ती हो रहे हैं । जो पुराने सिपाही हैं उनको आरम्ड पुलिस में या कहीं और लगाया जा सकता है इस बारे में सरकार ध्यान दे । इसके चाद डिमांड नम्बर 8 बिल्डिग्ज एंड रोडज के बारे में हे । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी कांस्टिचुऐंसी ऐसी कांस्टिचुऐंसी है जिसका क्षेत्रफल 77 किलोमीटर है । अम्बाला कैंट के पास नीचे जा कर एक पिलखनी गांव है । इसके बाद जगाधरी रोड आएगी फिर जी० टी ० रोड आएगा उसके बाद हिसार रोड आएगा और

इस्माइलाबाद से आगे जाकर एक दानीपुर गांव हे वहां तक का डिस्टैंस निकाला जाए तो 77 किलोमीटर का क्षेत्रफल बनता है । हरियाणा में जितने भी नदियां नाले निकलते हैं वे सभी मेरे हल्के से हो कर निकलते हैं । उन नदी नालों पर पुलों की बडी भारी कमी है । मेरा हल्का काफी कटाफटा है । रोडज तो बन रही हें लेकिन मेरे हल्के में कई ऐसी सड़के हैं जैसे जलबेडा सै उगाडा के लिए जो रोड है अगर उस रोड से जलबेडा से अम्बाला कैट आना हो तो पहले अम्बाला शहर जाना पड़ेगा फिर अम्बाला कैट जा सकते हैं । इसी तरह से यदि एहमों गांव से अम्बाला शहर आना हो तो पहले हिसार रोड पर जाना पड़ेगा फिर अम्बाला शहर आ सकते हैं । यदि एहमों से सुलर तक सड़क बना दी जाए तो उससे एहमों से अम्बाला शहर आने के लिए सीधा रास्ता हो जाता है और वह सिर्फ एक किलोमीटर का डिस्टैंस है । इसी तरह से जलबेडा से उगाडा तक रोड बना दी जाए तो 10– 15 किलोमीटर का डिस्टैस बचता है । मेरे हल्के में एक बडोली गांव है वहां पर एक नाले पर छोटा सा पुल बनना है । वह पुल न बनने के कारण बरसात के दिनों में वह गांव शहर से तीन महीने के लिए लगातार कट जाता है । उस पुल का चार पांच लाख रुपए का ऐस्टीमेट सैंक्शन हो चुका है लेकिन अभी तक उसको बनाने के लिए काम शुरू नहीं किया गया है । बरसात के दिनों में सारा क्षेत्र उस गाँव से कट जाता है इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करुंगा कि उस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए । इसी. तरह से जी०टी० रोड़ पर मोहडा गांव के पास एक फडौली गाँव है । वह गांव

मोहडा गांव की पंचायत में पड़ता है । लेकिन उन गाँवों के बीच में एक नाला पड़ता है उस पर पुल न होने की वजह से वे दोनों गांव यूक दूसरे से बरसात के दिनों में लगातार तीन महीने तक कटे रहते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, आप यकीन करें उन दोनों गांवों के लोग बरसात के दिनों में खानपुर हो कर आते हैं वह वहुत लम्बा रास्ता पड़ता है इसलिए उस पुल को भी बनाया जाए । इसी तरह से एक ब्राहमण माजरा गाँव है वह बिल्कुल अम्बाला कैंट की जड़ में है । ब्राहमण माजरा और सम्भालखा के बीच में यदि पुल बना दिया जाए तो उन लोगों को भी काफी सहूलियत हो जाएगी क्योंकि ब्राहमण माजरा और सम्भालखा बरसात के दिनों में तीन महीने लगातार एक दूसरे से कटे रहते हैं । यदि उन गांवों के पास नाले पर पुल बना दिया जाए तो उन गांवों के लोगों को अम्बाला कैंट आने के लिए पहले जगाधरी रोड़ पर नहीं जाना पड़ेगा वे सीधे अम्बाला कैंट आ सकते हैं । पुल न होने के कारण उनको अम्बाला कैंट आने के लिए पहले जगाधरी रोड पर जाना पड़ता है फिर अम्बाला कैंट आते हैं । मैं उस पुल के बारे में मिनिस्टर साहब के साथ कई बार मीटिंग कर चुका हूं । मेरी अब भी प्रार्थना है कि उन सभी पुलों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए । इसके अलावा जो रोडज रिपेयर का काम है उसको भी किया जाना चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर रोडज का जाल बिछा हुआ है लगभग हर गांव को सड़क से जोड़ा हुआ है । लेकिन मै कहना चाहूंगा कि जब तक हरियाणा के देहातों में सड़कें नहीं बनी थीं उस वक्त तक देहातों की अजीब

स्थिति' होती थी कि यहां पर भी सडकें बन जाएंगी लेकिन अब जब रोडज बन गई हैं तो उनकी जरूरत हो गई है । लेकिन जो रोडज बनी हुई हैं उनकी रिपेयर नहीं हो पा रही है । जब लो गों की साईकिल के टायर से रोडी टकरानी है तो लोगों को महसूस होता हे कि सड़क बहुत खराब है । मैं कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से रोडज की कंस्ट्रैक्शन के लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है इसी ढंग से रोडज की रिपेयर के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है । मेरे हल्के में एक बिसनगढ़ गांव है । उस. गांव से नग्गल एक सड़क जाती है । आप यकीन करें कि उस रोड के बारे में लोग यह कहते हैं कि इससे बेहतर तो कच्चा रोड ही था इस रोड से तो उल्टा रास्ता ही खराब हो गया है । 6–7 वर्ष हो गए हैं उस र ओड की रिपेयर नहीं हो सकी है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस रोड की रिपेयर करवाई जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े । जिस–जिस रोड की रिपेयर होनी जरूरी है उसकी रिपेयर करवाई जाए । इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, ऐजुकेशन की डिमांड है । ऐजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । हमारी आने वाली जनरेशन का शिक्षा के साथ भविष्य जुड़ा हुआ है । शिक्षा के मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे नौजवान प्रधान भली जी ने एक बहुत अच्छी नीति ऐजुकेशन को दी है । उन्होने ऐजुकेशन के पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात कही है । उस बारे में जल्दी विचार किया जाना चाहिए । बच्चों की पीठ पर जो बस्ते का बोझ है उसको कम किया जाए । जिन स्कुलों में टीचर्ज का अभाव है

वहां तर टीचर भेजे जाएं । आज के वक्त में अगर किसी स्कूल में बच्चे टीचर के बगैर बैठे हैं तो यह बड़ी अजीब बात है । इसमें भी नई प्रणाली लानी चाहिए । मेरी कस्टिचुऐंसी में एक बबीयाल गांव है यह गांव बिल्कुल अम्बाला कैट के साथ लगता हुआ है और उस गांव के सभी लोग नौकरी पेशे में हैं । उस गांव की दिक्कत यह है कि उस गांव की पंचायत के पास आमदनी नहीं है । वह गाँव 10 हजार की उग्रबादी का गाँव है लेकिन उस गांव की पंचायत के पास कोई आमदनी नहीं हे यानी उस पंचायत के पास एक भी पैसा नहीं है । उस गाँव में लड़कियों और लड़कों के स्कूल की बिल्डिंग बच्चों के बैठने के काबिल नहीं है । मैं यह बात मंत्री जी के नोटिस में भो कई बार ला चुका हूं कि उस बिल्डिंग को बनाया जाए । मैं अब भो कह हूं कि उन स्कूलों की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए । इसके बाद डिमांड नम्बर 8 हैल्थ एंड मैडीकल की है । डिप्टी स्पीकर साहब, हैल्थ डिपार्टमैंट ने पिछले साल हर ब्लाक में 30 हजार की आबादी पर एक पी०एच०सी० खोलने की बात कहा थी और उससे थोड़ी कम आबादी पर एक डिस्पैंसरी खोलने की बात कही थी लेंकिन मेरे हल्के में अभी तक केवल तीन डिस्पैंसरी ही खोली हैं । मेरे हल्के में माजरी, मोहडा और जनसुई गाँवों में डिस्पैंसरी खोलने की बात थी । इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनसुई ? के बारे में यह कह करके दिक्कत डाल दी गई कि नग्गल में आलरेडी प्राइमरी हैल्थ सैटर हे इसलिए वहाँ पर डिस्पैसरी खोलने की कौई आवश्यकता नहीं है । जो नग्गल में पी० एच० सी० है

उसको हम प्रमोट करेंगे इसलिए जनसुई में डिस्पैंसरी खोलने की कोई जरूरत नहीं है । लेकिन उस गाँव में जा कर अनाऊंस कर दिया गया कि यहां पर पी० एच० सी० खोली जाएगी । जिस वक्त यह अनाऊंसमैंट की उस वक्त इस बात का ध्यान रखा जा सकता था कि कहां–कहां पर डिस्पैसरीज खोलनी हैं और कहाँ–कहाँ पर उनको प्रमोट करना है । इसके अलावा डिस्पैंसरीज का जो मामला है । डिस्पैसरी के नाम पर तो केवल एक कमरा ही बना हुआ है और वहां पर कभी डाक्टर आता है और कभी नहीं आता है । मेरे हस–कें में एक गाँव नूरपुर है उसमें डिस्पैंसरी है । उस डिस्पैंसरी में डाक्टर के रहने के लिए कोई जगह नहीं है । मैंने तो उस गांव मैं डाक्टर को रहते हुए कभी देखा नहीं है । मेरे हल्के में जिन तीन गांवों के मैंने नाम लिए हैं उनके अन्दर डिस्पैसरी खोलने का काम जल्दी से जल्दी किया जाए । हैल्थ डिपार्टमैंट का सब से जरूरी प्रोग्राम फेमिनी प्लानिंग का है । फेमिली प्लानिंग का काम हैल्थ डिपार्टमैंट अपने हाथ में ले । लेकिन कई बार टारगेट निश्चित कर दिया जाता है कि फलां बी ० डी० ओ ० या फलां तहसीलदार इतने इतने फैमिली प्लांनिग कें केस ले कर आएं कैम्प लगाया है । यह काम हैल्थ डिपार्टमैंट का है कि लोगों को इस बारे में प्रचार करके शिक्षित करे । आज ऐसी बात है नहीं है । आज लोग ' सारी बातों को समझते हैं । अब लोगो पर इस बारे मैं दबाव डालने या टारगेट निश्चित करने की जरूरत नहीं है । केवल लोगों को इस बारे में अच्छे ढंग से शिक्षा देने से और उनका अच्छे ढंग से आप्रेशन करने से काम चल सकता है । हैल्थ

डिपार्टमैंट के पास वाकायदा ऐसी टीम होनी चाहिए जो गांवों में जाए और लोगों को शिक्षा दे कि किस ढंग से उन्होंने रहना है । किस ढंग से उनको सफाई रखनी हे । इसी तरह की पिक्चरें बनाई जाएं और डी ० पी ० आर० ओ० के माध्यम से लोगों को वे पिक्चरें दिखाई जाएं । इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 15 इरीगेशन के बारे में है । इस में ड्रेनेज की बात आती है । इरीगेशन और ड्रेनेज दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं । सिंचाई का मामला भी बहुत गम्भीर है इसमें कोई दो राय नहीं हे कि सिंचाई के लिए सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए हैं । खास करके अम्बाला जिले के लिए सिंचाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार ने दिया है । लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक नहर दादूपुर से नलवी की तरफ आएगी और उस पर 18 करोड़ रुपये खर्च होने हैं लेकिन उस नहर के निर्माण के लिए इस बजट में पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है । उस नहर के निर्माण के लिए न बजट में' पैसे का प्रावधान है और न ही डिमांडज में बताया गया है । आई० पी० एम० साहब ने कहा था कि हम उस नहर के निर्माण पर दो करोड़ रुपये खर्च करेंगे लेकिन बजट में उसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया गया हे । इसलिये पता नहीं वे उस नहर के निर्माण पर पैसा कहां से खर्च करेंगे? डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे हल्के में बहुत नदी नाले निकलते हैं उन पर ड्रेनेज के महकमे का मैक्सीमम काम होने वाला है । कई स्कीमें सैक्शन हुई पड़ी हैं लेकिन उन स्कीमों के लिए पैसे का प्रावधान नहीं है । आई० पी०

एम ० साहब ने बताया था कि ड्रेनेज के कामों के लिए पिछले साल 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन उस पैसे को कम करके 11 करोड़ कर दिया गया । उस 11 करोड़ रुपये में से 6 करोड़ रुपये तो एस्टेब्लिशमैंट का खर्चा था, तीन करोड़ रुपये मसानी ब्रांच के लिए रखे गए थे और अढ़ाई करोड़ रुपये जमीन का कम्पनसेशन देना है । यदि सारा हिसाब लगाया जाए तो यह साढ़े 11 करोड़ रुपये बनता है । इसलिए यह बात नहीं समझ आती कि ये इसको किस तरह से अमलीजामा पहनाएंगे । इस से आगे ऐनीमल हसबैडरी की डिमांड है । इस बारे में बताया गया है कि जहां जहां पर शहरों के पास गांवों के लोग डेरी का काम करते हैं वे अपने पशुओंकी छोटी मोटी बीमारी कें लिए शहरों के अस्पतालों में जाते हैं । इस लिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां पशू अस्पताल नहीं है वहां अस्पताल खोलने के बारे में सरकार विचार करे । जहां सरकार ऐनीमल हसबैडरी के तहत गाय भैंसों के लिए प्रोत्साहन देती है वहां मिल्क योअर के दूध को बेचने का सिस्टम भी ठीक करना चाहिए । गांवों में दूध 3 रुपये' के हिसाब से खरीदा जाता है जबकि शहरों मैं उसी दूध को 5 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है । जो दो रुपये का मार्जिन है वह मिल्क योअर को नहीं मिलता बल्कि दूसरे लोगों की जेब मैं जाता है । सरकार इस बारे में विचार करे । इसके अलावा, फिशरीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को इस बारे में ऐजुकेट किया जाए और उनको बताया जाए कि मछलियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ।

12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में जिक्र करना चाहूंगा । यह बात ठीक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था काफी ठीक है लेकिन इसके बावजूद इस में सुधार की भी काफी गुजांइश है । ट्रांसपोर्ट का शत–प्रतिशत चार्ज सरकार के अपने हाथ में है । जितनी आमदनी अब सरकार को हो रही है इसमें यदि और सुधार कर दिया जाए तो सरकार की आमदनी बढ़ सकती है । आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जिन लोगों के पास प्राईवेट बसिज हैं वे सरकार से ज्यादा पैसा कमाती हैं । अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो यात्री हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा करेगे उनका बीमा हुआ समझा जायेगा । यह व्यवस्था सरकार ने टिकटों के साथ की है । यह अच्छी बात है । अम्बाला से दिल्ली तक ट्रैफिक की हालत बहुत गम्भीर है । ड़ंस बारे में मेरा कहना है कि जितने भी बड़े वडे हाई–वे हैं, उन पर ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक का कन्ट्रोल होना चाहिए । इस हाई–वे पर हरियाणा की बसें काफी चलती हैं लेकिन ट्रैफिक का कन्ट्रोल पुलिस के हाथ में हे । यह एक बहुत बड़ी समस्या है । आप भी जानते है कि जी ० टी ० रोड पर बहुत तेजी से बसें चलती हैं जिनकी वजह से ऐक्सीडैन्टस भी बहुत अत्रिक होते हैं । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि रोडवेज महकमे का और ट्रेफिक का आपस में तालमेल होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि के बारे में जिकर करना चाहूंगा । आज के दिन किसान कर्जों से दबे हुए हें । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि किसानों को अधिक से अधिक राहत दी जानी चाहिए । अब सरकार ने ट्रैक्टर पर सेल्ज टैक्स कम करके बहुत अच्छा काम किया है । इसके साथ साथ मेरा सुझाव यह भी है कि सरकार को किसानों को पेडू लगाने के लिए ऐजुकेट करना चाहिए और डसके लिए बजट में पैसे रखे जाने चाहिए । इस के लिए ऐग्रीकल्चर विभाग द्वारा किसानों को लोन दिया जाना चाहिए । आज के दिन किसानों को बिजली की भी बहुत जरूरत है । यदि कोई किसान अपने खेत में पेडू लगाता है तो उसके लिए लोन सरकार को देना चाहिए । यह लोन सरकार को इस हिसाब से देना चाहिए कि जितनी जमीन में उसने पेडू लगाये हैं उससे उसको प्रतिवर्ष कितनी आमदनी हो सकती है । यह लोन उस समय तक किसानों को प्रतिवर्ष दिया जाना चाहिये जब तक वे पेडू बड़े होकर कट कर किसान द्वारा बेच नही दिए जाते । जब किसान अपने पेडू काट कर बेच दे तो उस समय सरकार बेशक अपना लोन इन्ट्रैस्ट समेत वापिस ले ले । यदि सरकार ऐसा कोई प्रबन्ध करती है तो किसान अधिक से अधिक पेडू लगायेगा और उसकी उससे आमदन भी बढ़ेगी । आज के दिन बिजर्ली और पानी की बहुत आवश्यकता है । बिजली जिन्दगी का आज एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है । इस सम्बन्ध में मेरा सरकार को सुझाव है कि डोमैस्टिक परपज के लिए अधिक से अधिक बिजली लोगों को दी जानी चाहिए इस के लिए सरकार को

नये प्लांटस लगाने चाहिए और सरकार नए प्लांटस लगाने भी जा रही है । यदि बिजली के नए प्लांटस लगाये जायेंगे तो आने वाले समय में बिजली की– मांग को पूरा किया जा सकता है वरना नहीं । मेरे हल्के नग्गल को पहले शाहबाद पावर हाउस से बिजली आती थी लेकिन अब अम्बाला कैन्ट के पावर हाउस से बिजली आती है । इस बात को सुरजेवाला साहब ने क्वैश्चन आवर के दौरान माना था । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) । इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि मेरे हल्के के दुराना गांव में एक नया पावर हाउस लगायें ताकि लोगों की बिजली की दिक्कत कम हो सके ।

श्री नेकी राम (रतिया अन्उसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आज हाउस में बजट की डिमांडज पर चर्चा चल रही है । यहां पर मैम्बर साहेबान अपने अपने क्षेत्रों की बात कर रहें हैं । मैं मुख्यतरू तीन डिमांडज पर बोलूंगा । ये डिमांडज शिक्षा, ऊर्जा और खेती से सम्बन्धित हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं स्कूल से पढ़ा लिखा तो हूं नहीं । प्राईवेटली ही पढ़ा हूं । कुछ आप से सीख लिया और कुछ इन भाईयों से सीख लिया । मैं एक बहुत ही गरीब घर का आदमी हूं और झौंपडी में पैदा हुआ हूं यदि मेरे से कोई गल्ती हो जाए तो माफ करना । हमारा राजनैतिक शास्त्र यह बताता है कि योद्धाओं और राजनैतिक लोगों का यह कर्तव्य है कि वे मनुष्य की एक अच्छी आत्मा का विकास करें । आज स्वतंत्र भारत थें एक तगड़ी कौम की जरूरत है लेकिन पीछे के इतिहास

को देखते हुए आज कौम कमजोर होती जा रही है । इसलिए हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि– हम एक तगड़ी कौम पैदा करें और तगड़े इन्सान पैदा करें और, उन को हम अच्छी शिक्षा भी दे । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पटियाला हमारे इलाके के साथ लगता इलाका है । हाउस के तकरीबन सभी मैम्बर साहेबान जानते हैं कि पटियाला में बाबा आला होते थे जब उनके समय में लड़ाई होती ' थी तो उस समय आज की तरह हथियार नहीं होते थे । उस समय लोहे के गोले होते थे जिन से उस समय के लोग लड़ा करते थे । मैं आप को बताना चाहूंगा कि मैं एक दिन जब पटियाला गया तो उस समय के जो गोले थे, जिनसे वें लड़ा करते थे, मैं उठाने लगा लेकिन वे मेरे से उठ नहीं सके । उस समय के जवानों की छाती 36–38 इंच के करीब हुआ करती थी । मेरे कहने का मतलब यह है कि हम को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी नींव रखनी चाहिए । क्रीड़ा स्थल इन्सान के लिए बहुत जरूरी है । जब तक बच्चे कोउ अच्छा मकान न मिले और अच्छी शिक्षा न मिले तब तक एक अच्छा हरियाणा नहीं बना सकते ।

अध्यक्ष महोदय' अब मैं उर्जा की बात कहना चाहूंगा । इस जमाने में और खासकर स्वतंत्र भारत में उर्जा की बहुत जरूरत है । आज हम कारखाने लगाते जा रहें हैं लेकिन ये कारखाने उर्जा से ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हैं । मैं समझता हूं कि यदि आने वाली पीढी के लिए हमने रास्ता नहीं दिखाया तो हम अपने कर्तव्य में कोताही करेंगे । मेरा सुझाव यह

है कि शिक्षा की दिशा में हमें उचित पग उठाने चाहिए । आज शिक्षा में एक नया मोड़ आ रहा है । अब सरकार 10 जमा 2 की पालिसी लागू करने जा रही है । इसके लिटरेचर का पता नहीं कि कैसा होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि किताबों के जरिए बच्चों को बताया जाना चाहिए कि बिजली कैसे पैदा होती है, पानी के अन्दर कितने तत्व होते हैं और आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस क्या होती हैं । अध्यक्ष महोदय, हाड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं । वैसे भी हाइड्रोजन गैस बहुत कम मात्रा में खर्च होगी । कोयले से चलने वाले जो कारखाने या दूसरी चीजें हैं वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेंगी । श्री अध्यक्ष चौधरी साहब, मेरा ख्याल यह है कि इन बातों को आप इंजीनियर्ज के लिए ही रहने दें । आप कृपया इन बातों को छोड़कर कोई और काम की बात करें ।

श्री नेकी राम : स्पीकर साहब, मैंने तो प्राईमरी तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है । मैं इंजीनियर्ज और आप सबको क्या सलाह दे सकता हूं मैं तो अपने तजुर्बे के आधार पर बात कर रहा हूं लेकिन अगर टाईम की कुछ कमी है तो मैं आपका इशारा समझते हुए बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । अब श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बोलेंगे ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला–महाराजपुर) : स्पीकर सर, जो सुलक्षणा बजट पेश किया गया है और इसमें जितनी भी अनुदान की मांगें रखी गई हैं उनमें कहीं रूकावट की गुंजाईश नजर. नहीं आती लेकिन इनके लिए सरकार की प्राथमिकता के मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए जितने और धन की व्यवस्था की जाए उतनी ही थौडी है । स्पीकर सर, अब मैं मांगों की तरफ आता हूं । सबसे पहले मैं डिमांड न ० 8, जो भवन एवं सड्कों के बारे में है, के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा । भवन और छर्ड्के बनाने के लिए सरकार काफी कोशिश कर रही है लेकिन जें अपने हल्के की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे हल्के में सैक्टर्ज बहुत आबाद हुए हैं । वहां हुड्डा ने काफी काम किया है । स्कूलों के लिए वहां बिल्डिंग्ज बनी हुई थीं । जब वे खाली थीं तो उन्हें पुलिस स्टेशन्ज और एस ० स्व ० पी ० औफिस आदि के लिए अकुपाई कर लिया गया था लेकिन आज हालत यह पैदा हो गई है कि स्कूलों में बढ्ती हुई आबादी को देखते हुए अकमोडेशन कम पड गई है । इसलिए प्रार्थना है कि औफिसिज जो स्कूल्ज में –लगे हुए हैं उनके लिए भवनों का इन्तजाम किया जाए । सड़कों से सरकार ने काफी गांव जोड़ दिए हैं । नई स्कीम के अनुसार अब हस्पताल और स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा । लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो सड़कें एक एरिया को दूसरे छुरिया से सीधा जोड़ती हैं या जिससे शहर को आने या जाने की दूरी कम होती है उन्हें प्रायरिटी दी जाए । पुलों के मुतालिक भी मैं एक बात कहना चाहता हूं । बल्लभगढ से

मझावली के लिए एक सड़क गई है । मझावली से दनकौर के लिए सीधा राप्ता पड़ता है तथा उससे सिकन्दराबाद और बुलन्दशहर के एरियज का फरीदाबाद के औद्योगिक नगर से सीधा सम्पर्क हो जाता है । जितने भी और दूसरे पुलों से यू ० पी ० को हरियाणा से जोड़ने की बात है उन सबसे कहीं ज्यादा इसका महत्व हो जाता है । क्वैश्चन आदर में मली जी ने (नबाब दिया था कि इसेके बारे में प्रपोजल भेज दी गई है लेकिन बाद में जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि इन्हें यह पक्का याद नहीं कि वह प्रपोजल इसी पुल की है या किसी और पुल की है । अगर इसी की है तो धन्यवाद और अगर इस की नहीं है तो इसकी ओर सरकार अवश्य ध्यान दे । स्पीकर साहब, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि दनकौर को यू ० पी ० गवर्नमैंट ने इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है । उसे भी इंडस्ट्रियली डिवैल्प करना चाहते हैं । इसलिए यदि मझावली के रास्ते से पुरन को दनकौर (यू ० पी ०) से जोड़ा जाए तो ज्यादा फायदा होगा । मैं समझता हूं कि दोनो प्रदेशों की जनता के लिए यह सुविधाजनक होगा और हमारे प्रदेश के लिए आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगा ।

स्पीकर साहब, मिनी सैक्रिटेरिएट के बारे में तो मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकिं पिछले साल उसके लिए 40 या 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी लेकिन ठेकेदारों ने वहां थोडा ही सामान डाला है और मामला यों ही पड़ा है। पता

नहीं कहां रूकावट है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उस काम को जितने जल्दी पूरा करवाया जा सके करवाया जाना चाहिए । वहां कोर्टस की भी बड़ी दिक्कत हे । मार्किट की बिल्डंग्ज में कोर्टस लगते हैं, और लोग प्लानिंग के विपरीत अनअथोराइज्ड दुकानें घरों में खोल रहे हैं । आशा है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस ओर ध्यान देगा ।

स्पीकर साहब, डिमांड नं० 9 शिक्षा के बारे में है । इसके मुतालिक बहुत से सुझाव यहां दिए गए हैं । मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद इस दिशा में काफी सुधार किया जाएगा । लड़कियों की शिक्षा के लिए भी प्राईमरी स्कूलों की काफी व्यवस्था की गई है । पहले भी सरकार ने इसके लिए काफी कोशिश की है । यह कोशिश होनी भी चाहिए क्योंकि पढ़ी लिखी बहिनें न केवल दो घरों को बल्कि कई घरों को संभालती हुँ । इस सम्बन्ध में मेरी गुजारिश यह है कि शहरों की निस्बत यदि दूर दराज के इलाकों में ज्यादा मिडल और हाई स्कूल अपग्रेड किए जाएं तो बेहतर होगा । हमारे मंत्री जी ने कई बार यहां जवाब दिया कि इंटीरियर में टीचर्ज भेजने में बड़ी दिक्कत है । मैं अपने हल्के के मुतालिक कह सकता हूं वैसे जिले के बारे में भी मुझे काफी पता है । स्कूल में दो दो टीचर्ज होते हैं लेकिन कभी एक टीचर पहुंचता है और कभी नहीं भी पहुंचता । इसके भी कुछ कारण हए । यह समस्या तब तक हल नहीं हो

सकेगी जब तक लोगों का शहरों के प्रति आकर्षण बना रहेगा । हाउस रेट आदि की जो फैसिलिटीज शहरों में दी जाती हैं उनको देहातों में दिए बिना यह समस्या हल नही होगी । मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए ताकि देहाती बच्चे सफर न कर सकें ।

डिमांड न० 10 मैडिकल और पब्लिक हैल्थ के बारे में है । फरीदाबाद के हस्पताल के मुतालिक ए ० सी ० चौधरी जी ने भी कहा है और मैं भी कहना चाहता हूं कि वह बहुत पुराना हस्पताल है । फरीदाबाद की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है । केवल हमारी स्टेट के ही नहीं बल्कि दूसरी स्टेटस यहां तक कि दक्षिण के लोग भी वहां आबाद हो गए हैं । तमाम सैकटर्ज और दोनों शहरों की आबादी तकरीबन पांच साढ़े पांच लाख हो गई है । सैक्टर 8 में पांच छः सौ बैडज का हस्पताल बनाने की व्यवस्था है । पिछले साल एक प्रश्न के जवाब में यहां कहा गया था कि ज्यों ही फंडज अवेलेबल होंगे उसे बनाने की कोशिश की जाएगी । मैं समझता हूं कि उसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत है क्योंकि पांच–छः सौ बैडज का वह हस्पताल बनना है । मेरी राय यह है कि यदि उसे पार्टस मैं बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ।

स्पीकर साहब, नगर बिकास, पुनर्वास और उद्योग की डिमांडज को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं । हुड्डा हमारे प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहा है । उसने लोगों के पुनर्वास के लिए कई

योजना बनाई हैं । छोटे छोटे सैक्टर्ज आबाद किए हैं लेकिन मैं सरकार का ध्यान फरीदाबाद की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं । मुख्य मती जी ने कल एक सप्लीमैंटरी के जवाब में आश्वासन दिया था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो अनअथोराइज्ड तरीके से बसे हुए हैं अगर द्सरी जगह कोआप्रेटिव तरीके सं या इंडिबिजुअल तरीके से बसना चाहते हैं तो हम उन्हें प्लोटस वगैरा कंप्लैक्स में या दूसरी जगह दे देंगे । उन्होने यह भी कहा था कि इसके सर्वे और ऐग्जामिनेशन का काम वे मेरे सुपुर्द करते हैं लेकिन इसके बारे में मेरी गुजारिश यह है कि इसके लिए एक कमेटी बना दी जाए । उससे एक तो तीनों हल्के कवर हो जाएंगे और काम भी आसानी से हो जाएगा ।

स्पीकर साहब, एक बात मैं स्लमज को रोकने के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा । आपने भी इस बारे में कहा था कि इसके लिए पहले ही कानून में व्यवस्था है लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि उसमें कुछ कमी है । बुनियादी बात यह है कि जमीन ऐक्वायर करने के लिए कुछ सैक्शन्ज का सहारा लेना पड़ता है । सैक्शन 4 एक ऐसा सैक्शन है जिसके तहत कंस्ट्रक्शन पर तो पाबन्दी है लेकिन सेल और परचेज पर पाबन्दी नहीं है । लोग प्लाट्स सेल कर देते हैं और गरीब लोग उन पर मकान बना लेते हैं । हमें भी इससे मुश्किल हो जाती है । उनकी हालत को देखते हुए मजबूरन हमें उनकी इविक्शन को रुकवाना पड़ता है । इसलिए यह निहायत जरूरी है कि कानून में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे खरीद

फरोक्त न हो सके । अनअथोराइज्ड कालोनीज के बारे में स्पीकर साहब बे एक मिसाल और देना चाहता हूं । दो साल पहले मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं फौरन जमीन ऐक्वायर करके ग्रेन मार्किट बनाने का आश्वासन पब्लिक में दिया था । उसके लिए आवश्यक धन और दूसरी कार्यवाही पूरी होने तक वह एरिया अनअथोराइज्ड मकानों से भर गया इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अब भी सरकार उस जगह को और उसके बाहर जो जगह है तुरन्त ऐक्वायर कर ले वरना वह जगह भी अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन से भर जाएगी ।

स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले अर्ज किया फरीदाबाद औद्योगिक दृष्टि से भी और रैजिडैन्शल सैक्टर्ज की दृष्टि से भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है । फलस्वरूप एयर पौल्यूशन और वाटर पौल्यूशन भी बढ़ रही है और स्लमज भी बन रहे हैं । इसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया था, जिसके दूरगामी परिणाम हैं । फरीदाबाद में बहुत बड़ी आबादी हो गई है और दिन प्रति दिन यह बढ़ती ही जा रही है । मैंने सुझाव दिया था कि वहां पर रैजिडैन्शल और इंडस्ट्रियल दबाव को खत्म करने के लिए पलवल, हसनपुर, सोहना आदि की तरफ इंडस्ट्रीज को फैलाया जाये । उससे एयरपौल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की जो दिक्कत होती है वह नहीं होगी । दूसरे छोटे शहरों की तरफ भी इन्डस्ट्री फैल सकेगी । यह जगह यदि जमुना साइड की तरफ चुनी जाये तो और भी अच्छा रहेगा । इससे जो ला एन्ड आर्डर की समस्या है

वह भी नहीं हो सकेगी और जो दूसरी समस्यायें हैं वे भी नहीं हो सकेंगी ।

मांग नम्बर 15 बिजली और सिंचाई के बारे में है । सिंचाई और बिजली के लिए सरकार ने काफी कोशिश की है कि लोगों को इस मामले में अधिक से अधिक सुविधा दी जाये । हमारी सरकार ने सिंचाई और बिजली के लिए 83 परसैन्ट से भीं ज्यादा बजट का हिस्सा इनके लिए–दिया है । यह बहुत अच्छी व्यवस्था. की है । किसान रीढ़ की हड्डी है । इसको सुविधा देने से हमारे प्रान्त की उन्नति होगी । स्पीकर साहब मेरे हल्के में इस विषय में जौ समस्यायें हैं उनका भी जिक्र करवा जरूरी समझता हूं । स्पीकर साहब, आगरा कैनाल से खेडी कला माइनर मेरे तथा शारदा जी के हल्के को कवर करती है । वहां पर लिफ्ट योजना से पानी दिया जाता है । इसी तरह से गुडगावा कैनाल से हरचन्दपुर माइनर भी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से चलती है । इन दोनों स्कीमों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है लेकिन बिजली पूरी नहीं मिल पाती । सरकार ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है लेकिन जो हालत बिजली की रही है वह किसी से छुपी हुई नहीं है । पिछले साल के हालात का आपको अच्छी तरह से मालूम ही है । बिजली न मिलने के कारण हमें हमारे हिस्से का प्रा पानी नहीं मिल पाता है इसलिए अपने हिस्से का पानी लेने के लिए वहां जनरेटिग सैटल लगाये

जाने चाहिए या कोई दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए । जो पानी मिलता है वह टेल तक बड़ी मुश्किल तक पहुंच पाता है ।

इसके अलावा मेरे हल्के में एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था । मेरे तथा शारदा जी के हल्के में एम०आई०टी० सी० के ट्यूबवैल्ज लगे हुए हें । यह स्कीम दस पन्द्रह साल पहले चालू की गई थी । मेरे हल्के मैं नीचे का सारा पानी ऐक्सप्लायट हो गया जिसके कारण लोगों के ट्यूबवैल्ज सूख गये । उन लोगों के लिए बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है । हुन ट्यूबवैल्ज से गुडगांवा कैनाल को फीड किया जाता है । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, इस बारे में उन्होंने मीटिंग भी की थी और कोई प्रोपोजल भी भेजी है । इसलिए. मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन ट्यूबवैल्ज को डी०आई०टी ट्यूबवैल्ज में कनवर्ट किया जाये । और इस पहले वाली स्कीम का खत्म किया जाये । दूसरे वहां खालों को भी पक्का किया जाये । इससे आने वाले वक्त में जो किसानों की तबाही होगी वह तो बच सकेगी और गरीब किसानों का भला हो सकेगा ।

इसके साथ–साथ मैं थोड़ा पशु पालन की डिमान्ड पर भी अर्ज करना चाहता हूं । पशुपालन के लिए सरकार ने 111 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है । पशुपालन 'किसानों के लिए इन्डस्ट्री के समान है । हमारे हरियाणा में 6–7 हजार देहात. हैं । अगली योजना तक हम छोटे मोटे सात सौ सेन्टर खोल पायेगें ।

इस तरह से दस गांवों पर एक सैन्टर पड़ता है । मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस बारे में बढ़ोतरी की जाये ताकि लोगों को फायदा हो सके । खादर और पहाड़ के इलाके में लोग पशुपालन पर बहुत निर्भर करते है । इसलिए उन इलाकों में और भी ज्यादा इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए । वहां पर प्रायरिटी बेसिज पर डिस्पैन्सरी और सैटर खोले जाने चाहिए ।

स्पीकर साहब, मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं । आजकल मेरे हल्के मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में एक समस्या बनी हुई है । ट्रांसपोर्ट में लेबर और ऐम्पलाएमेंट का मामला भी आ जाता । मैं इस बारे में सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें मिनी बसों के परमिट दे दिये जायें ताकि बेरोजगारी की समस्या हल हो सके । मेरे हल्के में काफी केसिज हैं जिनको हरियाणा सरकार ने डगई व्हीलर्ज का दस साल पहले लाइसेंस दिया था लेकिन अब सरकार ने वे लाइसेंस खत्म कर दिये हैं । अब उन्हे रोड पास नहीं दिया जाता है । उन लोगों ने बैंकों से और दूसरे तरीके से लोन लिया हुआ कुए लेकिन सरकार उन लोगों को ओं पर चलने नहीं देती है । अगर वे बिना लाइसेंस और परमिट के च लते हैं तो उा चालान किया जाता है । अब उन अफसरों की भी मजबूरी है क्योंकि सरकार के आदेश हैं । फिर दूसरी ओर हमारी भी मजबूरी है, हमें भी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कहना पड़ता है कि इनका चालान न किया जाये । हमें ऐडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालना पड़ता है कि इन

लोगों ने लोन ले रखा है इसलिए इनका चालान न किया जाये । इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन लोगों को परमिट इशू किये जायें । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन मांगों की ताईद करता हू ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1986–87 के बजट की डिमान्डज आज सदन के सामने हैं । दो दिन पहले वित्त मंत्री जी ने हरियाणा प्रान्त का बजट प्रस्तुत किया था । जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया तो हमें वेहद खुशी हुई कि किसानों की जो बिजली और पानी की समस्यायें हैं, उनका वास्तव में समाधान करने के लिए 232 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, अगर सारे बजट को देखें तो यह बिल्कुल सच बात है जैसी कि हमारे एक दोस्त ने कही कि इरीगेशन और बिजली बोर्ड के महकमों पर जो खर्च किया जा रहा' है वह इस बजट का काफी बड़ा हिस्सा है । बाकी महकमों के पास तो एक ब्रेकफास्ट के तौर पर ही पैसा रह जाता है । डिनर और लन्च तो बिजली बोर्ड और इरीगेशन ही करेगा । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, हर साल हम इस महीने में बजट पास करते हैं और यह समझ कर पास करते हैं कि हमारी अपनी कांस्टिचुऐंसी में कहां कहां और किस किस जगह के लिए पैसा रखा गया है । जब हम अपनी कस्टिचुऐंसी से आते हैं तो हमारे सामने सारे साल की समस्याऐं होती हैं क्योंकि उन समस्यों के

विषय में हम मुख्य मला जी, मंत्रियों और सचिवों को चिट्ठियां लिखते रहते हैं और उनके जवाब भी हमारे पास जाते रहते हैं । किसी लैटर के जवाब में जब यह बात जाती है कि यह स्कीम बननी मुश्किल है क्योंकि फन्डज की कमी है या अवेलेबल नहीं हैं तो हम उनकी दिक्कतों को महसूस करते हैं कि जो उन्होंने लिखा है यह वाकई ही ठीक बात है । सरकार को फन्डज की दिक्कत हो सकती है लेकिन जब हम बजट पास करते हैं और उस बजट में प्रावधान होता है कि अगले साल में इस चीज के लिए पैसा रखा गया है तो वह काम होना चाहिए । जब अगले साल के लिए यह बजट में रख देते हैं कि डिस्पैंसरीज पर इतना पैसा खर्च होगा और एस० वाई० एल० पर इतना होगा, तो बह पैसा तो खर्च किया ही जाना चाहिए । जब बजट में हमारे अपने इलाके के लिए पैसे का प्रोविजन हो तो बड़ी खुशी होती है कि ड्ह स्कीम के लिए पैसा रखा गया हे । हम उस बात को एक अचीवमैट समझते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने यह लिखा था कि सन 1985–86 में इरीगेशन महकमे को तीन करोड सतरह लाख रुपया स्प्रिकलर्ज सैट्स के लिए दिया जायेगा और सौ स्प्रिकलर्ज सैटस खरीदे जायेंगे । जब हम यहां से बजट पास करके अपने इलाके में गये तो हमने इस बात को लोगों को कहा । आप जानते हैं कि हमारा इलाका रेतीला है, यह इलाका मुख्य मंत्री जी के इलाके से मिलता जुलता है । चौधरी शमशेर सिंह जी ने हमारे इलाके को देखा होगा क्योकि उनका इलाका हमारें से बहुत अच्छा है । वे हमारे इलाके में घूमे हैं ।

हमने बड़े विस्तर से पब्लिसिटी की कि आपके लिए यहां सौ स्प्रिकलर्ज सैट्स आयेंगे । हमारे यहां जो इलाका ऊंचा है यानि जो एरिया 15– 15 फुट माइनर और नहर से ऊंचा पड़ता है उसके बारे में अफसरों के पास दरखास्तें भिजवाते कि यह इलाका चूंकि ऊंचा हैं इसलिए यहां पर स्प्रिकलर्ज सैट्स लगवाईये । वे पास भी कर दिये कि यहां पर लगना चाहिए लेकिन वे अब तक नहीं लगे । अध्यक्ष महोदय, इस बजट में अपनी चर्चा में कहीं भी वित्त मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि यह बजट तो पास कर रहे हैं लेकिन जो हमने पिछले साल 317 लाख रुपया स्प्रिंकलर्ज सैट्स का पास किया था, वह हमने यूज किया है या नहीं किया है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सौ स्प्रिकलर्ज सैटस में से केवल छः खरीदे गये हैं । इस बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया था, जब वे भिवानी गये थे । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं जा कर तहकीकात करूंगा कि ये सैटस क्यों नहीं खरीदे गये? मुझे तो खुशी है कि वित्त मती जी भिवानी के रहने वाले हैं । उन्हे भिवानी के बारे में शायद कुछ शान भी होगा ।

अध्यक्ष महोदय, आज से तीन चार साल पहले और हो सकता है पांच साल भी हो गये हों लेकिन तीन साल पक्के हो गये हैं इस सदन में मैंने मुख्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट की थी कि जो जमीन नहर की खुदाई में आयी है या किसी माइनर में आयी है उसका मुआवजा पूरा नहीं मिल पाया है । बड़ी कोशिश के बाद और मुख्य मंत्री जी के हुक्म से कुछ केसिज में मुआवजा मिला है

लेकिन कुछ केसिज अभी भी रह्ने हैं । इनके कुछ अफसर रोहतक, हिसार और अम्बाला में बैठते हैं जिसकी वजह से केसिज कने डिसाईड करने में देर लगती है । स्पीकर साहब, इनके भिवानी जिले का एक तो दुर्भाग्य यह है कि जब हम लैंड ऐक्वीजीशन के या कम्पनसेशन के बारे थे लिख ते है तो हमसे यह कहते हए कि जाकर रोहतक के अफसर से बात करो । मैं खुद रोहतक के अफसर से मिलने के लिये अपने कांस्टीच्यूएंट्स को लेकर गया और वहां अफसर से मिला तो उसने यह कहा कि हो सकता है कि आपका भिवानी जिले का केस मेरे पास न् हो । इसलिये मैं चौधरी शमशेर सिंह जी से और मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो जमीन के मुआवजे के केसिज अभी तक पैंडिंग हैं, उनके लिये. एक अफसर भिवानी के केसिज के बारे में भिवानी में लगाया जाये । मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जुई नहर, निगाना नहर, सिवानी नहर, लौहारू नहर और जे ०एल ०एन ० नहर के इलाके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हें । वहां के बहुत से केसिज अभी तक पैंडिंग पड़े हैं । इसलिये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि एक अफसर भिवानी में जरूर लगा दिया जाये ताकि वह वहां के केसिज का निपटारा कर सके । अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी समस्या और है जहां– जहां यह लिफट इरीगेशन स्कीम्ज हैं, वहां पर यह समस्या है । लिपट इरीगेशन स्कीम की नहर चलते हुए अगर बिजली चली जाए तो पहला पम्प हाउस पानी नहीं उठाता और न ही दूसरा उठा पाता है । दूसरे की खो नौबत ही नहीं आती क्योकि पहला पम्प हाउस ही आगे पानी की सप्लाई

नहीं करेगा । अध्यक्ष महोदय, बहुत से किसानों कौ इस वजह से दिक्कत है । मेरे डिस्ट्रिक्ट में तीन–चार गांव ऐसे हैं जैसे सिवानी कैनाल का पहला पम्प हाउस शहाडवा के पास है, जुई कैनाल का पहला पम्प हाउस लोहानी के पास है । लोहारू कैनाल का पहला पम्प हाउस गांव रावलधी के पास है और निगाना कैनाल का पहला पम्प हाउस रिवासा के पास धारण में है । मुख्य मंत्री जी ने भी इस समस्या को हल करने की काफी कोशिश की है लेकिन इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । वहाँ पर या तो पावर सप्लाई का डबल अरेजमैंट कर दिया जाए या फिर डबल फीडर्ज दे दिए जायें । अगर डबल फीडर्ज भी प्रोवाइड करना पोसीबल न हो तो वहां पर एक थर्मल प्लांट लगा दिया जाए और उसमें सबसे पहली प्रायरिटी लिफ्ट इरीगेशन को मिलनी चाहिए । स्पीकर साहब, हमारे इलाके का एक बड़ा ही दुर्भाग्य है । आपके इलाके में जीरो होती है । तब उसको 4– 4 और 5– 5 पानी देने पड़ते हैं । इसके लिए आपको लगातार बिजली भी देनी होती है । अब तो भगवान की दया से बिजली इस सवय पूरी उपलब्ध है लेकिन जब पूरी बिजली नहीं होती तो फिर क्या करते हैं । फिर हमारे इलाके से बिजली काटते हैं । बहां पर नहर भी पूरा पानी नहीं दे पाती और बिजली की कटाई भी वहीं से होती है । इसलिए मैं सरकार के सामने यह सु त्राव रखूंगा कि जहाँ परं नहर का पानी उपलब्ध न हो, वहां पर बिजली ज्यादा दी जाए । इसके अलावा,. स्पीकर साहब, मैं सिंचाई मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा । जो लिफ्ठ कैनाल्ज के पहले पम्प हाउस हें, वहां से

पानी एस्केप होता है वहां पर 4–4 और 5– 5 सौ एकड़ जमीन खराब हो जाती है । वहां पर हर साल फसल खराब होती है 1 मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वहाँ पर कोई रिजर्वायर बनाई जाए चाहे इसके लिए गवर्नमैंट को जमीन ही क्यों न ऐक्वायर करनी पड़े उस रिजर्वायर में पानी इक्ट्ठा करके बाद में उसको कभी–भी प्रयोग में लाया जा सकता है । एक हमारा कम्पनसेशन का कानून 1928 का अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है । इस हिसाब से एक एकड़ का एक किसान को 500 या 700 रुपया थी नहीं मिल पाता । इसको चेंज किया जाए । स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड की हालत संतोषजनक नहीं है । बिजली बोर्ड के बारे में मैंने एक लिस्ट देखी है । कोई भी महकमा नहीं है जिससे बिजली बोर्ड ने लोन न ले रखा हो । यह लिस्ट किसी क्वैश्चन के बारे में टेबल पर ले हुई थी । कहने का मतलब यह है कि बिजली बोर्ड ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है । अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे यह जानकर कि एक–एक एम० एल० ए० ने एस० ई ० को यह दरख्वास्ते दी कि उसके हल्के में यह सामान भेजा जाए । फिर बिजली बोर्ड वहाँ पर 50 खम्बे भी न पहुंचा सके, यह काबिले गौर बात है । ट्यूबवैल कुनैक्शन्ज के बारे में चौधरी शमशेर सिंह जी की भी बेबसी है क्योंकि इस बारे में कई दिक्कतें हैं । लेकिन इन दिक्कतों का समाधान मंत्री जी के और मुख्य मंत्री जी के पास है । किसान को तो तब फील होता है जब कोई आकर उसके गिरेबान को पकड़ता है और यह कहता है कि तुमने ट्यूबवैल के लिए लोन लिया हुआ है । आज लोगों को लोन लिए हुए 6–6,

4– 4 और कईयों को तीन–तीन साल हो गए है । तीन साल के केसिज तो आपको अकसर मिल जाएंगे । बैंक वाले पैसे की रिकवरी के लिए पहुंच जाते हैं लेकिन उसको कुनैक्शन नहीं मित्रता । मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जब तक किसान को टयूबवैल का कुनैक्शन में मिले, उस वक्त तक उस लोन पर इन्टैमस्ट न लिया जाए । स्पीकर साहब, मैं एक और बात सिंचाई विभाग से रिक्वैस्ट करूंगा हमारी जो लिफ्ट चौनल्ज हैं, उनमें इतनी स्लिटिंग हो जाती है कि उनको डिस्लटिंग की जरूरत है । आपको पता ही है ये चौनल्ज टिब्बों में से गुजरती हैं । मैं मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहुंगा कि उनमें आज पानी की जगह रेत भरी हुई है । जब हम निजी तौर पर चिट्ठी लिखते हैं चौधरी शमशेर सिंह जी को कि यह दिक्कत है तो यह कहते हैं कि पैसे की दिक्कत है । आधी नहर में तो पानी पहुंच गया लेकिन बाकी की में रचे पड़ी हे । यही हाल उनकी मेनटेनैसं का है । इन लिपट स्कीम्ज की मेनटेनैंस के लिए सारे साल के लिए बजट में 5– 6 लाख रुपया भी नहीं खर्च किया जाता है । मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दें । स्पीकर साहब, ड्रेनेज के बारे में पिछले बजट में वित्त मंत्री जी को याद होगा कि 14 करोड रुपया ड्रेनेज के लिए दिया गया था । इसी से फ्लड एरियाज को भी देखना था । अध्यक्ष महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से ग्यारह–साढे ग्यारह करोड रुपया ही खर्च ही पाया है । यह जो 14 में से 11– 11½ करोड़ रुपया खर्च हूआ हैं? यह ड्रैनैज के काम पर खर्च नहीं हुआ है ।

यह तो ड्रैनेज डिपार्टमैंट का ऐक्सपैडीचर है । मसानी ब्रांच के लिए 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ । इस डिपार्टमैंट की ऐस्टैबलिशमैंट पर कितना खर्चा है, इसका जवाब चौधरी शमशेर सिंह जी क्या देंगे? मेरी इत्लाह के मुताबिक 6 करोड़ रुपया इसकी ऐस्टैबलिशमैंट का खर्च है और जो जमीन का मुआवजा दिया गया है, वह अढाई करोड़ के करीब है । इस तरह से साढ़े ग्यारह करोड़ तो हो गया । बाकी का पैसा ड्रैनेज के लिए क्या इस्तेमाल होगा? मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि जहां पर ज्यादा प्रौब्लम हैं, वहां पर दिल खोल कर इरीगेशन डिपार्टमैंट खर्च करे । स्पीकर साहब, फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत की है लेकिन इनके कमिशनर ने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी । स्पीकर साहब, यह मिनिस्टर से आशा नहीं की जा सकती कि उसको माइन्यूट डिटेल्ज पता हों अच्छा होता, वह अपने बजट के ऐडेरस को पहले पढ लेते । वह भिवानी जिले के हैं । इसमें इन्होंने कहा है कि to serve the undulating tracts of the State, the Jui and Siwani lift irrigation schemes have already been completed. स्पीकर साहब, इन्होंने यह बात बिल्कुल बेसलैस कही हैं । मेरे पास इनके मंत्री जी की चिट्ठी आई है । मैंने पहले एक चिट्ठी चौधरी शमशेर सिंह जी को लिखी थी । उसका जवाब मती जी ने 25 जनवरी को दिया है । यह चिट्ठी केवल एक महीना और दो दिन पहले ही आई है । जुई कैनाल की लम्बाई 1,46,000 आर० डी० हे । इसमें इन्होंने खुद माना है कि इस कैनाल की लाइनिग पूरी नहीं हुई है । मैंने इनको यह

चिट्ठी लिखी थी कि आपकी लाइनिंग पूरी नहीं हुई हुए तो इन्होंने यह कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर सीपेज बहुत ज्यादा है । यह बात ठीक है कि उस इलाके में सीपेज ज्यादा है । नहरों में इस तरह के पानी को बचाकर ठीक इस्तेमाल किया जा सक्तता हे । स्पीकर साहब, 1,46,000 आर०डी० में से 88,000 आर ० डी ० का काम अनलाईन्ड है । मैं सरकार से यह अर्ज करूंाा कि कम से कम इनके कमिशनर साहब को तो रिकार्ड देख लेना चाहिए था । स्पीकर साहबय एस ० वाई० एल० के बारे में बहुत ज्यादा पैसा इसके अन्दर दे रखा है । यह खुशी की बात है । मुझे पूरा भरोसा है कि चौधरी भजन लाल इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह कैरीयर चौनल जल्दी से जल्दी बनाई जाए । मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार के प्रयत्नों से और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के प्रयत्नों से हरियाणा के हक हकूक की पूरी रक्षा होगी ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी खत्म करें ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब अभी तो मुझे थोड़ी ही देर हुई है । स्पीकर साहब कई बार बड़े अचम्भे की वात होती है । पिछले दिनों एक मंत्री जी का ब्यान था कि बेहतर तो यह होता कि कैरियर चौनल 1976 में बन जाती । मन्त्री जी का ब्यान यह जाहिर करता है कि आज की सरकार इस कैरियर चौनल को नहीं बना सकती । मैं आपके जरिए मुख्य मंजी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मिनिस्टर को कहें' कि कैरियर चौनल के बारे में वे इस तरह के ब्यान न दिया करें । स्पीकर साहब, यह

बड़ा सैन्सिटिव इशू है । अगर मन्त्री इस प्रकार की बात कहेंगे तो लोगों का फेथ शैटर हो जाएगा और लोगों के अन्दर अविश्वास पैदा होगा ।

स्पीकर साहब, कल या परसों अनअथोराइज्ड कालोनीज के बारे में एक सवाल था और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन. दिया था कि हम अनअथोराइज्ड कालोनाइजर्ज के खिलाफ ऐक्शन लेगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । स्पीकर साहब, हमारे हल्के के एम० पी ० ने जून में मुख्य मन्त्री जी को एक चिट्ठी लिखी और मुख्य मती ने उसका जवाब 9 दिसम्बर, 1985 को दिया । उस चिट्ठी में चीफ मिनिस्टर ने इस वात को माना है कि भिवानी जिले में अनअथोराइज्ड कालोनाइजर्ज के खिलाफ टाउन एण्ड कन्टरी प्लानिंग डिपार्टमैंट ने 175 एक ० आई आर ० दर्ज करवा रखी हैं । स्पीकर साहब, मेरे नोटिस में आया है कि जिस आदमी ने सब से ज्यादा अनअथोराइज्ड कालोनीज बना रखी हैं एफ० आई० आर० दर्ज होने के बाद उसको लाइसैंस दे दिया गया है । स्पीकर साहब, अनअथोराइज्ड कालोनीज से यह दिक्कत आती है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, उनको सिवरेज की दिक्कत होती है, बिजली की दिक्कत होती है और दूसरी कई तरह की दिक्कतें आती हैं ।

स्पीकर साहब, अब मैं बोर्डज और कार्पोरशन की बात करूंगा । आपके हुक्म से इनकी रिपोर्टस सबमिट की गई । आपने देखा होगा कि कोई बोर्ड या कार्पोरेशन ऐसा होगा जिसकी

रिपोर्ट समय पर आई हो । हमारे एम०एल० एज० साहिबान इनके चेयरमैन हैं । इनको पब्लिक के इन्ट्रैस्ट में फैसला करना चाहिए । मैं परसों रिपोर्ट पढ्ने लगा तो पता लगा कि ये वे रिपोर्टस हैं जिनके बारे में पहले ही अखवारों में चर्चा हो चुकी है । स्पीकर साहब, मैं एक सैन्सिटिव बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । यह बात एग्रीकलचर मार्किटिंग बोर्ड के बारे में है । कैथल की मार्किट कमेटी, जो आपके हल्के के साथ लगती है, ने एक सड़क बनवाई । उस पर जो अर्थ वर्क हुआ उस अर्थ वर्क में लाखों रुपए का घपला था । शिकायत हो गई और शिकायत के बाद मुख्य मंत्री ने यह आर्डर कर दिए कि इस बारे में तहकीकात करके जायज कार्यवाही की जाए और इन्साफ किया जाए । इंक्वायरी के बाद चीफ सैक्रेटरी ने बोर्ड को लिख कि इस एस०डी०ओ० के खिलाफ यह फूल प्रूफ केस है । इस पर ऐक्शन लिया जाए । उस लैटर पर एल० आर० ने लिखा कि चीफ सैक्रेटरी की ऐडवाइस कोई मैटर नहीं बनता । उस केस को विदड्रा कर लिया । स्पीकर साहब, गवर्नमैंट के कहने पर सारी चीजें हों और फिर भी कोई ऐक्शन न लिया जाए यह कहां तक ठीके हे । मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे एम० एल० एज० चेयरमैन हों या दूसरे लोग चेयरमैत्र हों उनको इस बात को अश्योर करना चाहिए कि बोर्ड ठीक तरह से चल रहें है या नहीं । हमारे एम० डीज० को भी इस बारे में विचार करना चाहिए । स्पीकर साहब, ऐग्रो इंडस्ट्रीज में भी लाखों रुपए का घाटा चल रहा है और वहां का काम कोई सैटिसफैक्टरी नहीं है । मैं मुख्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि जब उनके सामने रिपोर्ट

आए तो वे सब बातों का ख्याल रखें । स्पीकर साहब, अगर मैं पल्लिक हैल्थ को टच न करूं तो बहन प्रसन्नी देवी नाराज हो जाएंगी । मैं बापोडा की वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं । इस वाटर सप्लाई में दस गांव ऐसे हैं जो टेल पर हैं । इन गांवों को दो तीन साल से पानी नहीं पहुंचा है । इसमें सब से बड़ा कारण बिजली की फेल्योर है । पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट इसमें कुछ नहीं कर सकता । मैंने मुख्य मन्त्री से भिवानी में बात की थी । आज फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इन स्कीमों को छोटा–छोटा करके जनरेटर्ज लगाए जाएं ताकि पब्लिक हैल्थ के वाटर वर्क्स के जरिए लोगों को पानी पहुंच सके । स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आप ने खुद भी महसूस किया होगा कि यदि गांव में नलका टूट जाए, बिजली का खम्बा टूट जाए या बिजली का ट्रांसफारमर जल जाए तो गांव से बीस तीस आदमी बस में भर कर आ जाते हैं । स्पीकर साहब, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अपनी गवर्नमैंट के आफिसर्ज की इतनी ऐफिशिऐन्सी होनी चाहिए कि कोई एस० डी०ओ० हो या बिजली का एस०डी०ओ० हो उसको सरकार की तरफ से यह हुक्म होना चाहिए कि वह इतने गांवों में जाएगा, उनको चौक करेगा । तभी लोगों की दिक्कतें दूर होंगी ।

स्पीकर साहब, आप बाजार में जाते होंगे । आपने देखा होगा कि कहीं एस० ई० की कार दौड़ रही है और कहीं एक्सीयन की कार दौड़ रही है । मैंने जन– वाणी प्रोग्राम देखा था । उसमें

विश्व प्रताप सिंह ने कहा था कि औफिसर्ज की कारों के ऊपर पांच परसैन्ट कट लगा दिया है लेकिन देखने में यह आया है कि औफिसर्ज की कारें राउन्ड दि क्लौक चलती रहती हैं । अगर आप हम एम०एल०एज० साहिबान की हालत देखें तो वह यह है कि जितना पैसा आप देते हैं उसी से गुजारा चलाते हैं । गुप्ता जी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन गांव तक जरूर पहुंचे । धन्यवाद ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा (जगाधरी) : अध्यक्ष महोदय, स्तन में बजट डिमान्डज पर चर्चा जारी है । मैं भी अपने हल्के के बारे में दो चार बातें कहना चाहूंगा । मैं उन डिमान्डज पर ही बोलूंगा जोकि हमारी बेसिक ऐमेनीटीज या बुनियादी जरूरियात से ताल्लुक रखती हैं । स्पीकर साहब, जगाधरी सब– डिवीजन शायद हरियाणा का तीसरे नम्बर का कमाऊ पूत है । हरियाणा से टैक्स की शक्ल में, एक्साइज की शक्ल में और रैवेन्यू की शक्ल में जितना कर प्राप्त होता है उसमें जगाधरी का नम्बर दूसरा या तीसरा है । मगर जगाधरी सब–डिवीजन पर उसमें से क्या कुछ खर्च होता है देखने वाली बात यह है । इस बात को लेकर मुझे सरकार की नियत पर या उसके इरादे पर कोई शक नही है । जहां तक बजट का ताल्लुक है वह प्रोग्रैसिव और बहुत अच्छा बजट हैं । मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार के नोटिस में नहीं आतीं । सरकार तो बहुत कुछ करने जा रही है लेकिन फरदर जहां तक ऐग्जीक्यूशन का तालुक है या सरकार को आगाह करने

का तासससउक है हमारे औफिसर्ज द्वारा कितनी ऐसी चीजें हैं जो –सरकार तक पहुंचती नहीं हैं । नैग्लीजैंस बहुत है । स्पीकर साहब, एक बुनियादी चीज ऐजुकेशन है । जगाधरी में आज से सत्तर पचहत्तर साल पहले गवर्नमैंट हाई स्कूल बना था । मैं 1932 की बात कर रहा हूं । जब मैं स्टूडैंट था आज से 53 साल पहले वहां पर स्कूल के बच्चों की संख्या 350 थी । वहां बोर्डिग हाउस भी था । वह बिल्डिग आज तक वैसे ही खड़ी हे । उसमें हुक या डेढ़ ब्लाक बनाने की कोशिश की गई है । अब उसमें तीन स्कूल खोल. दिए गए हैं । एक लड़कियों का स्कूल, एक स्कूल लड़कों का जो पहले चल 'रहा था और एक प्राईमरी स्कूल भी वहां खोल दिया गया । मैं अपने वित्त मन्त्री जी से व चीफ मिनिस्टर साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि वे इस बात को ऐग्जामिन करवाएं और यह देखें कि ऐजुकेशन को लेकर हरियाणा के दूसरे जिलों में, दूसरे सब डिविजनज में काम हो रहा हए तो हमको क्यों नजर–अन्दाज किया जा रहा एकु? आया इसमें महकमे का दोष है या हमारे मन्त्री जी का जो हमारी तरफ नजर नहीं करते, उनका दोष है । तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से एक बार फिर रिक्वैस्ट करूंगा कि जगाधरी के अन्दर एक सरकारी हायर सैकन्डरी स्कूल है जो कि आज से 70– 75 साल पहले का बना हुआ है और उस स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है । उसी बिल्डिंग में तीन स्कूल चल रहे हैं । एक लड़कियों का स्कूल, दूसरा 10+2 प्रणाली वाला स्कूल व तीसरा प्राईमरी स्कूल । इस बिल्डिंग की जगह एक नई बिल्डिग दरकार है और नई जगह भी दरकार है क्योंकि यह

स्कूल बहुत ही छोटो सो जगह पर बना हुआ है । जहां पर तीन स्कूल इकट्ठे लगते हों, उसके लिये यह जगह बहुत कम है सरकार इस तरफ ध्यान दे । अब हें डिमांड 8 के बारे में कुछ कहूंगा । स्पीकर साहब, जगाधरी में आज से छ साल पहले मौरचरी की एक बिल्डिग बनी थी । उसका काफी बडा कम्पाउन्ड है । उस बिल्डिग के अन्दर तीन चार कमरे बने हुए हैं । उसके साथ लगती दीवार ट्यूबवैल नं० 3 की है । हस्पताल इससे तीन चार किलोमीटर के फासले पर था अब मौरचरी का प्रवन्ध हस्पताल में ही हो गया है । तथा यह मौरचरी की बिल्डिग अब बिल्कुल खाली पड़ी हुई है । लोग इसकी ईंटें तक उखाड़ कर ले गये हैं । इसके बराबर में ट्यूबवैल नं० 3 है । उसके बारे में मैंने सन् 1982 में वहां की म्युनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा था कि इस मौरचरी की जगह पर सरकार द्वारा धोबी घाट बना दिया जाए क्योंकि इसके साथ ही पानी का अच्छा इन्तजाम है । धोबी जो हैं वे जौहडू पर जाकर कपड़े धोते हैं जिससे बीमारियां फैलने का अन्दैशा है । इस बारे में लोक्ल बौडीज के अधिकारियों को भी मैंने लिखा था और आज डायरैक्टर साहब से भी मैंने बात की है । एक दरखास्त भी दी है । वे कहते हैं कि यह बात पहले हमारे नोटिस में नहीं आई । अब हम इसे एग्जामिन करेंगे । इसलिये अब मैं मुख्य मन्त्री महोदय से भी यह कहूंगा कि चूंकि यह बिल्डिंग बिल्कुल नकारा हो चुकी है, इसके साथ ही ट्यूबवैल नम्बर 3 लगता है । पानी की कोई कभी नहीं है और उस इलाके में धोबी घाट भी नहीं, है इसलिये वहां पर इस बिल्डिंग को कवर

करके धोबी घाट बना दिया जाए तो बडी मेहरबानी होगी । जैसा मैंने पहले कहा धोबी जौहड पर कपड़े धोते है, उससे शहर में गन्दगी फैलती है और गन्दगी से बीमारियां फैलने का डर रहता है । आशा है कि सरकार इस तरफ पूरा–पूरा ध्यान देगी ।

डिमांड नम्बर 10, जो कि मैडिकल और पब्लिक हैल्थ से सम्बन्धित है के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे वहां पर 30 बैडज का हस्पताल है । मुख्य मन्त्री महोदय जी वहां गये थे और उन्होंने 20 हजार लोगों के सामने यह वायदा किया था कि इस हस्पताल को 50 बैड का हस्पताल बना दिया जाएगा । अतरू मेरी रिक्वैस्ट है कि इस बजट के अन्दर ही कुछ न कुछ राशि अवश्य निकाली जातु और मुख्य मन्त्री महोदय अपने वायदे को पूरा करें और वहां पर 30 बैडज की बजाय 50 बैडज का हस्पताल बनाने की छुपा करें ।

इससे अगली बात लेबर एण्ड ऐम्पलायमन्ट की हैं । इसका जिकर मैंने कल भी किया था कि लोगों को जो लोन दिया जाता है यह लोगों की टेम्पोरेरी इमदाद है । जो राशि लोगों को दी जाती है वह जब कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाती है तो लोग भूखे के भूखे ही रह जाते हैं । इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि यदि इस पालिसी को फिर से ऐग्जामिन करवाया जाए और कोई परमानैन्ट साधन लोगों क्रो जुटाया जाए तो बेहतर होगा क्योंकि आजकल वर्ल्ड के अन्दर मन्दे की लहर चल रही है और जगाधरी में तो काफी भूखमरी है । सरकार कोई इस तरह

की स्कीम बनाये जिसके तहत इंडस्ट्रीज कायम की जा सकें ताकि लोगों को पक्के रोजगार का साधन मुहैया हो सके ।

स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर 14 फूड एण्ड सप्लाई से सम्बन्धित है । उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ सुधार की आवश्यकता है । उस सिस्टम में सुधीर होना चाहिये । डिस्ट्रीब्यूशन ,ठीक नहीं है । माल–डिस्ट्रीब्यूशन न हो, फेयर हो । मैं आपको एक मिसाल देता हूं । आप मिट्टी के तेल का वितरण ही देख लीजियेगा उसमें काफी घपला होता है । लोगों के पास जब लकड़ी नहीं होती तो वे बेचारे स्टोव पर ही आधारित रहते हैं । स्टोव जलाने फै लिये उनको मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है लेकिन समय पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो पाता । महीनों–महीनों मिट्टी का तेल नहीं मिलता । मेरे हल्के में एक गांव बम्भोली का डिपो हे । डी ० एफ ० एस ० सी० को ओर डी ० सी० साहिब को भी हमने कह लिया । उन्होंने कहा कि हम इसका इन्तजाम कर रहे हैं । इसलिये मेरी रिक्वैस्ट है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे । इसके साथ–साथ मैं यह कर्हूगा कि फूड एण्ड सप्लाई विभाग कोआप्रेटिव डिर्पाटमैन्ट से जुड़ा हुआ है जिसके अन्डर स्टोर्ज आते हैं । कनफैड भी इसके साथ जुड़ो हुआ है । इसके अन्दर आपने जनरल मैनेजर्ज लगा रखे हैं वे दो–दो अढ़ाई–अढाई हजार रुपया वेतन लेते जै और काम कुछ नहीं करते । वे क्या करते हें? मैं आपका बताता हूं । मैं एक स्टोर में गया और उनसे पूछने लगा

कि चीनी का भाव क्या है वे कहने लगे कि हमें नहीं पता । लेकिन जब आप लोगे तो बता देंगे । मैंने उन से यह भी पूछा कि आपके स्टौक रजिस्टर में कितनी चीनी हे और आपके बैगज का क्या वेट है लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया । आज मैं एम० डी० साहब के नोटिस में भी यह बात लाया हूं । उनकी समझ में बात आ गयी औत उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वे एक सर्कुलर जारी करेंगे कि सभी स्टोरज पर रेट लिस्ट लगी हुई हों कि फलां फलां चीज का क्या रेट है और बोरी का वेट कितना है । इससे करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा । करप्शन कम होगी और –सभी लोगों को एक ही भाव पर सभी चीजें मिलेगी । इसके साथ साथ मेरा एक और सुझाव है कि कोआप्रेटिव स्टोर्ज और कनफैड को एक ही कर दिया जाए तो ठीक रहेगा इससे करप्शन घटेगी । एम० डी० साहब ने भी कहा है कि इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है । इन शब्दों के साथ स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया और सरकार से अन्त में यह रिक्वैस्ट करता हूं कि जो जो बातें मैंने यहां पर कहीं हैं उन पर ध्यानपूर्वक गौर किया जाए ।

श्री बनारसी दास बाल्मीकि (झज्जर, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं डिमांड नम्बर 2, 3 और 8 पर अपने विचार रखूंगा । यह जो बजट हमारे काबिल वित्त मन्त्री महोदय ने बनाकर यहां पर प्रस्तुत किया है, वह वहुत ही सराहनीय और

बढिया बजट है । इसकी जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है । सबसे पहले मैं डिमांड 2 को लूं गा और म्युनिसिपल कमेटी झज्जर के बारे में अपने विचार रखूंगा । सन् 1973 में सर्विरेज सिस्टम का काम वहां पर चालू किया गया था लेकिन वह कम्पलीट नहीं हुआ है । शहर के अन्दर 12 इंच मोटी पाईप लाईन बिछाई गई थी लेकिन वह अभी तक मेन लाईन से नहीं जोड़ी गयी है और सीवरेज का पानी शहर की तरफ वापिस आ रहा है । सरकार इस तरफ ध्यान दे ।

13.00 बजे

इसी तरह से मैं वाटर सप्लाई के बारे में कुछ बातें बताऊंगा । हमारे यहां जिसदिन वाटर सप्लाई की टैंकी बनी थी उस समय हमारे शहर की आबादी कम थी लेकिन अब आबादी बढ़ गई और उस टैक कीं कैपेसिटी कम है । उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अब सरकार ने कुछ पैसा भी दे दिया है । वहां पर बीस किल्ले जमीन ऐक्वायर कर ली है । उसमें 15–20 गरीब आदमियों के घर आते हैं । मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर उसमें से आधा किल्ला जमीन छोडू दी जाए तो गरीब आदमियों के मकान बच सकते हैं । जो पानी की स्कीम है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए । वहां पर दफा 4 का नोटिफिकेशन तो हो गया है लेकिन दफा 6, 7 और 8 के बाकी रहते हैं । आगे गर्मी आने वाली है और गर्मियों में पानी की समस्या और भी बढ़ जाएगी । नहर का पानी महीने में केवल दो

बार आता है । जो वहां पर ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं उनका पानी खारी है । हमारे शहर की आबादी तीस हजार की है । अगर पानी न दिया गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी । हने वैसे मुख्य मन्त्री जी को, मन्त्री जी को और चीफ इंजीनियर को इस बारे में चिट्ठी भी लिख दी है ।

अब मैं सडकों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे हल्के में मन्त्री जी गए थे और इन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया था । वहां के लोगों ने मन्त्री जी को बहुत प्यार दिखाया था । मन्त्री जी को वे बैल' गाड़ी में बिठा कर ले गए थे । इतना जोर का स्वागत किया था जिसकी कोई मिसाल नहीं है । हरियाणा में पहली बार मन्त्री जी बैल गाड़ी में बैठे थे । इसके अलावा दो तीन सड़कें और हैं जैसे रत्नतला से हासावास सड़क है दृ सको भी बहुत जल्द बनाया जाए । अगर यह सड़क बन जातो है तो लोगों को 40 किलोमीटर रास्ते की बचत होगी । इसी तरह से कदाडी से धटोली सड़क है इसके लिए वर्ल्ड बैंक का भी पैसा सरकार के पास है । इसमें 5– 7 ढाणियां भी शामिल हैं यह सड़क भी जल्दी बना दी जाए ।

इसके बाद मैं पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारी पुलिस हरियाणा में बहुत सराहनीय काम कर रही है । आपको पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है लेकिन हमारे यहां ला एंड आर्डर की पोजीशन बहुत बढ़िया है । मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस वालों को बाहर जाने के लिए जो वाउचर दिए जाते हैं

उसकी बजाए उनको रोडवेज की तरह पास दे दिए जाएं । अगर यह संभव न हो तो उनको 10– 15 रुपाए टी ०ए ० भत्ते के दिये जाएं । मैं इस बारे में थोड़ा–सा और कहना चाहूंगा कि झज्जर थाने में 65– 68 गांव आते हैं लेकिन उस थाने में सिर्फ 16 सिपाही हैं, एक एस ० एच ० ओ ० है. दो ए ० एस ० अई ० हैं । वहां पर थाने की बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन सिपाहियों की कमी है । लगर यह कमी पूरी कर दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी । स्पीकर साहब, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 23 जनवरी को मेरे को सूचना मिली कि बनारसी दास एम ० एल ० ए ० के मकान को आग लगाई जाएगी । वहाँ के डी ० एस ० पी ० ने फौरी तौर पर मेरे को कहा था कि अगर आपको पुलिस की जरूरत है तो मैं भेज देता हूं । मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, हम पुलिस वालों से ज्यादा तगड़े हैं । स्पीकर साहब, हम सात भाई हैं और सातों के पास पाँच–पाँच सात–सात लड़के है जो मेरे से भी तगड़े हैं । इस लिए हमने कहा कि हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं है । नेहरा साहब ने मेरा परिवार' देख रखा है । इन्होंने वहां मुझे यह भी कहा था कि मैंने सुना है कि आपके 21 लाठियाँ हैं मैंने उनको कहा कि 21 नहीं 51 लाठियाँ हैं, आप घटा क्यों रहे हो? स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं सभी डिमाँडज का समर्थन करता हूं ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आज आने वाले वर्ष के बजट की

डिमाँडज पर जो चर्चा हुई और नहर और बिजली महकमों के ऊपर जो मुद्दे उठाए गए उस बारे में हें चर्चा करूंगा । मेरे साथी लीला कृष्ण जी ने फतेहाबाद में ट्रांसफारमर्ज की कमी के बारे में कहा । है उनको बताना चाहता हूं कि सितम्बर, 1985 तक फतेहाबाद के पूरे आप्रेशन डिवीजन में एक भी ट्रांस्फारमर ऐसा नहीं था जो डैमेज्ड हो और रिप्लेस न हुआ हो । लेकिन उसके बाद के महीनों में कुछ कमी रही है । उसका कारण यह था कि अगस्त, 1985 में बिजली बोर्ड ने किसी फर्म से ट्रांसफारमर आयल खरीदने की बातचीत की थी । उस तेल के सैम्पल को जब टैस्ट करवाया गया तो वह फेल हो गया । उसके बाद दोबारा बातचीत करके वह तेल कहीं और से खरीदा गया । इस गैप की वजह से काफी बैक लोग इकट्ठा हो गया । उस बैक लोग को दूर करने के लिए पूरे प्रयत्न किए गए हैं । इनकी कांस्टिचुऐंसी के आप्रेशन डिविजन की लेटैस्ट पोजीशन यह है कि 17 ट्राँसफारमर फरवरी के महीने में ऐसे थे जिनकी रिप्लेसमैंट करनी चाहिए थी । उनमें से दस तो रिप्लेस कर दिए हैं और जो बाकी सात हैं वे भी एलोकेट कर दिए गए हैं जोकि बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिए जाएंगे । इसके साथ–साथ जो बैक लोग था उसके लिए बिजली बोर्ड ने नये ट्राँसफारमर खरीदने का फैसला किया है । अब तक 250 के करीब आ चुके हैं और 900 के करीब और आ रहे हैं । अगले साल मार्च के अन्त तक प्रे प्रान्त में कोई भी ट्राँसफारमर ऐसा नहीं होगा जो कि एक हफ्ते के अन्दर रिप्लेस न कर दिशा जाए । जो पोजीशन 1985 के मध्य से पहले थी वैसी हो जाएगी । हमारे सात

ट्रॉसफारमर वर्कशाप हैं और यह नार्मली 500 के करीब ट्रांसफारमरों की रिपेयर कर देते हैं । जनवरी 1986 में 600 ट्रांसफारमर रिपेयर किए गए । मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि इनके आप्रेशन सब डिवीजन में बाकी के सात ट्रांसफारमर भी बहुत जल्दी भेजे जा रहे हैं, इसकी कोई समस्या नहीं होगी । दूसरी बात श्री महेन्द्र प्र ताप जी ने यह कहीं थी कि एम ० आई० टी ० सी० के तथा दूसरे जो टयूबवैल आगमेंटेशन कैनाल्ज पर लगे हैं उन्होंने वहां बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है जिसकी वजह से लोगों के शैंलो ट्यूबवैल्ज का पानी बहुत नीचे चला गया है । इसी प्रकार की शिकायतें हमें प्रांत के दूसरे भागों से भी आई हैं । सरकार ने इस बारे में एक फैसला लिय।' है । मैं जब माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रताप 'सिंह जी के हल्के में गया तो उस समय मैंने इनको और वहां के लोगों को यह बताया था कि जिन नहरों, डिस्ट्रीव्यूटरीज और माइनर्ज पर ऐसे ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं और उनके साथ–साथ लगते हुए जिन किसानों के खेत हैं अगर वे किसान उन ट्यूबवैल्ज से पानी लेना चाहे तो हम उनको उन टयूबवैल्ज से डी० आई० टयुबवैल्ज की तरह पानी देंगे । यह फैसला सरकार ने किसानों की भलाई के लिए किया है । इसके अलावा सरकार और बिजली– बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि पहले डी० आई० टयूवैल्ज से पानी देने का बिजली का जो खर्चा ० पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों से चार्ज किया जाता था वह थोड़ा सा ज्यादा रेट था । उस रेट को लगभग एक साल पहले कम कर दिया ताकि किसानों को ज्यादा खर्चा न पड़े ।

इसके अलावा, मैंने माननीय सदस्य श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के इलाके की प्रोब्लम्ज को देखते हुए एक आफिसर्ज की कमेटी बनाएँ थी । अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई हे । जब भी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हड्डा मीटिंग कर लेंगे और इनके इलाके की प्रोब्लम का समाधान करेंगे । फिर भी यदि कोई प्रोब्लम है जिसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है उसके बारे में हमें माननीय सदस्य बताएं उसका समाधान करेंगे । हुसके अलावा जो बाकी माननीय सदस्य बोले हैं उन में से चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने भी नहरी महकमे और बिजली बोर्ड से सम्बन्धित कुछ समस्याओं के बारे में काफी चर्चा की है । इनके इलाके में पिछले साल 100 स्प्रिकलिंग सैटस लगाने की जो प्रपोजल थी या योजना थी, उस बारे में चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने बताया कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने उस बारे में पिछले साल कोई बात कही थी । बहु बात तो वित्त मन्त्री जी जब बोलेंगे उस समय बता देंगे । मुझे उस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि पिछले साल वित्त मंत्री जी ने उनको क्या कहा था लेकिन मुझे इतना पता है कि यह प्रोजैक्ट सरकार ने सैंक्शन कर दिया है । बाकी जो दूसरी फार्मेलिटीज हैं जैसे कि स्प्रिकलिग सैटस खरीदने हैं, कैसे उनको लगाना है, वे पूरी होने के बाद सरकार बहुत जल्दी इनके इलाके में 100 स्प्रिकलिंग सैंटस लगाने का प्रोग्राम कार्यान्वित करने जा रही है । माननीय सदस्य ने लिफ्ट इरीगेशन स्वामि के बारे में बिजली की कमी की बात कही और यह भी कहा कि भिवानी में थर्मल प्लांट लगाए जाएं । स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को

बताना चाहूंगा कि भिवानी में 210–210 मैगावाट के दो यूनिटस लगाने के लिए बिजली बोर्ड ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट सी० ई० ए० को सबमिट कर दी है । ज्यों ही बाकी दूसरी फार्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी उन दोनों यूनिटस को नैक्सट फाईव ईयर प्लान में लगाने की योजना है ताकि लिफ्ट इरीगेशन स्कीम और दूसरी चीजों के लिए पूरी माला में बिजली उपलब्ध कराई जा सके । इससे पहले बिजली बोर्ड और नहरी महकमा ने भिवानी में लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के लिए जितने भी सब स्टेशन हैं उन सब को औगमैंट कूरने का कार्यक्रम बनाया है । उस कार्यक्रम के लिए दोनों महकमों को ट्राँसफारमर्ज चाहिएं या कोई और चीज चाहिए ऐसी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं । एक बात चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने यह भी कही कि जब नहर का पानी एस्केप के जरिए किसानों की जमीनों में जाता है तो उनकी जमीन में फ्लड सा आ जाता है । ऐसी जगहों पर रिजरवायर बनाए जाएं ताकि उस पानी को उठा कर दोबारा नहर में डाला जा सके । मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रिजरवायर बनाने में सरकार को जो पैसे की दिक्कत आएगी उसको तो वर्कआउट किया जा सकता है लेकिन दिक्कत यह है कि रिजरवायर बनाने के लिए सरकार जिस किसी किसान की जमीन लेना चाहेगी उस किसान की तरफ से बड़ी भारी रिजिस्टैस होगी । लेकिन फिर भी इस बारे में विचार करने की कोशिश करेंगे । अगर किसान इस बात के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार होंगे तो जिन जगहों पर यह दिक्कत है वहां पर रिजरवायर बनाने का प्रयत्न

करैंने । माननीय सदस्य चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने बिजली. बोर्ड के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि ऐसा कोई महकमा या अदायरा नहीं है जिससे बिजली बोर्ड ने लोन न ले रखा हो । स्पीकर साहब, यह तो अच्छी बात है लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है । यह तो पुरानी धारणा है कि कर्जा लेना बुरी बात है । वह धारणा तब बुरी हुआ करती थी जब कोई व्यक्ति कर्जा लेकर उसे वापस नही कर पाता था और उसके बाद उसकी जमीन और दूसरी जायदाद की नीलामी होती थी । आज के युग में कर्जा लेना तरक्की की निशानी है और इस बात की निशानी है कि लोग कर्जा लेकर अपना धन्धा ऐक्सपैंड कर रहे हैं । अगर बिजली बोर्ड ने कर्जा ले लिया है तो वह पब्लिक के काम करने के लिए और अपने काम को ऐक्सपैड करने के लिए लिया है । बिजली बोर्ड ने जो कर्जा लिया है उसको वह समेत ब्याज वापिस भी करता है । बिजली बोर्ड ने कोई ऐसा कर्जा नही ले रखा जो वह वापिस न करे । माननीय सदस्य चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने एक बात यह भी कही कि जिन किसानों ने बैंकों से कर्जा ले कर ट्यूबवैल्ज लगाए हुए हैं लेकिन जिन्हें दो तीन साल से बिजली का कनैक्शन नहीं मिला है और बक की। तरफ से –लोन पर इन्ट्रैस्ट लग रहा है, उनका इंट्रैस्ट माफ कर दिया जाए । इस बारे मे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लगभग एक साल पहले इस बारे में विचार करने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी । ' उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक्शन देने के लिए ऐप्लीकेशन देने का जो सिस्टम

है उसको बदल दिया जाए । नए सिस्टम के अनुसार 50 रुपए फीस और एक सिम्पल एप्लीकेशन देनें से किसान की ट्यूबवैल कनैक्शन के 'लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वही उसका प्रायर्टी नम्बर होगा । जिस समय किसान को कनैक्शन देना होगा उस वक्त बिजली बोर्ड उस किसान को एक महीने का नोटिस देगा कि आप एक या दो महीने के अन्दर ट्यूबवैल लगाने के लिए कर्जा ले लें, कुआँ खोद लें और मीटर खरीद लें या जो कुछ करना चाहें वह कर लें हम आपको एक महीने में कनैक्शन देने के लिए तैयार हैं । पहले किसान कर्जा लेकर ट्यूबवैल लगाने के लिए कुआं, कोठा और दूसरी जरूरियात की चीजें मुकम्मल कर लेता था और फिर उसकी टैस्ट रिपोर्ट के बाद उसको कनैक्शन के लिए प्रायर्टी बनती थी । वह सिस्टम किसानों की सुविधा के लिए बदल दिया गया है । अब किसी भी किसान को ट्यूबवैल लगाने के लिए पहले कर्जा लेने की जरूरत नहीं है और न ही किसी किसान को पहले खर्चा करने की जरूरत है । जिन किसानों ने ट्यूबवैल लगाने के लिए पहले कर्जा ले रखा हे और कनैक्शन के लिए ऐप्लीकेशन दे रखी है उनमें से 7 हजार ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक्शन दे दिया गया है बावजूद इस बात के कि जो नए प्रोजैक्ट हैं उनका खर्चा करना भी बहुत जरूरी है । बिजली बोर्ड ने अपनी सीमा में रहते हुए वह खर्चा किया है । बिजली बोर्ड ने अगले साल लगभग 12 हजार ट्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक्शन देने का टारगैट रखा है । पिछले दिनों बिजली बोर्ड के साथ हमारी बातचीत हुई है और हम यह सोच रहे हैं कि जितने भी रुराने बिजली के कनैक्शन

हैं वे ज्यादातर एस ० टी ० कनैक्शंज हैं । वह सारा बैकलौग क्लीयर कर लिया जाए । जौ भी टयूबवैल्ज के पुराने बिजली के कनैक्शन पैंडिग हैं वे दे दिए जाएं । इस बारे में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है । एक बात चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने नहरों में सिल्टिंग की कही । मैंने इस बारे में पिछले साल एक सवाल के बारे में बताया भी था । स्पीकर साहब, गहरी महकमें ने भिवानी जिले में डी–सिल्टिग के लिए लाखो रुपए खर्च किए हैं । वह रेतीला इलाका हे और जब गर्मियों में आधी आती है तो अच्छी भली नहरों और सड़कों पर मिट्टी भर जाती है । लेकिन फिर भी माननीय सदस्य के इलाके में कोई ऐसी प्रोब्लम होगी उसको देख लेंगे । गहरी महकमे ने इस ' काम के लिए काफी पैसा खर्च किया है और नहरी महकमा इस काम पर निरन्तर पैसे खर्च करता रहता है । उन्होंने एक बात यह भी कही कि पिछले साल ड्रेनेज के काम के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रावधान था लेकिन उसमें से साढ़े ग्यारह करोड रुपए खर्च किए और उस पैसे में से ड्रैनेज के काम के लिए कोई पैसा खर्च नही किया गया । मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले साल बजट में इस काम के लिए एस ०वाई०एल ० नहर के निर्माण के लिए और दूसरे कामों के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रावधान था । खर्चे की सीमा को देखते हुए फाइनैंस डिपार्टमैंट ने अकेले नहरी महकमे पर ही नहीं बल्कि सारे महकमों पर कट लगा कर इस बात का प्रयत्न किया कि काम ठीक ढंग से चल सके । जो 11 करोड़ रुपए था, यह बात ठीक है कि उसमें से 3 करोड़ रुपए मसानी ब्रांच का खर्चा है । इसके अलावा जिन

जमीनों पर ड्रेन्ज बनाई हैं या बनाने जा रहे हैं उन जमीनों का कम्पनसेशन भी देना है और इसमें एस्टेब्लिशबेंट का भी खर्चा शामिल है । मैं यह कहूंगा कि पिछले दो तीन सालों में सरकार ने काफी पैसा खर्च करके हरियाणा के अन्दर बहुत ड्रेन्ज बनाई हैं और उनका कोई मेजर काम बाकी नहीं है । लेकिन फिर भी कहीं पर लिंक ड्रेन की डिमांड है, कहीं पर ब्रांच की डिमांड है । जो इस तरह की डिमांडज हैं उनके लिए ज्यों ज्यों हमारे पास पैसा उपलब्ध होगा हम उन डिमांडज को पूरा करने की कोशिश करेंगे । इसके अलावा, एक बात चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने यह कही कि जुई और सिवानी बाँच की लाइनिंग पूरी नहीं हुई है और इन्होंने एक लैटर का हवाला भी दिया । अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों इस बात का जवाब दिया था कि टोटल जो प्रोजैक्टस हमने तैयार करने थे उनमें से बहुतों पर काम हो चुका है लेकिन लाइनिंग का काम थोड़ा सा बाकी है । हम इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे । इन सारी बातों के साथ–साथ महकमे की जो कमी है या इमकी जों मांगे हैं उन सबका मैं उल्लेख करूंगा । स्पीकर साहब, नहर के महकमें ने काफी सराहनीय काम किए हैं यदि उनकी चर्चा चौधरी सुरेन्द्र सिंह कर देते तो अच्छा होता । इनको पता है कि जून, 1985 के आखिर से लेकर नवम्बर, 1985 के आखिर तक लगातार नहर चलती रही । भिवानी जिले की नहरें लगातार 5 महीने तक बिना रुकावट के चलती रहीं । इतने लम्बे समय तक ये नहरें कभी नहीं चलीं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है । इसी प्रकार से दिसम्बर के

महीने से लेकर अब तक वहां पर 15– 15 दिन के बाद नहर चलती रही है यह भी अप्ने आप में एक रिकार्ड है । इस के साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भि वानी जिले के किसानों की सहूलियत को देखते हुए डब्ल्यू ० जे ० सी ० का जो सर्कल रोहतक पड़ता था उसका एक सर्कल अब भि वानी में बना रहे हैं ताकि किसानों कों रोहतक के एस ० ई ० के पास अपना समय खराब न करना पड़े । तीसरी बात मैं भिवानी जिले के बारे में यह कहना चाहूंगा कि लिस्ट इरीगेशन की जो नहरें हैं या दूसरी जो नहरें हैं या जो और माईनर्ज हैं उन पर तकरीबन 172 दर्जन जगहों पर काम हो रहा है । नहर का महकमा पूरी तरह से जागरूक है । भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल या दूसरे जो जिले हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा पानी देने का प्रयत्न करते हैं । यह काम हम उस सूरत में कर रहे हैं जबकि हमारे पास धन की बहुत कमी है । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) : स्पीकर साहब, हाउस में रोडज की मेन्टेनेंस के बारे में काफी मैम्बर साहेबान ने जिकर किया है । मैं हाउस की जान– कारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्र देश के साथ लगते जो प्र देश राजस्थान, पंजाब और यू ०पी ० हैं उनकी जो सबसे बढ़िया सड़कें हैं उसका मुकाबला हरियाणा की जो सबसे घटिया उड़के हैं उनसे किया जा सकता है । मुझे गुजरात और महाराष्ट्र भी जाने

का मौका मिला है । हमारी स्टेट की सड़कें दूसरी स्टेट की सड़कों की अपेक्षा सारे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी हैं । मैं मैम्बर साहेबान की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1985– 86 में 1– 2– 1988 तक 640 किलोमीटर लम्बाई पर अर्थ वर्क हुआ है, 192 किलोमीटर लम्बाई पर सीलिग हुई है और 130 किलोमीटर लम्बाई पर मैटलिग हुई है । अब इन रोडज को चालू करने के लिए 12 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । वर्ष 1977– 78 के अन्दर 15 हजार किलोमीटर सड़कें थीं जबकि आज के दिन 20 हजार किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं । जिस समय हमारे पास 15 हजार किलोमीटर सड़कें थी उस समय हमें 14– 15 करोड़ रुपए सड्कों की रिपेयर और मेन्टेनैंस के लिए' मिलते थे जबकि आज हमारे पास 20 हजार किलोमीटर लम्बी सड़क होने के बावजूद सड़कों की रिपेयर के लिए सिर्फ साढ़े बारह करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं । मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि सड़कों की मेन्टेनैंस के लिए, जो फाईनैसं कमीशन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, 40 करोड़ रुपया चाहिए तब जाकर हमारी सड़कें रबड़ की तरह नजर आएंगी । जितने साधन हमारे पास हैं उस हिसाब से हम सड़कों की पूरी मेन्टेनैन्स कर रहे हैं । मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा हुआ है कि गांवों की सड़कें खराब नहीं रहनी चाहिएं और उनकी मेस्टेनैंस सही तौर पर की जानी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

वित्त मन्त्री (श्री सागर राम गुप्ता) : स्पीकर साहब, आज भिन्न–भिन्न डिमांडज पर बोलते हुए हमारी पार्टी के सदस्यो ने बहुत ही जागरूकता का सबूत पेश किया । मुझे और सरकार को बहुन ही खुशी है कि हमारे सभी मैम्बर साहेबान अपनी अपनी कांस्टिच्यूऐंसी की सेवा करने के लिए तत्पर है और अपने–अपने हल्को की सेवा करने के लिए पूरे सचेत नजर आते हैं । इन साथियों ने अपनी बात कहने में कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं दिखाई । मैम्बर साहेबान ने यह जानते हुए कि सरकार के फण्डज के रिसोर्सिज बहुत लिमिटड हैं, फिर भी अपने मन की बात कही और मुख्तलिफ मांगें करने में कोई कोताही नहीं की स्पीकर साहब, मुझे मजबूरन एक बात को दोहराना पड़ रहा है । आप भी यही कहेंगे कि एक बात को बार बार न दोहराया जाए लेकिन मैं लाचार हूं । हमारे दूसरी तरफ अपोजीशन भाईयों के बैन्चिज खाली पड़े हैं । इन एम० एल० एज० का यहां पर न होना और अपने हल्के की बात न रखना केवल इस बात को जाहिर करता है कि उनको अपने हल्के की सेवा करने की कोई लगन नहीं है और वे कोई सेवा अपने हल्के की करने की कोशिश में नहीं हैं । वे गलत तरीके से लोगों की आंखों में धूल झौंकने की कोशिश में लगे हुए हैं । स्पीकर साहब, मैं करन प्रादेशिक न्यूज सुन रहा था । उनमें एक हमारे अपोजीशन के लीडर ने कहा कि जो बजट मैंने पिछले दिनों पेश किया है वह ऐन्टी फार्मर है । इससे मुझे उनकी अनपढता और गैरजिम्मेदारी मालूम होती है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि डससे बड़ा गैर–जिम्मेदारी का सबूत और

मिल नहीं सकता । एक लोकदल के लीडर का यह कहना कि यह बजट ऐन्टी फार्मर है एक बेतुकी बात नजर आती है । उनको यह अच्छी तरह पता है कि इस बजट के अन्दर सिंचाई, बिजली और कृषि के लिए पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रावधान है । इसके बावजूद भी ये लोग ऐसी बातें करें तो वे समझ से बाहर की बातें हैं । कल भी मेरे एक कुलीग ने यह कहा था कि वे सच्चाई के सामने आंखे बन्द करते हैं । बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस सहमत हो तो सदन का समय 20 मिनट बढ़ा लिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 20 मिनट बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1986– 87 के बजट पर अनुदानों 'की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, कल मेरे कुलीग श्री सुरजेवाला साहब ने बताया था कि हरियाणा सरकार किसानों की कितनी सहायता कर रही है । मैं आपको याद दिलाऊगा कि जब इन लोगों का पीछे राज आया था तो उस समय गन्ने की क्या दुर्दशा हुई थी । लोगों ने उस समय गन्ने को जलाया था । इसके विपरीत आज हमारे शूगर मिल पूरे समय भी नहीं चल पाते क्योंकि सरकार किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दे रही है

जिसकी वजह से किसान अपना गन्ना इन मिलों को सप्लाई कर रहे है । कल यहां पर बताया गया था कि हरियाणा सरकार एग्री–कल्चरिस्टस के लिए क्या कुछ कर रही है । बिजली के मामले को भी आप देखिए । किसानों को बिजली सिर्फ 18– 19 पैसे प्रति यूनिट देते हैं जबकि वही बिजली इण्डस्ट्रीज को 90–95 पैसे प्रति यूनिट देते हैं । फिर भी यह लोग यह कहें कि यह बजट किसान विरोधी हैं. समझ में नहीं आता । स्पीकर साहब, ऐसा लगता है कि उन को कोई बीमारी लग गई है जिसका आपको कोई न कोई इन्तजाम करना पड़ेगा । ये अपोजिशन के भाई ऐसी बातो? से लोगों को भडकाते हैं जिनका कोई सिर–पैर नहीं होता । लेकिन खैर अप हाउस के अध्यक्ष हैं । यह हमारा सिर दर्द नहीं है । हमारे से ज्यादा आपका है कि आप कैसे सदस्यों को सही बात कहने के लिए प्रभावित करें और ऐनकरेज करें । मैं तो इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

स्पीकर साहब, यहां बहुत ही अच्छे सुझाव दिए गए हैं । यह बात भी ठीक है कि हर एम०एल०ए० साहब की कोशिश है 'कि उसकी कांस्टीचुएंसी बैस्ट सर्वड हो । सरकार कोशिश भी करती है कि हर कांस्टीचुऐंसी की हर जरूरत निश्चित समय के अन्दर प्री की जाए लेकिन जैसा आप जानते हैं, सारे मैम्बरान जानते हैं, रिसोर्सिज लिमि– टिड होते हें लेकिन उनको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता है कि हरियाणा सरकार जितना विकास का काम कर रही है इसका पैरेलल देश में बहुत कम मिलेगा । कुछ मैम्बर

साहेबान ने दो तीन बातों के ऊपर ज्यादा वजन दिया है और मैं समझता हूं कि वह बहुत उचित भी है । एक बात कही गई कि जो वेरियस वैलफेयर स्कीम्ज हैं उनके तहत जब बैंकों से कर्जा लेने की बात आती है तो उसमें कुछ दिक्कत आती है । स्पीकर साहब, हमारे जो निगम हैं, वोर्डज हैं उन्होंने कई स्कीमें चला रखी हैं । उनका मकसद लोगों की गरीबी दूर करने और उनकी भलाई करने से है । उनमें कुछ मार्जिन मनी बैनिफिशरी को गवर्नमैंट देती है, कुछ गवर्नमैंट डिपार्टमैंट देता है और बाकी पैसा बैंक वारने देते हैं । श्री साहब सिंह सैनी और कुछ अन्य सदस्यों ने इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया है । सरकार इस बात को समझती है लेकिन स्पीकर साहब आप जानते हैं कि ये बैंकस पहले सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बड़े बड़े ठेकेदारो? और बड़े बड़े लैंड–लार्डज की सेवा किया करते थे, केवल उनको ही कर्जे दिया करते थे । यह तो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, इंदिरा जी और राजीव जी की मेहरबानी हे जिन्होंने पालिसी चेंज की और इन्हें गरीबों की सेवा में भी लगना पड़ा । गवर्नमैंट बैंकों क्रो परसुएड करके, पालिसीज बना करके कोशिश करती रही है कि जो पैसा है वह देश से गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, देश के नीचे स्तर के लोगों को ऊपर उठाने के लिए खर्च हो । केन्द्रीय सरकार भी और राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि बैंकों वाले अच्छा बिहेव करें और जिन लोगों को वाक्या में पैसे की जरूरत है उसे पूरा करने में सरकार को सहयोग दें । मैं सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों को

विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस बारे में पूरी जानकारी रखती है और हतुलवसा यह कोशिश की जा रही है कि बैंक उन केसिज में जिनको सरकार या निगम रिकोमैंड करते हैं निश्चित तौर पर बैनिफिशरीज को लोन ऐक्सटैंड करे लेकिन स्पीकर साहब आप जानते हैं कई केसिज ऐसे भी होते हैं जिनमें कमी भी होती है । इसलिए सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि ऐसे केसिज को, जिनमें बुनियादी कमी है, रिकोमैन्ड न किया जाए और जिन केसिज को रिकोमैंड किया जाए उन सब को बैक समय पर लोन दे । इस बात –के कदम उठाए जा रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार की तरफ से कि हम निरन्तर यह कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐंटी पावर्टी प्रोग्राम्ज हैं. वैलफेयर प्रोग्राम्ज हैं, उनके तहत लोन के जो केसिज होते हैं उनमें बैंक समय पर बैनिफिशरीज को लोन दे ।

डा० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से एक बहुत जरूरी बात जानना चाहता हूं । जहां तक बैंक के लोन देने का सवाल है, बैंक दो तरह के लोन देते हें । एक लोन वह है जो असैटस के आधार पर दिया जाता है और एक लोन साधन के रूप में दिया जाता है । लेकिन इसमें एक बात देखने की है कि अगर बैंक लोन तो देता जाए और वह रिटर्न हो न तो बैकों के पास पैसा कहां से आएगा? (शोर)

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं डाक्टर साहब की बात को समझ गया । बैक वाले भी वही बात करते हैं जो डाक्टर साहब कर रहे हें । (विध्न)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब की बात अगर अखबार में छप गई तो बाहर लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, सारी फारमैलेटीज पूरी होने के बाद भी बैंक वाले गड़बड़ करते हैं ।

श्री सागर राव गुप्ता : स्पीकर साहब, इस वक्त सारे स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं हैं लेकिन हम बैंक वालों को यह बात समझायेंगे कि नेशनेलाईजेशन से पहले जब वे धनी लोगों को लोन दिया करते थे तो कितने अमांउट की रिकवरी नदी हुआ करती थी और अब उसके मुकाबले में कितनी रिकवरी नहीं होती । मेरे ख्याल में तो आज यह राशि' बहुत कम होगी । पहले इंडस्ट्रियलिस्टस के बहुत दिवालिए निकला करते थे, बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हौ जाया करती थीं । आज अगर हम पांच हजार या सात हजार रुपये का लोन एंटी पावर्टी मैयर्ज के तौर पर किसी बैनिफिशरी को दिलवाने की कोशिश करते है बिना जमानत या बिना असैटस के तो हमारा बेसिक परपज यह होता है कि हम बैनिफिशरी की वैल्थ जैनरेट करने में मदद करें । किसी को हम भैंस के लिए लोन दिलाते हैं, किसी को गाडी के लिए, टैक्सी के लिए लोन दिलाते हैं और किसी को थई व्हीलर के लिए लोन

दिलाते हैं । उद्देश्य यह होता है कि बैंकों से लोन लेकर के गरीब आदमी वैल्थ पैदा करे, अपना गुजारा करे और बैक की किस्त भी वापस दे । होता भी यही है लेकिन आप जानते हैं कि समाज में एक दो पर्सन ऐसे भी होते हैं जो पैसे का दुरुपयोग कर लेते हैं । गरीब आदमी आम तौर पर बनी आदमी से बहुत ज्यादा ईमानदार है । यह मेरा तजुर्बा भी है और सरकार का भी तजुर्बा है ।

डा ० ओम प्रकाश शर्मा : स्पीकर साहब, ये मुझे गलत समझ गए। मैं भी इनकी तरह ही समाजवादी विचारों का आदमी हूं । यह बात नहीं है कि मैं यह नहीं चाहता कि गरीब आदमी को लोन न मिले । गरीब को कर्जा जरूर मिले मगर सवाल यह है कि अगर उनको एक हजार या दो हजार रुपये देने की बजाए साधन दिए जाएंगे तो वे अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे और बैक का पैसा भी लौटा सकेंगे । आप उसे 1500 या 2000 रुपये का लोन दिलवाते हैं लेकिन आज की महंगाई में इतने रुपये क्या मायने रखते हैं । स्पीकर साहब, मैं वित्त मती जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि ऐसे लोन की बजाए क्या उन्हें साधन के रूप में लोन दिलवाने का विश्वास दिलवाएंगे?

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । में डाक्टर साहब की बात को स्पोर्ट करता हूं । मंत्री महोदय हमें इतना जरूर बताएं कि क्या इनके नोटिस में ऐसी शिकायतें हें कि सारी फामैलेटीज पूरी होने के बाद भी बैक वाले लोन रिलीज नहीं

करते? ऐसे केसिज में सरकार लोनीज की कहां तक मदद कर पाती है?

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था– कि पहली बात तो बुनियादी हमें समझ लेनी चाहिए कि बैंक्स केन्द्रीय सरकार के थम्ब के नीचे हैं, राज्य सरकार के थम्ब के नीचे नहीं हैं । हम राज्य सरकार के तौर पर वैक्स को पर– सुएड करते रहते हें और मेरे काल में ऐसा कोई भी केस नहीं होगा जिसमें सारी फार्मैलेटीज पूरी हों, सारी जरूरतें पूरी हों और उसमें बैंक कर्जा न दे ।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पिछली बार भी डिसकशन के दौरान मैंने एक केस हाउस के सामने रखा था और वह ऐडमिटिड फैक्ट भी था । अगर ऐसी बात न हो तो ये सारे मैम्बर्ज यहां ऐसी शिकायत क्यों करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात ठीक है । मैं भी कहूंगा कि आम गरीब आदमी को कर्जा लेने में काफी डिफिकल्टी आती है ।

श्री सागर राम गुप्ता : सीकर साहब, मैं इस बात को डिनाई नही करता कि गरीबों को कर्जा मितने में दिक्कत नहीं है, दिक्कतें है लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि कई दफा हमारी फार्मेलिटीज में कमी रह जाती है । कई दफा ऐसा होता है कि किसी बैंक से 15 केसिज तय किये गये कि इतने लोगों को फायदा पहुंचाया जायेगा लेकिन हमारे अफसर चाहे वे

डिपार्टमैंट के हैं या निगम के हैं वे अपनी इस धारणा से कि जितने ज्यादा लोगों का भला हो अच्छा है, वे ज्यादा केसिज भेज देते हैं । कई हमारे एम०एल०एज० साहेबान के प्रैशर से वे 15 की बजाए 20– 25 केसिज बना कर भेज देते हैं । ऐसा होने पर बैक बालों को चान्स मिल जाता है । उस टाईम बैंक वाले कहते हैं कि हमने 15 केसिज के लिए कहा था लेकिन आप लोगों ने 25 केसिज भेज दिये अब जव बैंक में 25 केसिज चले गये तो जिन लोगों के केसिज हैं उन सब लोगों को भी पता लग गया कि बैक में केसिज चले गये हैं इसलिए वे कोशिश करते ३७ कि हमारा केस हो जाए लेकिन बैंक वालों ने 15 केसिज का ऐग्रीमैंट किया था न कि 25 केसिज का । ऐसी हालत में वाकई ही यह दिक्कत है । चौधरी सुरेन्द्र सिह जी जो कह रहे हैं ऐसी दिक्कतें आती हैं । अगर 15 केसिज कंसीड बैंक ने किये हें तो 15 को निश्चित रूप से देते हैं लेकिन अगर बैंक वालों ने इराके इलावा कोई ऐसी वैसी बात की है तो ये सरकार के नोटिस में लायें हम निश्चित तौर पर उसका इलाज करेंगें ।

श्री ए० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब के नोटिस में एक केस लाना चाहता हुं । एक आदमी को बाकायदा चौक दिया गया । उसने जिससे माल खरीदा था उसको वह पहुंचा दिया क्योंकि माल लेना था । दूसरी तरफ बैक वालों ने गरीब आदमी को चौक दे कर यह उम्मीद लगायी थी कि वह पैसा ले कर उन्हें भी देगा लेकिन उसने नहीं दिया और वे

धोखे से जिससे उसने माल खरीदा था, उससे उस चौक को वापिस ले आये । स्पीकर साहब उस आदमी ने सरकार को चौक नम्बर दिया कि उसे इस नम्बर का चौक दिया गया था लेकिन उसके बाद भी वे धोखे से वापिस ले गये और आज भी वह आदमी डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज सैन्टर और बैंकों के चक्कर काट रहा है । यह इन्स्टांस फरीदाबाद का है ।

श्री सागर राम गुप्ता : स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि इस मामले में बहस की जरुरत नहीं है । मैं इस बात को कसीड करता हूं कि जैसा व्यवहार बैक वालों को करना चाहिए वे वैसा नहीं कर रहे हैं । इसमें कोई दो राय नहीं हैं । राज्य सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि सैन्टर के बैक ठोक से बीहेव करें और सरकार जो ऐन्टी पावर्टी मैयर्ज ले रही है उनको बढ़ावा मिले । हम इस वात की कोशिश कर रहे हैं कि बैक उसमें हरडल न बनें ।

स्पीकर साहब इरीगेशन एण्ड पावर के मामले में मेरें माननीय दोस्त श्री सुरजेवाला ने हाउस की काफी बातों का उत्तर दे दिया है और हमने काफी अच्छा 'प्रावधान बिजली और पानी के लिए बजट में रखा है । एक दो बातें माननीय सदस्यो ने सौशल वैलडेयर के बारे में कहीं कि गरीब आदमियों को मकानों के लिए जो दो हजार रुपये सबसिडी या ग्रान्ट दी जाती है वह बहुत कम है, उसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया जाये । यह बहुत जायज बात नजर आती है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि

सरकार इस मामले में पहले से ही विचार कर रही है । स्पीकर साहब, कुछ बातें लीला कृष्ण जी, नैन साहब और राम सिंह जी ने कही कि सौशल वैल्फेयर स्कीम के तहत जो पैन्शन दी जाती है उसमें काफी फार्मेलिटीज पूरी की जाती है और पैन्शन पहुंचने में भी डिले होती हे । उन्होंने यह भी कहा कि कई केसिज में पैन्शन पहुंचती भी नहीं है । इस मामले से सरकार परिचित है । मैं सदन की सूचना के लिए यह बताना चाहूंगा कि फिलहाल सरकार ने यह फैसला किया है कि छः जिलों में वर्ष 1986– 87 और छः जिलों में उस से अगले साल सुधार करेंगे । इस साल अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, भिवानी और सिरसा में जितने भी पेन्शन के केसिज हुआ करेंगे उनको डायरैक्टोरेट और गवर्नमैंट लैवल तक आने की जरुरत नहीं हुआ करेगी बल्कि जिला स्तर पर ही उनका फसला कर दिया जाया करेगा ताकि लोगों को दिक्कत न हो ।

स्पीकर साहब, ऐनीमल हसबैंडरी की डिमान्ड पर भी कइं बातें कही गई । मैम्बर्ज साहेबान को बिल्कुल जायज वात है कि आज किसान के पास ऐन्टी पावर्टो प्रोग्राम एनमिलज को पालना और बढ़ावा देना है । उनकी यह बात बडी जायज है । आप जानते हैं कि हरियाणा में 6745 गांव हैं । हरियाणा सरकार चाहती है कि हर गांव में अस्पताल, डिस्पैसरी या स्टौकमैन सैन्टर खोल दिया जायें लेकिन मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सन 1983– 84 में कोई पशु संस्थान नहीं खोला गया । उस वक्त कुल 1604 संस्थाए थो । सन 1984– 85 में तीस

संस्थाएं खोली गई और इस साल 31 मार्च 1988 तक चालीस संस्थाए खोलने का प्रावधान किया हुआ है । सन 1986– 87 के बजट में चालीस नयी डिस्पैसरिया खोलेगे, तीस डिंस्पैंसरियां अपग्रेड करेंगे और एक पोलोक्लनिक खोलेंगे । सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जितना हो सके किया जाये । सरकार इस बात को मानती हे कि ऐनीमल को बचाना, पालना करना और उसे बढ़ावा देना बहुत जरूरी है । यह प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी हे ।

स्पीकर साहब बैठने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं क्योंकि उस बारे में जिक्र ए०सी ० चौधरी जी ने किया है और कुछ दूसरे सदस्यों ने भी किया है । उन्होंने कहा कि पोल्यूशन बढता जा रहा है । मैं इस बारे में उनको यही कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार काफी सजग है और पोल्यूशन कन्ट्रोल के लिये काफी मैयर्ज लेने की कोशिश कर रही है । सरकार स्कीमें बनाने की कोशिश कर रही है कि जो बडे बड़े इन्डस्टूयिल एरियाज हैं उन्में कौमन ट्रीटमैंट प्लांटस लगाये जायें । आप जानते है कि म्यूनिसिपल कमेटियों के पास पूरे साधन नही हैं और न ही सरकार के पास हैं । उसके पास भी कंस्ट्रेन्टस है लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकार इस बारे में उचित कदम उठायेगी । इन शब्दों के साथ मैं हाउस से दरखास्त करता हूं कि इन मांगों को पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : साहेबान, अब मैं वेरियस डिमान्डज फार ग्रान्टस को हाउस की वोटिंग के लिये रखता हूं । क्या इनको एक साथ पुट कर दिया जाए?

अवाजें : ठीक है जी ।

Mr. Speaker : All right. Question is—

That a sum not exceeding Rs. 85,82,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 1—Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 20,65,84,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 2—General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 51,36,23,000 for revenue expenditure be granted to the Governor 'to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demend No. 3—Home.

That a sum not exceeding Rs. 10,22,14,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 4—Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 5,52,90,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to d fray charges that will come in the course of payment for the year

1986-87 in respect of charges under Demand No. 5—Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs, 28,76,62,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 6—Finance.

That a sum not exceeding Rs. 37,41,78,000 for revenue expenditure and Rs. 37,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 33,03,32,000 for revenue expenditure and Rs. 32,15,85,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 1,55,84,01,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 9—Education.

That a sum not exceeding Rs. 93,86,92,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 10—Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 6,08,36,000 for

revenue expenditure and Rs. 27,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under demand No. 11—Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 9,79,32,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will' come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 12—Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 26,30,81,000 for revenue expenditure and Rs. 2,17,45,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come .in the course of payment for the year 1986-87 in respect 'or charges under Demand No. 13— Social Welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 2,54,27,000 for revenue expenditure and Rs. 1,70,70,26,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray-charges that will come in the course of payment for 'the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 14- Food and Supplies.

That a sum not exceeding Rs. 90,81,84,000 for revenue expenditure and Rs. 445,67,47,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 15—Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 10,40,73,000 for

revenue expenditure and Rs. 3,54,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect _of charges under Demand No. 16—Industries.

That a sum not exceeding Rs. 45,71,33,000 for revenue expenditure and Rs. 3,95,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to 'defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 17— Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 14,50,39,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 18--Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 2,31,76,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 20,14,75,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 32,81,18,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 7,43,05,000 for revenue expenditure and Rs. 4,92,70,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 22—Co-operation.

That a sum not exceeding Rs. 92,45,50,000 for revenue expenditure and Rs. 12,48,50,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 23- Transport.

That a sum not exceeding Rs. 97,23,000 for revenue expenditure and Rs. 1,05,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charge; that will come in the course of pamyent for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 1,66,97,48,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1986-87 in respect of charges under Demand No. 25—Loans and Advances by state Government.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है ।

13.49 बजे

(तत्पश्चात् सदन शुक्रवार, दिनांक 28–2–86 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए 'स्थगित हुआ) ।